चिंतन

विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के प्रयास

उपभोग और आर्थिक जिम्मेदारी के बीच राष्ट्रहित में संतुलन बनाया जाना बेहद जरूरी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील को केवल राजनीतिक बयान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने, अनावश्यक सोना खरीदने से बचने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने, विदेशी यात्राओं में कटौती और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर देना दरअसल, एक व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। इसका मूल उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार पर संभावित दबाव को कम करना और देश को वैश्विक आर्थिक झटकों के लिए तैयार करना है। यह सच है कि वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक है और स्थिति किसी तत्काल संकट जैसी नहीं है, लेकिन आर्थिक प्रबंधन केवल वर्तमान हालातों को देखकर नहीं किया जाता, बल्कि संभावित जोखिमों को पहले से पहचानकर तैयारी करना ही दूरदृष्टि कहलाता है। मध्य पूर्व में जारी तनाव और हार्मुज जलडमरूमध्य पर मंडराते खतरे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में तेल कीमतों में वृद्धि का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और व्यापार घाटे पर पड़ना तय है। प्रधानमंत्री की अपील का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें जनता की भागीदारी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा गया है। यदि नागरिक सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कार पूलिंग अपनाएं और अनावश्यक ईंधन खर्च कम करें तो इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। इसी प्रकार, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों को बढ़ावा देना भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम हो सकता है। सोने की खरीद को लेकर की गई अपील भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत अपनी लगभग पूरी सोने की जरूरत आयात के माध्यम से पूरी करता है। यही कारण है कि जब सोने का आयात बढ़ता है तो डॉलर की मांग भी बढ़ती है और व्यापार संतुलन प्रभावित होता है। जीटीआरआई द्वारा इस अपील का समर्थन यह दर्शाता है कि यह केवल भावनात्मक राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि आर्थिक यथार्थ से जुड़ा विषय है। यदि एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोना खरीदने से परहेज किया जाए तो इससे विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव काफी हद तक कम हो सकता है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल जनता से संयम की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को भी वैकल्पिक निवेश साधनों को मजबूत और आकर्षक बनाना होगा, ताकि लोग सोने के बजाय वित्तीय निवेश की ओर बढ़ें। साथ ही, आयात आधारित उपभोग कम करने के लिए घरेलू उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाना भी जरूरी है। विपक्ष द्वारा इस अपील को सरकार की विफलता बताना राजनीतिक दृष्टि से स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय चुनौतियों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि संकट के समय सामूहिक अनुशासन और मितव्ययिता ने भारत को मजबूत बनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 'सप्ताह में एक दिन उपवास' का आह्वान हो या कोरोना काल में जनता की भागीदारी देश हर चुनौती में एकजुटता दिखाई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक जिम्मेदारी को केवल सरकार की नहीं, बल्कि नागरिक कर्तव्य के रूप में भी देखा जाए।

अभिजात्य भारद्वाज
पीएम की ताजी अपील

पीएम मोदी की ताजा सलाह दरअसल, फिलहाल भारत का पैसा भारत में रखने के प्रयास व खर्च के आनुपातिक सिद्धांत को अनुशासित करने से ही प्रेरित है। इसकी रोशनी में सरकारों के सोशल वेलफेयर को भी नए सिरे से बुना जा सकता है। कैश स्कीम को काम के बदले पैसे में बदला जा सकता है ताकि देश के विनिर्माण और उत्पादन क्षेत्र में एक नई इबारत लिखी जा सके। इस सलाह के आधार पर सरकारी फिजूलखर्ची, कारों के लंबे काफिले व राजनीतिक रैलियों को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। पीएम की इस नसीहत में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का मंत्र भी है, जिसे केंद्र व राज्य सरकारें अपना भी रही हैं। इसके सार्थक नतीजे भी आ रहे हैं।

अब फिर 'आदतें' बदलने का वक्त

भारत इस समय एक ऐसे आर्थिक मोड़ पर खड़ा है, जहां भीतर ही भीतर कई तरह के दबाव घुमड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा सलाहें-विदेशी यात्राएं टालिए, सोने की खरीद कुछ समय के लिए कम कीजिए और जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाइए-सामान्य नहीं हैं। इसके पीछे अर्थव्यवस्था का गहरा गणित छिपा हुआ है। इन तीनों बातों को ध्यान से देखें, तो एक समान धागा दिखाई देता है-डॉलर। विदेश यात्रा में डॉलर खर्च होता है, सोना आयात करने में डॉलर खर्च होता है और अधिक तेल (ईंधन व खाद्य तेल) खपत का अर्थ है अधिक तेल आयात, यानी फिर डॉलर का खर्च। तो, क्या सरकार वास्तव में भारत से बाहर जा रहे डॉलर के प्रवाह को धीमा करना चाहती है? यहीं से कहानी भारत से निकलकर दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री पट्टी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक पहुंचती है। आज इस क्षेत्र में तनाव केवल युद्ध की खबर नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन पर असर डालने वाला संकट बन चुका है। लगभग 1,550 जहाज इस क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं और करीब 22,500 नाविक फंसे हुए हैं। कुछ दिनों में जहाजों की आवाजाही सामान्य स्तर के केवल 5 फीसदी तक सिमट गई। अब प्रश्न यह है कि यदि दुनिया के तेल का रास्ता धीमा पड़ जाए, तो क्या केवल पेट्रोल महंगा होगा? या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगेगी?

यही वह बिंदु है जहां भारत की चिंता शुरू होती है। भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85 फीसदी आयात करता है। अर्थात, हमारे घरों की रसोई से लेकर ट्रक, ट्रेन, विमान, उद्योग और खेती तक सब कुछ उस तेल पर निर्भर है जो समुद्र के रास्ते बाहर से आता है। अब यदि तेल महंगा होता है या उसकी सप्लाई बाधित होती है, तो भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और जब डॉलर अधिक खर्च होते हैं, तो देश की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ता है। यहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका सामने आती है। कुछ ही सप्ताह पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 728.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। लेकिन कुछ ही समय में यह घटकर लगभग 690.7 बिलियन डॉलर रह गया। यानी लगभग 38 बिलियन डॉलर कम हो गए। इसका अर्थ है कि आरबीआई लगातार डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यदि आरबीआई हस्तक्षेप न करे, तो रुपया और तेजी से गिर सकता है। अब यहां एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है-रुपया गिरने से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? जब रुपया कमजोर होता है, तब आयात महंगे हो जाते हैं। तेल महंगा होता है, परिवहन महंगा होता है, और फिर धीरे-धीरे सब्जी, दूध, दाल, दवाई, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स-हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। यानी विदेशी मुद्रा का संकट अंततः घर की रसोई तक पहुंच जाता है। लेकिन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेल की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा दबाव इस समय भारत की तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल पर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लंबे समय से पूरी तरह नहीं बढ़ाया गया। परिणाम यह हुआ कि कंपनियों को प्रति

लीटर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ अनुमान बताते हैं कि पेट्रोल पर लगभग 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 से 35 रुपए प्रति लीटर तक का दबाव बन रहा है। अब सरकार के सामने विकल्प क्या हैं? पहला-टैक्स कम कर दे। लेकिन, इससे सरकारी आय घटेगी। दूसरा- कंपनियों को सब्सिडी दे। लेकिन, इससे सरकारी खर्च और फिस्कल डेफीसिट बढ़ेगा। तीसरा-पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दे। लेकिन, इससे महंगाई और जनता की नाराजगी दोनों बढ़ेंगी। तो, फिर सरकार क्या करे? शायद यही कारण है कि सीधे कीमतें बढ़ाने के बजाए लोगों के व्यवहार को बदलने की कोशिश हो रही है। यानी कम यात्रा करें, कम ईंधन खर्च करें, कम आयातित सोना खरीदें और डॉलर की बचत करें। इसी बीच एक और संकेत आया है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 14 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं कि भारत कमजोर देश बन गया है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि वैश्विक निवेशक इस समय सुरक्षित जगहों पर पैसा रखना चाहते हैं। जब विदेशी निवेश कम होता है, तब भारत में डॉलर का प्रवाह भी कम होता है। यानी एक तरफ तेल के लिए डॉलर चाहिए और दूसरी तरफ निवेश से डॉलर कम आ रहे हैं। अब यदि इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ें तो एक बड़ा चित्र सामने आता है। यह केवल आर्थिक संकट नहीं, बल्कि भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी का आइना है। वर्षों से भारत विकास कर रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी बाहरी निर्भरता कम नहीं हो रही। ऊर्जा बाहर से, सोना बाहर से, इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से, और कई बार निवेश भी बाहर से। प्रश्न यह है कि यदि दुनिया लंबे समय तक अस्थिर रही, तो क्या केवल विकास दर भारत को सुरक्षित रख पाएगी? शायद यही कारण है कि अब स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, नवकरणीय ऊर्जा, स्थानीय और आयात प्रतिस्थापन (एक ऐसी आर्थिक रणनीति, जिसमें विदेशी वस्तुओं के आयात को कम करके उन्हें घरेलू स्तर पर निर्मित (स्वदेशी) वस्तुओं से बदला जाता है) जैसे शब्द केवल राजनीतिक नारे नहीं रह गए हैं। वे अब आर्थिक आवश्यकता बनते जा रहे हैं।

आज भारत के सामने चुनौती केवल ग्रोथ बनाए रखने की नहीं है, बल्कि ऐसी ग्रोथ बनाने की है जो बाहरी झटकों से टूटे नहीं। क्या भारत आने वाले वर्षों में अपनी तेल निर्भरता कम कर पाएगा? क्या भारतीय परिवार सोने की जगह प्रोडक्टिव फाइनेंशियल असेट्स में निवेश बढ़ाएंगे। इसका मतलब ऐसी वित्तीय संपत्तियों से है, जो समय के साथ आय उत्पन्न करती हैं या उनके मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे आपका धन बढ़ता है। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को इतना मजबूत बनाना होगा कि डॉलर कमाने की क्षमता आयात के दबाव से अधिक हो जाए?

क्योंकि, अंततः अर्थव्यवस्था केवल शेयर बाजार के उत्साह से नहीं चलती। वह चलती है भरोसे से, ऊर्जा से, विदेशी मुद्रा से और उन अदृश्य आर्थिक संतुलनों से जिन्हें आम लोग रोज महसूस नहीं करते। लेकिन, जब हमारे प्रधानमंत्री नागरिकों से विदेशी यात्राएं टालने, सोना कम खरीदने और ईंधन बचाने की अपील कर रहे हों तो समझ लेना चाहिए कि हम एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले वक्त से गुजर रहे हैं। कोविड काल में हमने इससे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तब हमने अपनी आदतें बदली थीं। अब फिर हम सबको अपनी आदतें बदलनी हैं। प्रधानमंत्री ये नसीहत देकर सिर्फ नागरिक बोध ही नहीं जगा रहे हैं बल्कि वे राज्य सरकारों और राजनेताओं से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वे भी आसन्न चुनौतियों के लिए अपने को तैयार करें ताकि 'बरताव' में बदलने का उदाहरण सिर्फ नागरिक तक ही सीमित न रह जाए।

(युवा लेखक अंतरराष्ट्रीय व आर्थिक मामलों के अध्येता हैं)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस

श्वेता गोयल

मानवता की निःस्वार्थ धड़कन और स्वास्थ्य का भविष्य हैं नर्स

जब भी मानवता की सेवा का उल्लेख होता है तो श्वेत परिधान में लिपटी एक ऐसी छवि मानस पटल पर उभरती है, जिसमें करुणा, धैर्य और समर्पण का अनूठा संगम होता है। यह छवि है 'नर्स' की। समाज के स्वास्थ्य ढांचे में नर्सें वह रीढ़ हैं, जिनके बिना चिकित्सा विज्ञान की गगनचुंबी इमारतें ढह सकती हैं। प्रतिवर्ष 12 मई को पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस' के रूप में मनाकर धरती के इन 'फरिश्तों' के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी 'लेडी विद द लैंप' फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा कर नर्सिंग को एक गरिमामय पेशे के रूप में स्थापित किया। वर्ष 2026 में इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज (आईसीएन) ने इस वर्ष के लिए 'हमारी नर्सें। हमारा भविष्य। सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं।' जैसा अत्यंत सार्थक विषय चुना है। यह वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को बचाने और उन्हें संवारने का एक रोडमैप है। नर्सिंग का पेशा केवल दवाइयां देने या घावों पर पट्टी बांधने तक सीमित नहीं है। चिकित्सा जगत में डॉक्टर को यदि मस्तिष्क माना जाए तो नर्सें निश्चित रूप से उस तंत्र की धड़कन हैं। अस्पताल के बंद कमरों में जब एक मरीज अपनी बीमारी से जूझ रहा होता है और उसके परिजन भी साथ नहीं होते, तब एक नर्स ही उसकी मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बनती है। वे मरीजों के स्वास्थ्य संकेतकों की चौबीसों घंटे निगरानी करती हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वे मरीज के टूटते हौसले को अपनी मुस्कान और सांत्वना से जीवित रखती हैं। यही कारण है कि नर्सिंग को विश्वभर में सबसे भरोसेमंद और पवित्र पेशों में शुमार किया जाता है। एक सशक्त नर्स न केवल रोगी की शारीरिक व्याधि को दूर करने में सहायक होती है, बल्कि अपने नैदानिक कौशल और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति को जीवनदान भी देती है। भारत के संदर्भ में देखें तो नर्सों के योगदान को पहचान देने के लिए सरकार ने 1973 में 'राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार' की स्थापना की थी। प्रतिवर्ष 12 मई को देश के महामहिम राष्ट्रपति उन नर्सों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा से समाज में एक मिसाल कायम की है। अब तक सैंकड़ों नर्सिंग कर्मियों को यह सम्मान मिल चुका है, जो इस पेशे की महत्ता को दर्शाता है। हालांकि, पुरस्कारों और सम्मानों से परे नर्सों की वास्तविक स्थिति पर विमर्श करना भी आवश्यक है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी है। विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें अक्सर इस ओर इशारा करती हैं कि विकासशील देशों से नर्सों का पलायन विकसित देशों की ओर हो रहा है। इसके पीछे बेहतर वेतन, बेहतर जीवन स्तर और कार्य की अधिक अनुकूल परिस्थितियां मुख्य कारण हैं। यह पलायन विकासशील देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नर्सों की कमी का सीधा प्रभाव शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था का पैमाना यह नहीं है कि वहां कितने आधुनिक अस्पताल हैं, बल्कि यह है कि वहां प्रति व्यक्ति कितनी प्रशिक्षित नर्सें उपलब्ध हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 1100 की आबादी पर एक नर्स है, जो आदर्श मानकों से काफी पीछे है। नर्सों के सामने आने वाली चुनौतियों में सबसे प्रमुख कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव और उचित सुविधाओं का अभाव है। विशेष रूप से निजी क्षेत्रों और छोटे शहरों में नर्सों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है और इसके बदले उन्हें वह सम्मान या वेतन नहीं मिल पाता, जिसकी वे हकदार हैं। इस वर्ष की थीम 'सशक्त नर्सें' हमें अहसास कराती है कि हमें नर्सों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक थकी हुई और उपेक्षित नर्स कभी भी अपनी पूरी क्षमता से सेवा नहीं दे सकती। इसलिए, उन्हें नेतृत्व के पदों पर बिठाना और उनके लिए शोध एवं प्रशासनिक कार्यों के द्वार खोलना समय की मांग है। नर्सों का कार्य केवल बिस्तर के पास खड़े रहना नहीं है बल्कि वे स्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य और नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वर्ष 1953 में जब डोरोथी सुथरलैंड ने पहली बार इस दिवस का प्रस्ताव रखा था, तब उद्देश्य केवल एक पेशे का जश्न मनाना नहीं था बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना था। आज 2026 में जब हम इस दिवस को मना रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि नर्सें ही हमारे भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी हैं। सशक्त नर्सें ही एक सशक्त और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगी।

(लेखिका शिक्षाविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

चरित्र गठन की व्यायामशाला है संसार

संकलित
दर्शन

संसार न तो अच्छा है, ना बुरा। प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना-अपना संसार बना लेता है। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। अग्नि स्वयं में अच्छी है न बुरी। जब यह हमें गर्म रखती है, तो हम कहते हैं यह कितनी अच्छी है, जब हमारी अंगुली जल जाती है, तो हम इसे दोष देते हैं। यही हाल संसार का है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ यह है कि इसमें अपने सभी प्रयोजन पूर्ण करने की क्षमता है। हमें जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें उसकी सहायता करने के लिए माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। परंतु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर अपने हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो, 'ऐ भिखारी, ले, मैं तुझे यह देता हूं।' तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ होओ कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्य पाने वाला नहीं, देने वाला होता है। भलाई के सभी कार्य हमें शुद्ध और पूर्ण बनाने में सहायता करते हैं। यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और ना मेरी। परंतु फिर भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, परोपकार करते रहना चाहिए। क्योंकि इससे हमारा ही भला है। यही एक साधन है, जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं।

मन की शांति कैसे प्राप्त करें?

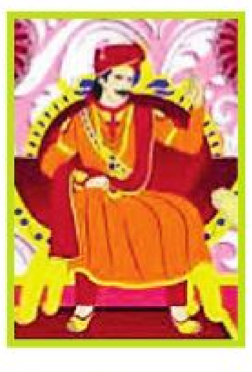

संकलित
प्रेरणा

सेठ अमीरचंद को हर पल कोई न कोई चिंता परेशान किये रहती थी। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। वहां उसे किसी साधु के प्रवचनों की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से प्रभावित होकर अमीरचंद आश्रम के अन्दर गया और बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने पर सभी व्यक्ति अपने अपने घर को चले गये। लेकिन वह वही बैठा रहा। उसे देखकर संत बोले- कहो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है, जो तुम्हें परेशान कर रही है। इस पर अमीरचंद बोला- बाबा, मेरे जीवन में शांति नहीं है। यह सुनकर संत बोले- घबराओ नहीं तुम्हारे मन की सारी अशांति अभी दूर हो जाएगी। संत की बात सुनकर ज्यों ही अमीरचंद ध्यान की मुद्रा में बैठा त्यों ही उसके मन में इधर-उधर की बातें घूमने लगीं और उसका ध्यान उचट गया। सेठ बोला- चलो, जरा आश्रम का एक चक्कर लगाते हैं। इसके बाद वे आश्रम में घूमने लगे। अमीर चंद ने एक सुंदर वृक्ष देखा तथा उसे हाथ से छुआ। हाथ लगाते ही उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया और सेठ। बुरी तरह चिल्लाने लगे। यह देखकर संत वापस अपनी कुटिया में आए। कटे हुए हिस्से पर लेप लगाया। कुछ देर बाद वह सेठ से बोले- तुम्हारे हाथ में जरा-सा कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। सोचो कि जब तम्हारे अन्दर ईर्ष्या, क्रोध व लोभ जैसे बड़े-बड़े कांटे छिपे हैं, तो तुम्हारा मन भला शांत कैसे हो सकता है ? संत की बात से सेठ अमीरचंद को अपनी गलती का अहसास हो गया। वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया।

अंतर्मन

आज की पाती

एक वोट की ताकत

लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि जन-जन की भागीदारी का जीवंत प्रतीक है। इसमें हर नागरिक का वोट समान महत्व रखता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित। हाल ही में तमिलनाडु की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट का परिणाम इस सत्य को फिर से प्रमाणित करता है, जहां मात्र एक वोट के अंतर से चुनाव का परिणाम तय हुआ। टीवीके के उम्मीदवार सीनिवसा सेतुपति आर ने डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केआर पेरियाकरुप्पन को केवल एक वोट से हराया। यह घटना केवल एक चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गहराई और उसकी शक्ति का सशक्त संदेश है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में विश्वास मत के दौरान केवल एक वोट से गिर गई थी। उस एक वोट ने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी।

-आकाश शर्मा, भिवानी

करंट अफेयर

गणित में भारत के योगदान वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन

विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें सहस्राब्दियों के दौरान गणित के क्षेत्र में भारत के ऐतिहासिक और समृद्ध योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का शीर्षक है 'फ्रॉम शून्य टू अनंत (ज़ीरो टू इन्फिनिटी) – भारतीय सभ्यता का गणित में योगदान' जिसमें 2,000 से अधिक वर्षों में गणित के क्षेत्र में भारत के व्यापक योगदान और विचार, अनुप्रयोग तथा विकास की विरासत को उजागर किया जाएगा। जयशंकर दो से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर थे। वह सोमवार को न्यूयॉर्क जाएंगे और इस संक्षिप्त यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि यह प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्र के राजदूतों, राजनयिकों, आगंतुकों और अन्य अधिकारियों को भारत की गणितीय विरासत और योगदान को मानवता की साझा धरोहर के रूप में देखने का अवसर प्रदान करेगी। यह विशेष प्रदर्शनी आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे महान भारतीय विद्वानों से लेकर केरल के खगोलशास्त्र और गणित विद्यालय तक की गौरवशाली परंपरा को सम्मानित करेगी।

ऑफ बीट

बंद शहर से हैं क्रूज, इसलिए तेजी से फैलता है संक्रमण

समुद्री क्रूज यात्राओं को आम तौर पर आरामदायक और विलासितापूर्ण छुट्टियों के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए ये जहाज यह समझने का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं कि संक्रामक बीमारियां किस तरह तेजी से फैल सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, क्रूज जहाज अस्थायी तैरते शहरों की तरह होते हैं, जहां हजारों लोग कई दिन तक एक ही जगह पर रहते, खाते, घूमते और मनोरंजन करते हैं। रेस्तरां, थिएटर, लिफ्ट, केबिन, रसोईघर, जल प्रणाली और बंद सामुदायिक स्थान संक्रमण के प्रसार को आसान बना देते हैं। एक बार कोई संक्रमण जहाज पर पहुंच जाए तो उसे रोकना बेहद कठिन हो सकता है। 'डायमंड प्रिंसेस' जहाज से कोविड 19 का प्रसार इसका सबसे चर्चित उदाहरण माना जाता है। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 'डायमंड प्रिंसेस' जहाज पर 619 यात्री और चालक दल के सदस्य संक्रमित पाए गए थे। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि जहाज की परिस्थितियों ने कोरोना वायरस के प्रसार को तेज किया। हालांकि पृथकवास और अलगाव जैसे कदमों से संक्रमण को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया, लेकिन अध्ययन में यह भी कहा गया कि यदि शुरुआती प्रतिक्रिया और तेज होती तो मामलों की संख्या और कम हो सकती थी।

X ट्रेंड

सनातन संस्कृति का दिव्य प्रतीक

प्रभास पाटन के तट पर सोमनाथ मंदिर श्रद्धा, भक्ति और भारत की सनातन संस्कृति का दिव्य प्रतीक बनकर आज भी अडिग खड़ा है। इस पावन मंदिर ने बर्बर आक्रमणों, विदेशी हमलों और सदियों के चुनौतीपूर्ण कालखंड को पार करते हुए अपनी अमर चेतना को अक्षुण्ण रखा है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप

पेट्रोल-डीजल के उपयोग में संयम, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का प्रधानमंत्री आह्वान भारत को आत्मनिर्भर और ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्र बनाने का स्पष्ट रोडमैप है।

-अमित शाह, गृहमंत्री

युवाओं का भविष्य छीन रहे

एक बार फिर से नीट-यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर खबरें छप रही हैं। भाजपा राज में कई साल से परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार देश के युवाओं से उनका भविष्य छीन रहा है। इस बार भी तकरीबन 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। **-प्रियंका गांधी,** कांग्रेस सांसद

मैं हार नहीं मानूंगी

डब्ल्यूएफआई में सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि मैं इस खेल को छोड़ दूं, लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं करूंगी। उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। आप मुझे 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' कह रहे हैं। क्या आपने अपनी भाषा देखी है? क्या आपको लगता है कि मैं वहां सुरक्षित हूं? **-विनेश फौगाट,** पहलवान

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड,
रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

दैनिक जागरण

समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते

उचित अपील पर आपत्ति

प्रतिकूल परिस्थितियों में बचत का सुझाव देना अथवा किफायत बरतने की अपील करना कभी भी अनावश्यक नहीं हो सकता, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री की इस सलाह पर आपत्ति है कि मौजूदा हालात में लोग पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में संयम बरतें, वर्क फ्राम होम की संस्कृति अपनाएं, विदेश यात्रा से बचें, सोना न खरीदें और देश में ही विवाह समारोह आयोजित करें। आखिर उन संसाधनों के उपयोग में किफायत क्यों नहीं बरती जानी चाहिए, जिनके आयात में विदेशी मुद्रा खर्च होती है? क्या यह किसी से छिपा है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते भारत समेत अधिकांश देशों के आयात बिल बढ़ रहे हैं और इसका बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है? हर किसी को इससे परिचित होना चाहिए कि डालर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से अर्थव्यवस्था को दोहरा नुकसान हो रहा है। यह नुकसान न बढ़ने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संसाधनों के संयमित उपयोग की जो सीख दी, वह सही समय पर दी गई एक उचित सलाह है। जब विपक्ष को इस पर आपत्तियां खड़ी करने के स्थान पर मौके की नजाकत समझनी चाहिए, तब वह ऐसी प्रतीति करा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री लोगों को डरा रहे हैं या फिर अपनी असमर्थता बयान कर रहे हैं।

राहुल गांधी समेत जो विपक्षी नेता प्रधानमंत्री की सही सलाह को उनकी नाकामी बता रहे हैं, उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि गाढ़े वक्त में जनता से संसाधनों के उपयोग में संयम बरतने का आग्रह पहले भी अनेक बार किया जा चुका है? उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि अमेरिका और ईरान में टकराव के चलते होर्मुज समुद्री मार्ग बंद होने से जो ऊर्जा संकट उपजा है, उसके नतीजे में पड़ोसी देशों समेत अधिकांश देशों में पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ाने पड़े हैं। क्या यह उल्लेखनीय नहीं कि भारत में अभी तक ऐसा करने की नौबत नहीं आई है? इसकी भी अनदेखी न की जाए कि कहीं-कहीं गैस की थोड़ी किल्लत अवश्य देखने को मिल रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कहीं कोई बाधा इसके बाद भी देखने को नहीं मिली है कि भारत में पेट्रो उत्पादों की खपत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इससे यही पता चलता है कि तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। यह विचित्र है कि जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराने वाली प्रधानमंत्री की जिस अपील को औद्योगिक जगत सही मान रहा है, उसमें विपक्ष को खामी दिख रही है? इसे उसके दृष्टि दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। विपक्ष को यह आभास होना चाहिए कि ऐसी अपील के केंद्र में आम लोगों के स्थान पर वे सक्षम लोग अधिक होते हैं, जो अपनी आर्थिक संपन्नता के चलते कई बार किफायत की चिंता नहीं करते?

प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों का जो प्रकरण संज्ञान में आया है, वह पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए डिजिटलीकरण का सहारा लेने और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। बाराबंकी जिले के एक ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दो जन्म प्रमाणपत्र जारी हो गए जहां कभी प्रसव हुआ ही नहीं। इसके आधार पर आधार कार्ड में उम्र बदलवा ली गई। साफ है कि यह सरकारी मशीनरी के अंदर बैठे कुछ तत्वों और जनसेवा केंद्रों की मिलीभगत से चल रहा संगठित फर्जीवाड़ा है। यह प्रदेश में पहला फर्जीवाड़ा नहीं है। सबसे पहले रायबरेली जिले के सलोन में फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों को जारी करने का मामला सामने आया था, जहां कुल आबादी से अधिक जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए, तब इस पर सवाल उठे। फर्जी प्रमाणपत्रों को लेकर कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन बड़ी मछलियां अभी तक पकड़ से बाहर हैं। यह केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी नहीं है। इससे सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, पात्रता की जांच प्रक्रिया बेकार हो रही है और वास्तविक जरूरतमंदों का हक मारा जा रहा है। ऐसे प्रकरणों की एकमुश्त जांच करने और उदाहरण बनने योग्य कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा सुधार के अनेक प्रयास निरर्थक ही साबित होंगे। सुशासन तभी सार्थक होगा जब कागजी और डिजिटल दोनों व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार मुक्त हों।

> ऐसे प्रकरणों की एकमुश्त जांच करने और उदाहरण बनने योग्य कार्रवाई की आवश्यकता है

नई रक्षा तकनीक अपनाए भारत

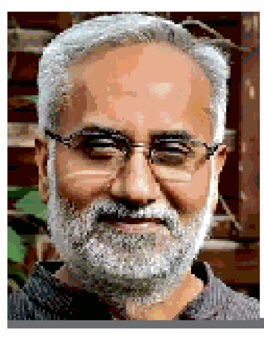

शिवकांत शर्मा

भारत के लिए स्वायत्त रोबोट और ड्रोन तकनीक में बढ़त पड़ोसी देशों में आतंकी अड्डों से निपटने में भी मददगार बनेगी

अवधेश राजपूत

रूस यूक्रेन से दस गुना शक्तिशाली परमाणु महाशक्ति है, लेकिन चार साल लंबी लड़ाई के बावजूद यूक्रेन को नहीं झुका पाया है। अमेरिका ईरान से सौ गुना शक्तिशाली परमाणु महाशक्ति है, मगर दो महीनों के विनाशकारी हमलों के बावजूद ईरान को नहीं झुका पाया है। कारण शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गत माह के उस दावे में छिपा है कि उनकी सेना के स्वायत्त रूप से काम करने वाले रोबोट वाहनों और ड्रोन प्रणाली ने एक रूसी मोर्चे पर कब्जा कर लिया और तीन रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया। लगता है दुनिया फिर उस युग में प्रवेश कर रही है, जहां सेनाओं की जगह उनके शस्त्रास्त्रों का आपस में संग्राम हुआ करेगा। यूक्रेन इस समय रूसी सैनिकों, वाहनों और ठिकानों को नष्ट करने, युद्ध में फंसे सैनिकों को रसद पहुंचाने और घायल सैनिकों को निकालने के लिए स्वायत्त रूप से काम करने वाली रोबोट प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। चार साल से चल रही लड़ाई में यूक्रेन के लगभग डेढ़ लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, इसलिए वह रूस की सीमा पर 30 से 40 किमी चौड़ी पट्टी को ऐसे क्षेत्र में बदलना चाहता है, जहां स्वायत्त रोबोट और ड्रोन दुश्मन को देखते ही मार दें। पिछले साल जून में उसने सौ से अधिक ड्रोन के जरिये रूस में चार हजार किमी भीतर तक हवाई ठिकानों के एक तिहाई विमानों को नष्ट कर दिया था। ऐसे शस्त्रास्त्रों के विकास में रूस भी पीछे नहीं है।

यूक्रेन ने पिछले साल रूस का एक ऐसा ड्रोन पकड़ा था जो एआइ से चलने के कारण दुश्मन के ठिकानों की खुद टोह लगाकर नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसे सामान्य ड्रोन की तरह संकेत लेने और भेजने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे जाम भी नहीं किया जा सकता था। रूस के रक्षा उद्योग के बारे में यह धारणा रही है कि वह केंद्रीय नियंत्रण और सेना की संस्थागत परंपराओं की जकड़न में बंधा है, जहां कोई व्यापक परिवर्तन बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि यूक्रेन युद्ध की चोट ने उसके पारंपरिक सोच को बदल दिया है। इस क्रम में रूस ने शुरुआत ईरान के शाहीन ड्रोन से की थी, जिनमें परिष्कार करते हुए वह स्वायत्त रूप से काम कर सकने वाले ड्रोनों तक पहुंचा है। उसने एआइ और स्वायत्त शस्त्रास्त्रों के विकास के लिए अपने रक्षा अनुसंधान क्षेत्र को पूरी तरह खोल दिया है। निजी क्षेत्र के स्टार्टअप, प्रयोगशालाएं और यहां तक कि कुछ स्कूल भी ड्रोन और रक्षा उपकरणों में एआइ से स्वायत्त क्षमता के विकास में लगे हैं।

युद्ध के मैदान से हर रोज हजारों वीडियो आते हैं, जिनका आकलन कर उनकी जानकारी को ड्रोन और स्वायत्त वाहनों में भरा जाता है। स्वायत्त ड्रोनों और रोबोट वाहनों को मानवाधिकार कार्यकर्ता 21वीं सदी का परमाणु बम बताते हैं। इन स्वायत्त प्रणालियों के प्रयोग से जहां सैनिकों की जान का जोखिम कम होगा, वहीं आम नागरिकों की जान का जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि एआइ से काम कर रहा ड्रोन सैनिक और नागरिक में कैसे भेद कर पाएगा? लड़ रहे सैनिक और समर्पण कर रहे सैनिक में कैसे भेद कर पाएगा? रूस तो यह सब चार साल से चल रही लड़ाई जीतने के लिए बना रहा है, क्योंकि उसे यूक्रेन के नागरिकों को होने वाले नुकसान की परवाह नहीं है, लेकिन यूरोप, अमेरिका और भारत जैसे देशों को स्वायत्त प्रणालियों के जोखिम पर भी विचार करना होगा। इसके बावजूद अमेरिका पूरे जोश के साथ स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास में जुटा है। चूंकि उसने ईरान के साथ हुए युद्ध में ड्रोन की मारक क्षमता देख ली है, इसीलिए युद्ध मंत्री पीटर हेगसेथ का कहना है कि अमेरिका को एआइ की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति बनना है। पेंटागन ने एआइ विकास में अग्रणी गूगल, ओपनएआइ, एमेजान, माइक्रोसाफ्ट, स्पेसएक्स, ओरेकल और एनवीडिया जैसी कंपनियों के साथ कदमताल शुरू की है। ड्रोन विकास के लिए उसे यूक्रेन से ही मदद लेनी होगी, जो इस समय ड्रोन विकास के मोर्चे पर बहुत ऊंचे पायदान पर है। हाल में उसने मार्शियन नाम के स्वायत्त ड्रोन का परीक्षण शुरू किया है, जो 300 किमी प्रति घंटे की गति से उड़ता है और ड्रोन टोही रडारों की पकड़ में भी नहीं आता।

भारत का रक्षा तंत्र भी शस्त्रास्त्र खरीद या विकास की संस्थागत परंपराओं से बंधा है। नए शस्त्रास्त्रों का परीक्षण कर सेना के सभी अंगों से सामंजस्य बिठाने में समय लगता है, जबकि स्वायत्त रोबोट और ड्रोन प्रणालियों का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि कुछ महीनों के भीतर ही उनकी काट तैयार हो जाती है और उनके नए परिष्कृत रूपों का विकास करना पड़ता है। इसलिए इस होड़ में आगे बने रहने के लिए रक्षा कंपनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र और स्टार्टअप की प्रतिभाओं का सहयोग लेना भी जरूरी है। उनके सहयोग से ही चीन रोबोट मानवों के विकास में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। पिछले महीने बीजिंग में हुई मानव और रोबोट धावकों की 21 किमी लंबी मैराथन दौड़ में चीनी मोबाइल कंपनी के रोबोट मानव लाइटनिंग ने विश्व रिकार्ड सात मिनट से तोड़ दिया।

भारत के लिए स्वायत्त रोबोट और ड्रोन तकनीक में बढ़त पड़ोसी देशों में आतंकवाद के अड्डों से निपटने में भी मददगार बनेगी। जरूरत पड़ने पर स्वायत्त रोबोट और ड्रोन प्रणाली की मदद से करोड़ों डालर के लड़ाकू विमानों और प्रशिक्षित पायलटों को जोखिम में डाले बिना आपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि इस तरह के स्वायत्त ड्रोन और रोबोट आतंकी संगठनों के हाथ पड़ जाएं तो ये गंभीर समस्या भी बन सकते हैं। इसलिए इनसे बचाव के लिए तैयार हो रहे अस्त्रों के विकास पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। इजरायल, ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसी लेजर गन का विकास किया है जो एक किमी की दूरी से ही ड्रोन को मार गिरा सकती हैं और वे पेट्रियट और एस-400 जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों की तुलना में बेहद सस्ती हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि एक तो ये कोहरे और बरसात में उतनी कारगर नहीं रहतीं, दूसरे निशाना चूकने या छिटकने पर विमानों और उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ड्रोन रक्षा पर अभी और बहुत काम होना बाकी है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

कृषि को संकट से बचाने की चुनौती

डा. जयंतीलाल भंडारी

पश्चिम एशिया में छाए संकट और कमजोर मानसून की आशंका ने खेती-किसानी और अर्थव्यवस्था की चिंता बढ़ा दी है

इन्वेस्टमेंट इन्फोर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आइसीआरए) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर मानसून, अल नीनो के प्रभाव और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस वर्ष कमजोर मानसून से भारत में कृषि की पैदावार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने और विकास दर में कमी की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने भी अल नीनो के कारण इस साल सामान्य से कम मानसून का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान पिछले 26 वर्षों में मानसून का सबसे कम शुरुआती अनुमान है। इससे देश में कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट में भी इसी तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 75 प्रतिशत वर्षा पर आधारित मानसून (जून से सितंबर) में 94 प्रतिशत वर्षा हो सकती है।

आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम मानसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, वितरण और फैलाव लगभग समान रहा, तब खरीफ के उत्पादन में अधिक कमी नहीं हुई, किंतु गैर-सिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए जोखिम पैदा हुआ। दलहन और तिलहन का कम उत्पादन खाद्य महंगाई पर असर डाल सकता है। एक ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया संघर्ष से महंगे उर्वरक, महंगे तेल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से खेती की लागत बढ़ी है, तब कमजोर मानसून से न केवल किसानों और कृषि पर, वरन आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हो सकता है। इससे पेयजल समस्या की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं।

गत वर्ष के मानसून सीजन में अच्छी बारिश के कारण जलाशयों में पर्याप्त पानी है, लेकिन अब इस साल अल नीनो के खतरे और कमजोर मानसून की आशंका से जलाशय के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है,

आवश्यक है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। फाइल

क्योंकि पानी का स्टाक जल्दी खत्म हो सकता है। नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 प्रतिशत ही सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर है। यह परिदृश्य देश में अभी सहज स्थिति वाले कृषि क्षेत्र के समक्ष एक नई चुनौती बनकर दिखाई दे रहा है। इस वर्ष सामान्य से कम मानसून और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए कई बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। अभी से ही जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए।

देश के विभिन्न हिस्सों में विविधतापूर्ण जलवायु है। देश कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों के मामले में समृद्ध है। अतः भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश में अभी भी अनाज, दलहन तथा तिलहन का उत्पादन मौसम पर निर्भर होता है। ऐसे में क्षेत्रवार और फसलवार स्थितियों का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई व्यवस्था की नई नीति तैयार करनी चाहिए। हमें कमजोर मानसून के पूर्वानुमान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खाद्य भंडारण मजबूत करना चाहिए। वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 17.41 करोड़ टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 17.45 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में एक बड़ी छलांग है। पिछले वर्ष खरीफ उत्पादन 16.94 करोड़ टन था, जिसमें इस बार लगभग 2.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रबी उत्पादन पिछले वर्ष 16.91 करोड़ टन था, जिसमें इस बार 3.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत में अनाज का यह रिकार्ड उत्पादन एक सुरक्षा कवच की तरह है। 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था खाद्यान्न ताकत के कारण ही बहुत कम प्रभावित हुई थी। कोविड से जंग में देश के खाद्यान्न भंडार देश के लिए बड़ा सहारा बन गए थे।

पिछले महीने अधिसूचित किए गए 50 लाख टन गेहूं के निर्यात आदेशों की पूर्ति अवश्य की जाए, लेकिन आगामी निर्यात आदेशों के लिए सजगता रखी जाए। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि देश ने वर्ष 2021-22 में 70 लाख टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया था, लेकिन वर्ष 2024 में गेहूं का आयात करना पड़ा था। ऐसे में अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में वर्ष 2028 तक सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कृषि में भी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। भंडारण अभियान और कृषि-वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे किसानों और कृषि क्षेत्र को मुश्किलों से बचाते हुए आम आदमी एवं अर्थव्यवस्था की चिंताएं भी कम की जा सकती हैं।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वास्तविक स्वतंत्रता

मनुष्य सदैव स्वतंत्रता की खोज में रहा है। वह बंधनों से मुक्त होकर अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है। प्रायः लोग स्वतंत्रता का अर्थ यह समझ लेते हैं कि मन जो चाहे वही किया जाए, किसी नियम या अनुशासन को स्वीकार न किया जाए। किंतु यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मन की दासता है। मन अत्यंत चंचल होता है। वह कभी इच्छाओं, कभी भय, कभी मोह और कभी अहंकार के प्रभाव में निर्णय लेता है। यदि मनुष्य केवल मन के पीछे चलता रहे, तो उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपने विवेक को जागृत कर मन को नियंत्रित करना सीखता है। यही आत्मबोध की शुरुआत है।

आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, तब उसे अनुभव होता है कि बाहरी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है। बाहरी परिस्थितियां कभी भी पूर्णतः हमारे अनुकूल नहीं हो सकतीं, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाता है। वास्तविक स्वतंत्रता अनुशासन, धैर्य और आत्मसंयम से जन्म लेती है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसी दिशा में स्थिर रहने की शक्ति देती है। ईश्वर के प्रति समर्पण, विचारों की पवित्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं।

अंततः स्वतंत्रता का अर्थ मन की प्रत्येक इच्छा को पूरा करना नहीं, बल्कि मन को सत्य, विवेक और आत्मिक चेतना के अनुरूप ढालना है। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तभी उसका जीवन शांति, संतुलन और आत्मिक आनंद से भर उठता है।

आदित्य नारायण अवस्थी

खत्म होती सहज संवाद की संस्कृति

डा. मोनिका शर्मा

> तकनीक के जरिये दुनियाभर से जुड़े होने के बावजूद भावनात्मक अकेलापन आज एक कटु हकीकत है

मन के बिगड़ते मौसम की बात हो या आक्रोश में अपराध कर बैठने की। करीबी संबंधों में आई दूरी हो या अलगाव चुन लेने की मजबूरी। बहुत-सी पीड़ादायी स्थितियों के लिए संवाद की कमी ही जिम्मेदार है। समाज एवं परिवार में पसारती चुप्पी महामारी बन रही है। सहज बोलचाल की कमी अवसाद और अकेलेपन का धरातल तैयार कर रही है। आखिर एक दूजे के मन की सुनने वाला समाज इतना कैसे बदल गया? कहां गए वे लोग जो अपरिचितों से भी हालचाल पूछ लिया करते थे।

हाल में तयशुदा फीस लेकर लोगों का दुख सुनने से जुड़ा मुंबई के युवक का वीडियो वायरल हुआ। यह वाकया क्या सचमुच इतना ही सहज है? ज्ञात हो कि मुंबई के जुहू बीच पर एक युवक इन दिनों पैसे लेकर लोगों के दुख-दर्द सुन रहा है। उसने इसका रेट कार्ड भी तय किया है। वह युवा मामूली परेशानी के लिए 250 रुपये, बड़ी समस्या के लिए 500 रुपये, साथ बैठकर रोने यानी मन हल्का करने के लिए 1000 रुपये की फीस ले रहा है। देखा जाए तो यह सीधे-सीधे किसी को भावनात्मक सहायता देने के मानवीय भाव को एक व्यवसाय बना देने जैसा है। हालांकि यह भी कटु सच है कि उसके द्वारा दी जा रहीं सेवाएं अकेलेपन के परिवेश में इंसानों के सचमुच अकेले पड़ जाने के हालात को भी दर्शाती हैं। यूं तो पेशेवर डिग्रीधारी लोग उलझन के शिकार इंसान के मन की सुनने और सलाह देने की सेवाएं देते ही हैं, पर उस युवक का यह कदम समग्र समाज के समक्ष एक बड़ा प्रश्न उठाता है।

निस्संदेह, यह पहल अनोखी भी और आश्चर्यजनक भी। बावजूद इसके इसे केवल कौतुक भरा बर्ताव भर नहीं माना जा सकता। इसे बहुत संवेदनशीलता से देखा-समझा जाना आवश्यक है, क्योंकि आत्म-केंद्रित होते समाज में अकेले पड़ते लोगों की पीड़ा और परेशानियों से जुड़ा कितना कुछ अनसुना रह जाता है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी के भीतर संवेदनाओं के मोर्चे पर बहुत कुछ दबा-सा ही रहता है। समस्याएं भले अलग हों, पर न सुने जाने की टीस तो हर किसी के मन में है।

तकनीक के जरिये दुनियाभर से जुड़े होने के बावजूद भावनात्मक अकेलापन आज एक कटु हकीकत है। शोध बताते हैं कि हमारे देश के शहरी इलाकों में 43 प्रतिशत लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। उनके पास अपनी बात साझा करने का कोई कोना नहीं। दुख-तकलीफ को भीतर ही दबाकर जीने की स्थितियां मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी चिंतनीय हैं। साथ ही समाज में आते बिखराव की ओर भी इशारा करती हैं। समझना जरूरी है कि मोल चुकाकर समय लिया जा सकता है, पर अपनापन नहीं। मन-मस्तिष्क में उमड़ती बातें तो कही जा सकती हैं, पर समझने और उचित सलाह मिलने की आशा नहीं की जा सकती।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

उत्तरदायी नेतृत्व भी जरूरी

डा. ऋतु सारस्वत का आलेख 'भारतीय राजनीति का बदलता चेहरा' बंगाल विधानसभा चुनाव के उदाहरणों के माध्यम से भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी बदलती भूमिका को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अब महिलाएं केवल मतदान तक सीमित नहीं, बल्कि वे राजनीतिक विमर्श और नेतृत्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। आज शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण महिलाएं अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक सजग हुई हैं। पंचायतों से लेकर संसद तक उनकी भागीदारी निरंतर बढ़ रही है, जो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। बालिका शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं ने महिलाओं में आत्मविश्वास और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। महिला आरक्षण से जुड़ा वर्तमान विमर्श भी इसी परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी है। राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति अब अपवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आवश्यकता बनती जा रही है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि राजनीति में केवल महिलाओं की संख्या बढ़ जाना ही पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, से नैतिकता, संवेदनशीलता और जनउत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। कुछ अवसरों पर राजनीतिक कटुता, व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा सत्ता-केंद्रित व्यवहार के उदाहरण ऐसे भी सामने आते हैं, जो लोकतांत्रिक आदर्शों को कमजोर करते हैं और महिला नेतृत्व से जुड़ी अपेक्षाओं पर प्रश्नचिह्न खड़े करते हैं। अतः आवश्यकता केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने की नहीं, बल्कि ऐसे उत्तरदायी और मूल्यनिष्ठ नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की है, जो समाज में विश्वास और प्रेरणा दोनों उत्पन्न कर सके।

pramodkgoelpnb2014@gmail.com

मितव्ययिता का संकल्प

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आया है। इससे होर्मुज जलमार्ग बाधित होने से तेल और गैस की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। इससे इसकी किल्लत बढ़ने के साथ कीमत भी बढ़ गई है। वैश्विक ऊर्जा इस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेट्रोल-डीजल और गैस के उपयोग में संयम बरतने, विदेश यात्राओं और अनावश्यक खर्चों से बचने का आह्वान समय की आवश्यकता है। देशवासी निश्चित रूप से इस संकल्प में सहभागी बनने को तैयार हैं, क्योंकि भारत ने हर संकट में सामूहिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। किंतु केवल आम नागरिकों से मितव्ययिता की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं होगा। यदि केंद्र और राज्य सरकारें तथा पूरा शासकीय तंत्र भी इसी भावना को व्यवहार में उतारे, तब यह अभियान अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बन सकेगा। आज भी मंत्रियों और उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधियों के भारी-भरकम काफिले, छोटी-छोटी दूरियों के लिए हेलिकाप्टर और चार्टर्ड विमानों का उपयोग, सरकारी आयोजनों पर अनावश्यक व्यय तथा सुविधाओं की निरंतर बढ़ती संस्कृति जनता के मन में प्रश्न खड़े करती है। जब आम नागरिक से ईंधन बचाने और खर्च घटाने की अपील की जा रही हो, तब सत्ता और प्रशासन को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। लोकतंत्र में नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रभाव उसके आचरण से पड़ता है। सबसे अधिक पुनर्विचार की आवश्यकता जनप्रतिनिधियों को दी जाने वाली आजीवन पेंशन और विभिन्न प्रकार के भत्तों पर है। एक कार्यकाल पूरा होते ही पेंशन की पात्रता, जबकि देश का बड़ा वर्ग न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा से भी वंचित हो, आर्थिक न्याय की भावना के अनुकूल नहीं कही जा सकती। संकट के समय इन सुविधाओं में कटौती या अस्थायी रोक से सरकारें जनता के बीच सकारात्मक संदेश दे सकती हैं। ऊर्जा और आर्थिक संकट में यदि नागरिकों के साथ-साथ सरकारें, जनप्रतिनिधि भी मितव्ययिता का पालन करें, तो यह त्याग एकतरफा न होकर राष्ट्रीय संकल्प बन जाएगा।

खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली-न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 उत्पादों की हो रही पहचान

नई दिल्ली: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया का कहना है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ तहत सरकार उद्योग के साथ मिलकर 100 उत्पादों की पहचान कर रही है। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका उत्पादन या तो भारत में होता ही नहीं है या फिर अपर्याप्त मात्रा में होता है। भाटिया ने कहा कि कुछ "अनोखे और दिलचस्प" उत्पादों का एक सेट पहले ही पहचान लिया गया है। (प्रेट्र)

भारतीय उद्योग को मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना चाहिए। यह समझौते व्यापार और निवेश, दोनों के लिए विशाल अवसर प्रदान करते हैं। – **राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव**

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलो ग्राम	डालर	क्रूड प्रति बैरल
76,015.28 ▼ 1,312.91	23,815.85 ▼ 360.30	₹ 1,55,300 ▼ ₹ 600	₹ 2,65,000 ▲ ₹ 3,700	₹ 95.28 ▲ ₹ 0.790	$ 103.5

पीएम की अपील से निवेशक चिंतित, बाजार लुढ़के

अमेरिका-ईरान के शांति समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहने और क्रूड में आई तेजी का भी दिखा दबाव

मुंबई, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बचत के उपायों की नसीहत शेयर बाजार को रास नहीं आई और सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1,313 अंक लुढ़क गया जबकि एनएसई निफ्टी 24,000 अंक के नीचे आ गया। अमेरिका और ईरान के शांति समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहने के बाद कच्चे तेल के दाम में आई तेजी ने भी बाजार को नीचे धकेलने में योगदान दिया।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,312.91 अंक यानी 1.70 प्रतिशत टूटकर 76,015.28 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,370.79 अंक तक लुढ़क गया था। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 360.30 अंक यानी 1.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,815.85 अंक पर बंद हुआ। पिछले गुरुवार से शुरू तीन कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स लगभग 1,950 अंक यानी 2.5 प्रतिशत टूटा है जबकि निफ्टी 515 अंक यानी दो प्रतिशत से अधिक के नुकसान में रहा। विश्लेषकों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मितव्ययिता की अपील ने विदेशी मुद्रा भंडार, ईंधन की कीमतों और उपभोग के दृष्टिकोण को लेकर निवेशकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.23 प्रतिशत बढ़कर 103.5 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 516.33 अंक टूटकर 77,328.19 पर, जबकि निफ्टी 150.50 अंक की गिरावट के साथ 24,176.15 अंक पर रहा था। एशियाई मार्केट में, जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 इंडेक्स नीचे बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क कास्पी और शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स ऊपर बंद हुआ।

1313 अंक टूटकर 76,015 पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स

1950 अंक टूटा है सेंसेक्स पिछले तीन कारोबारी दिनों में

360 अंक की गिरावट के साथ 23,815 पर बंद हुआ एनएसई का निफ्टी

515 अंक से अधिक के नुकसान में रहा है निफ्टी गुरुवार से अब तक

टूर-ट्रेवल और विमानन क्षेत्र के शेयर गिरे

पीएम की अपील के बीच सोमवार को टूर और ट्रेवल से जुड़ी सर्विस देने वाली कंपनियों और विमानन कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई पर यात्रा आनलाइन का स्टाक 5.41 प्रतिशत, थामस कुक (इंडिया) लिमिटेड का 3.88 प्रतिशत, ईज ट्रिप प्लानर्स का शेयर 3.27 प्रतिशत गिरा। इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोबल एविएशन के शेयर 4.94 प्रतिशत और स्पाइसजेट के 4.72 प्रतिशत गिरे।

ज्वेलरी से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में दिखी भारी बिकवाली

पीएम की सोना नहीं खरीदने की अपील का सबसे ज्यादा नकारात्मक असर ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों पर दिखाई दिया और इनके शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स में टाइटन के शेयर में सबसे ज्यादा सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इंट्रा-डे में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर 10 प्रतिशत गिरकर 382.20 रुपये पर आ गए, जबकि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का शेयर 8.32 प्रतिशत गिरकर 668.05 रुपये पर आ गया। स्काई गोल्ड और सेंको गोल्ड इंट्रा-डे में 12 प्रतिशत से ज्यादा गिरे, फिर छह प्रतिशत से ज्यादा नीचे बंद हुए। सेंको गोल्ड के शेयर 7.8 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर वैश्विक अनिश्चितता ने पहले ही बाजार की धारणा को कमजोर कर दिया था। अब प्रधानमंत्री की अपील ने विदेशी मुद्रा भंडार, ईंधन की लागत और उपभोग के दृष्टिकोण को लेकर निवेशकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। **-हरिप्रसाद के. संस्थापक,** लाइवलांग वेल्थ

ईवी कंपनियों के शेयर चढ़े

पीएम की अपील से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के शेयर बढ़कर बंद हुए। एथन एनर्जी के शेयर 6.02 प्रतिशत, जेबीएम आटो 4.75 प्रतिशत, ओला इलेक्ट्रिक 2.47% और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 2.16 प्रतिशत चढ़े।

रुपया 79 पैसे टूटकर नए निचले स्तर पर पहुंचा

मुंबई, प्रेट्र: रुपया सोमवार को 79 पैसे टूटकर डालर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर 95.28 पर आ गया। शांति प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खारिज करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डालर के मजबूत रुख और विदेशी पूंजी की भारी निकासी ने रुपये पर और दबाव डाला।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डालर के मुकाबले 94.97 पर खुला। दिन में 94.87 से 95.34 प्रति डालर के बीच कारोबार करता रहा। अंत में यह अबतक के सबसे निचले स्तर 95.28 प्रति डालर पर बंद हुआ। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डालर की स्थिति को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.02 पर रहा। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा ने कहा कि पीएम की अपील का असर वृद्धि की गति में सुस्ती के रूप में दिखेगा।

इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य तेल और चांदी भी बढ़ा रहे आयात बिल

राजीव कुमार • जागरण

नई दिल्ली: पेट्रोलियम पदार्थ और सोने के साथ इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद, खाद्य तेल और चांदी के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। देश के कुल आयात में इन पांच उत्पादों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। गत वित्त वर्ष 2025-26 में 774 अरब डालर का कुल आयात किया गया और इनमें पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रानिक्स आइटम, सोना, चांदी, खाद्य तेल की हिस्सेदारी 393 अरब डालर की थी। पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की खपत सोच-समझ कर करने तो सोने की खरीदारी को एक साल तक टालने की अपील की है, जिससे आयात बिल को कम किया जा सके। आरबीआइ के मुताबिक इस साल एक मई को विदेशी मुद्रा का भंडार 690 अरब डालर का था। जबकि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के समय इस साल फरवरी आखिर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 728.5 अरब डालर का था।

पिछले एक साल के दौरान डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में 10 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। सोने के दाम में पिछले एक साल में 50 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक का इजाफा हुआ है। इस कारण वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात बिल 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 72 अरब डालर तक पहुंच गया। जबकि गत वित्त वर्ष 2025-26 में वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 36 टन कम सोने का आयात किया गया। दूसरी तरफ, गत वित्त वर्ष में चांदी के आयात में मात्रा और राशि दोनों के लिहाज से भारी बढ़ोतरी रही। मूल्य के लिहाज से चांदी के आयात में 149 प्रतिशत का इजाफा रहा। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों व एथनाल जैसे वैकल्पिक ईंधन को अपनाने से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कम हो रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कच्चे तेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थ का आयात 174 अरब डालर का रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 6.37 प्रतिशत कम है। इस अवधि में खाद्य तेल का आयात 19.5 अरब डालर रहा। देश में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाकर इस आयात को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रानिक्स आइटम का आयात गत वित्त वर्ष में 116 अरब डालर का रहा। मोबाइल फोन, टीवी बनाने के लिए सैकड़ों छोटे इलेक्ट्रानिक आइटम आयात किए जाते हैं। इनका निर्माण भारत में शुरू करके आयात बिल को कम किया जा सकता है।

- मूल्य के लिहाज से चांदी का आयात 149 प्रतिशत बढ़ा
- इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों का आयात 116 अरब डालर का रहा

डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट से भी सोने का आयात बिल बढ़ा है। सोने के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, इसलिए भारत में सोने की खरीदारी कम करने से सोने के भाव पर फर्क नहीं पड़ेगा। **-एसपी शर्मा,** मुख्य अर्थशास्त्री, एसोचैम

बीते दो वित्त वर्ष में सोना-चांदी का आयात

- वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात 721.03 टन
- वित्त वर्ष 2024-25 में सोने का आयात 757.09 टन
- वित्त वर्ष 2025-26 में चांदी का आयात 7334 टन
- वित्त वर्ष 2024-25 में चांदी का आयात 5164 टन

2025-26 में प्रमुख उत्पादों का आयात मूल्य

पेट्रोलियम पदार्थ और कच्चा तेल	174 अरब डालर
इलेक्ट्रानिक्स आइटम	116 अरब डालर
सोना	72 अरब डालर
खाद्य तेल	19.5 अरब डालर
चांदी	12 अरब डालर

अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 38,440 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र: अप्रैल में इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड योजनाओं में 38,440 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया गया और यह मार्च के मुकाबले पांच प्रतिशत कम है। इसके अलावा, एसआइपी (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के माध्यम से मासिक योगदान पिछले महीने मार्च में 32,087 करोड़ रुपये से घटकर 31,115 करोड़ रुपये रह गया। अप्रैल में 3.22 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया। इसमें डेट फंडों में 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा योगदान है। इस निवेश के चलते उद्योग की प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) अप्रैल के अंत में बढ़कर 81.92 लाख करोड़ रुपये हो गई। मार्च अंत में यह आंकड़ा 73.73 लाख करोड़ रुपये था।

इक्विटी सेगमेंट में, फ्लेक्सी कैप फंड 10,148 करोड़ रुपये के शुद्ध प्रवाह के साथ श्रेणी में सबसे आगे रहे, इसके बाद स्माल कैप फंड 6,886 करोड़ रुपये और मिड कैप फंड 6,551 करोड़ रुपये के साथ रहे। इसके अलावा, लार्ज कैप फंड ने 2,525 करोड़ रुपये का प्रवाह दर्ज किया। अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध निवेश 3,040.3 करोड़ रुपये रहा, जो महीने-दर-महीने के आधार पर 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। 30 अप्रैल तक गोल्ड ईटीएफ का नेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 1.78 लाख करोड़ रुपये था।

एसआइपी में मासिक योगदान घटकर 31,115 करोड़ रुपये रहा, पिछले महीने गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध निवेश 34 प्रतिशत बढ़ा

शहरों में बेरोजगारी दर में मामूली कमी आई

नई दिल्ली, प्रेट्र: मार्च तिमाही में शहरों में बेरोजगारी दर मामूली कम होकर 6.6 प्रतिशत हो गई। अक्टूबर-दिसंबर, 2025 में यह 6.7 प्रतिशत थी। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर पिछली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2025) के मुकाबले बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण इलाकों में, नियमित वेतन वाले कर्मचारियों की संख्या जनवरी-मार्च, 2026 के दौरान पिछली तिमाही के 14.8 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गई।

स्वरोजगार लोगों की हिस्सेदारी अक्टूबर-दिसंबर 2025 के 63.2 प्रतिशत से घटकर इस तिमाही में 62.5 प्रतिशत हो गई। जनवरी-मार्च 2026 के दौरान देश में औसतन 57.4 करोड़ लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 40.2 करोड़ पुरुष और 17.2 करोड़ महिलाएं थीं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वे में कुल 5,61,822 लोगों को शामिल किया गया।

कच्चा तेल तय करेगा विकास दर की रफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से तय होंगी। एसबीआइ रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पूरे वित्त वर्ष क्रूड 90 डालर के स्तर पर रहता है तो भारत की सालाना विकास दर 6.8 प्रतिशत रहेगी। हालांकि, अगर क्रूड की कीमतें 130 डालर प्रति बैरल रहती है तो विकास दर घटकर छह प्रतिशत पर आ जाएगी। वैसे, एसबीआइ का अनुमान है कि पूरे वर्ष क्रूड कीमत 100 डालर प्रति बैरल के स्तर पर रह सकती है, जिसकी वजह से भारत की विकास दर 6.6 प्रतिशत रहेगी। यह आरबीआइ की अनुमानित सालाना विकास दर 6.9 प्रतिशत से कम है। मूडीज, एसएंडपी जैसी कई अन्य वैश्विक एजेंसियों ने भी भारत की विकास दर के अनुमान को घटाया है।

सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 104-105 डालर प्रति बैरल रही है। जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय का डाटा बताता है कि अप्रैल और मई में अभी तक भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से औसतन 109.5 डालर प्रति बैरल की दर से कच्चे तेल खरीदा है। भारत अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत तक क्रूड बाहर से आयात करता है और यही वजह है कि इसकी कीमतों का असर पूरी इकोनमी पर होता है।

क्रूड के दाम रुपये की कीमत को कर रहे प्रभावित : अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत भारतीय रुपये की कीमत को भी प्रभावित कर रही है। क्रूड की खरीद डालर में होती है और जितना क्रूड महंगा होता है, उतना ही ज्यादा डालर देश से बाहर जाता है। लिहाजा इससे रुपये कमजोर होता है। एसबीआइ रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पूरे वर्ष रुपया 95 के स्तर पर रह जाता है तो भारतीय इकोनमी का आकार घटकर 4.04 ट्रिलियन डालर रह जाएगा और ऐसी स्थिति में पांच ट्रिलियन की इकोनमी बनने का सपना वर्ष 2030 में ही पूरा हो सकेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर क्रूड 120 डालर रहता है तो महंगाई की दर 5.3 प्रतिशत और 130 डालर होने से महंगाई की दर 5.7 प्रतिशत तक जा सकती है।

- एसबीआइ रिपोर्ट के मुताबिक, क्रूड अगर औसतन 100 डालर रहा तो 6.6% रहेगी विकास दर
- डालर के मुकाबले 95 के स्तर पर रहा रुपया तो 2030 तक बनेंगे 5 ट्रिलियन डालर इकोनमी

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अंतरराष्ट्रीय

न्यूज गैलरी

'फुजैरा पोर्ट से भारतीयों की निकासी की खबर फर्जी'

नई दिल्ली : भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) फुजैरा पोर्ट के जरिये भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए समझौता कर रहे हैं। मंत्रालय ने इसे 'फर्जी और बेबुनियाद' खबर बताया है। मंत्रालय की फैक्ट चेक इकाई ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि ऐसी किसी निकासी योजना पर काम नहीं हो रहा है। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित विदेश यात्रा के दौरान यूएई के फुजैरा में भारतीय कामगारों की निकासी को लेकर समझौता हो सकता है। इसी दावे को विदेश मंत्रालय ने गलत बताया। (एएनआइ)

भारत ने भगोड़े राणा के प्रत्यर्पण पर पुर्तगाल का आभार जताया

लंदन : भारत ने भगोड़े अभय राणा के प्रत्यर्पण में सहयोग के लिए पुर्तगाल का आभार व्यक्त किया। सरकार ने इस कदम को विदेशों में रह रहे वांछित अपराधियों को वापस लाने के अपने निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। राणा को इंटरपोल रेड नोटिस जारी होने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते के तहत शनिवार को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया। यह हरियाणा में जबरन वसूली, धमकी और हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामलों में वांछित था। (प्रेट्र)

बलूचिस्तान में सीमा शुल्क गोदाम में आग से 35 घायल

क्वेटा : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग इलाके में सीमा शुल्क गोदाम में आग लगने से 35 लोग झुलस गए। आग के कारण एलपीजी टैंकर में विस्फोट हो गया। डान के अनुसार, क्वेटा-कराची राजमार्ग पर स्थित लकपास इलाके में सीमा शुल्क सुविधा केंद्र में रविवार को आग लगी और तेजी से पार्किंग क्षेत्र में फैल गई। तभी एलपीजी ले जा रहे एक टैंकर में आग लग गई और सीमा शुल्क चौकी के पार्किंग क्षेत्र में उसमें विस्फोट हो गया, जिससे भारी तबाही हुई। (आइएएनएस)

ट्रंप बोले, ईरान का जवाब 'मूर्खतापूर्ण', तेल 103 डालर के पार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और होर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिशों को एक बार फिर झटका लगा है। अमेरिका की ओर से ईरान को भेजे गए 14 सूत्रीय अल्पकालिक समझौता प्रस्ताव पर तेहरान के जवाब को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'बेवकूफी भरा प्रस्ताव' करार दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के जवाब को 'अस्वीकार्य' बताते हुए खारिज कर दिया था। ट्रंप की प्रतिक्रिया के बाद आशंका बढ़ गई कि दो महीने से ज्यादा समय से जारी संघर्ष लंबा खिंच सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब दो प्रतिशत बढ़कर 103 डालर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं।

रायटर के अनुसार, जेपी मोर्गन के विश्लेषकों ने अनुमान जताया है कि तेल की कीमतें पूरे साल 100 डालर के आसपास बनी रह सकती हैं।

ईरान ने रविवार को पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को अपना जवाब भेजा था। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने, युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता स्वीकार करने और अमेरिका से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की मांग की गई।

ईरानी जवाब मिलने के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने ईरानी प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, लेकिन यह उन्हें 'बिल्कुल पसंद नहीं आया' और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया।

एपी के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान की मांगें 'वैध, उदार और जिम्मेदार' हैं। वहीं, भारत स्थित ईरानी दूतावास ने भी कहा कि अमेरिका को भेजा गया जवाब ईरानी जनता के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

ट्रैकर बंद करके होर्मुज पार कर रहे टैंकर : न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, शिपिंग डाटा रखनेवाली फर्म केप्लर और एलएसईजी ने बताया कि पिछले हफ्ते कच्चा तेल लदे तीन विशालकाय मालवाहक जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट पार करने में सफलता हासिल की। फर्म ने दावा किया कि तेल टैंकरों ने ट्रैकर स्विच-आफ कर दिया, जिससे वे ईरानी हमलों से बच सके।

लेबनान की गुहार, इजरायल को रोके अमेरिका : लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने अमेरिका से इजरायल पर हमले रोकने के लिए दबाव डालने की अपील की है। शनिवार के बाद से इजरायली हमलों में 74 लोगों की मौत हुई है।

- खाड़ी संकट समाधान के लिए ट्रंप की चीन यात्रा पर टिकी वैश्विक निगाहें
- अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर ईरान का जवाब ट्रंप ने खारिज किया
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम दो प्रतिशत तक बढ़े
- सीमित संख्या में टैंकर अब भी होर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे

तेहरान में होर्मुज स्ट्रेट और डोनाल्ड ट्रंप को प्रदर्शित करते अमेरिका विरोधी बिलबोर्ड के सामने से सोमवार को गुजरते राहगीर। रायटर

अमेरिकी सैन्य समर्थन पर निर्भरता खत्म करना चाहता है इजरायल

न्यूयार्क, रायटर : इजरायल सैन्य मदद के लिए अमेरिकी वित्तीय निर्भरता खत्म करना चाहता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में उम्मीद जताई कि एक दशक में इजरायल की अमेरिकी सैन्य समर्थन पर निर्भरता नहीं रहेगी। इजरायल खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन संभव है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेतन्याहू ने सीबीएस न्यूज के '60 मिनट्स' कार्यक्रम में कहा, मैं हमारे सैन्य सहयोग के तहत मिलने वाली अमेरिकी वित्तीय सहायता को शून्य तक कम करना चाहता हूं। इजरायल को प्रति वर्ष लगभग 3.8 अरब डालर की अमेरिकी सैन्य सहायता मिलती है। अमेरिका ने 2018 से 2028 तक इजरायल को कुल 38 अरब डालर की सैन्य सहायता प्रदान करने पर सहमति जताई है।

छात्र वीजा पर रह रहा भारतीय मूल का ट्रांसजेंडर बना स्काटिश संसद सदस्य

लंदन, प्रेट्र : एक भारतीय छात्र स्काटिश संसद सदस्य (एमएसपी) के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु में जन्मे क्यु मणिवन्नन ट्रांसजेंडर हैं और 2021 में छात्र वीजा पर स्काटलैंड आए थे। वह ऐसे व्यक्ति हैं, जो विदेशी नागरिक होने के बावजूद ब्रिटेन में रहने के लिए स्थायी वीजा नहीं रखते।

उन्हें स्काटिश ग्रीन्स की एडिनबर्ग और लोथियंस ईस्ट क्षेत्रीय सूची से स्काटलैंड की संसद के लिए चुना गया। पिछले सप्ताह हुए चुनावों के परिणाम नौ मई को घोषित किए गए। यह एक नियम में बदलाव के कारण संभव हो पाया। उनकी एमएसपी (स्काटिश संसद सदस्य) उम्मीदवारी एक राष्ट्रमंडल नागरिक के रूप में संभव हुई, जिसके अनुसार अल्पकालिक वीजा पर रहने वाले और अनिश्चितकालीन निवास की अनुमति या स्थायी निवास वाले विदेशियों को भी स्काटलैंड में चुनाव लड़ने के लिए पात्र माना जाता है।

जेल से रिहा हुए थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा

बैंकाक में सोमवार को जेल से पैरोल पर रिहा होने के बाद समर्थकों के बीच थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा। एपी

बैंकाक, रायटर : थाईलैंड के प्रभावशाली पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पैरोल पर अपनी एक साल की सजा के शेष चार महीने पूरे करने की अनुमति दी गई है। अदालत के उस फैसले के बाद थाकसिन को आठ महीने जेल में बिताने पड़े, जिसमें कहा गया था कि जेल से बचने के लिए उन्होंने गलत तरीके से अस्पताल में रहने का बहाना बनाया था। 76 वर्षीय अरबपति ने थाई राजनीति को नया रूप दिया और उस पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन हाल ही में जेल जाने और उनकी कभी शक्तिशाली रही फेउ थाई पार्टी के इस साल की शुरुआत में हुए अब तक के सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन के बाद उनका प्रभाव कम हो गया है। थाकसिन स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 7:40 बजे जेल से बाहर निकले। जेल के बाहर सोमवार तड़के से ही सैकड़ों समर्थक जमा थे।

काठमांडू में टर्किश एयरलाइंस के विमान में लगी आग, बाल-बाल बचे 288 यात्री

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सोमवार सुबह बड़ा विमान हादसा टल गया, जब इस्तांबुल से आ रही टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट टीके-726 के लैंडिंग के दौरान पिछले पहिये में आग लग गई। विमान में सवार सभी 277 यात्रियों और 11 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यह घटना सुबह हुई, जब एयरबस ए330 विमान रनवे पर उतर रहा था और उसके दाहिने पिछले टायर में आग भड़क उठी। आग लगते ही एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत उड़ान संचालन रोक दिया और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, लेकिन विमान को मुख्य रनवे पर ही रोकना पड़ा, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकाला गया।

ईरान से तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कल से चीन की यात्रा पर

बीजिंग, प्रेट्र : ईरान से जारी तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा करने जा रहे हैं। वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के आमंत्रण पर 13 से 15 मई तक बीजिंग का दौरा करेंगे। इस दौरान ट्रंप और चिनफिंग के बीच ईरान, ताइवान और व्यापार से लेकर एआइ व परमाणु हथियार जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। करीब नौ वर्ष बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली चीन यात्रा होगी। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में 2017 में बीजिंग का दौरा करने वाले अंतिम अमेरिकी राष्ट्रपति थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के चलते वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न है और ताइवान समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के चीन दौरे की यह घोषणा की। जबकि हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रधान उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने रविवार को बताया कि ट्रंप बुधवार शाम बीजिंग पहुंचेंगे। वह गुरुवार को एक स्वागत समारोह और राष्ट्रपति चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। दोनों नेता शुक्रवार को फिर मुलाकात करेंगे।

इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव : अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, चिप और रेयर अर्थ मिनिरल्स समेत कई मुद्दों पर तनाव है। इनमें सबसे प्रमुख ताइवान है। चीन इस द्वीपीय क्षेत्र को अपना मानता है। अमेरिका की तरफ से इसे सैन्य साजो-सामान मुहैया कराए जाने पर वह कई बार नाराजगी जता चुका है।

- नौ साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा
- चिनफिंग से ईरान, ताइवान और परमाणु हथियार जैसे मुद्दों पर वार्ता संभव

ओसाका में 29 जून 2019 को जी20 बैठक के दौरान शी चिनफिंग और डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

प्रधानमंत्री की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जो सलाह दी है, उसकी चर्चा स्वाभाविक ही तेज हो गई है। सर्वाधिक चर्चा एक साल तक सोना न खरीदने की सलाह को लेकर हो रही। भारत में सोना केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से भी बहुत प्रचलित है। स्वर्ण के प्रति ऐसी मानसिकता है कि यहां जीवन से जुड़े हरेक संस्कार में इसकी जरूरत पड़ती है। अतः एक साल तक सोना न खरीदने की सलाह पर खूब चर्चा हो रही है। आज देश के हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि सोना न खरीदने या कम खरीदने से क्या होता है? भारत प्रति घंटे औसतन 80 किलोग्राम सोना खरीदता है और देश में खपत के लिए जरूरी 90 प्रतिशत सोना आयात करना हमारी मजबूरी है। सोना खरीदने में डॉलर खर्च करने की जरूरत पड़ती है, इसका असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। एक अनुमान है कि भारत अपनी रक्षा पर जितना धन खर्च करता है, उससे करीब आधे धन का सोना आयात करता है। सोने के साथ समस्या है कि तिजोरियों में बंद हो जाता है और उसमें निवेशित पैसा ठहर जाता है। निस्संदेह, प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने की खपत कम होगी, तो देश को आर्थिक बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री की दूसरी बड़ी अपील है- घर से काम करने की प्रथा को पुनर्जीवित करना। उन्होंने कार्यालयों और व्यवसायों से आग्रह किया है कि जहां भी संभव हो, वे घर से काम करने की विधि का उपयोग करें।

यह पहला अवसर नहीं है, जब किसी प्रधानमंत्री ने लोगों से मितव्ययिता की अपील की है। यह देश की तरक्की को बनाए रखने की सामूहिक चिंता का समय है।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ईंधन की बचत होगी। पेट्रोल, डीजल के आयात में धन की बचत होगी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की यह भी सलाह है कि पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से उपयोग किया जाए। यहां यह ध्यान रखना होगा कि दो महीने से भी ज्यादा समय से भारत ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों को बहुत हद तक संभाले रखा है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में तेल के भाव में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। जब दुनिया महंगाई से जूझ रही है, जब तेल का अभाव हो रहा है, तब पचास से ज्यादा देशों में पहले से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लोग भूले नहीं हैं, कोरोना और लॉकडाउन के समय भी वर्क फ्रॉम होम की नौबत आई थी। अब एक अंतर यह होगा कि तब लोग जान बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और अब संभावित आर्थिक मंदी और महंगाई से बचने के लिए ऐसा करेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चर्चा की है, उससे कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही कुछ फैसले होंगे और दिशा-निर्देश जारी होंगे।

प्रधानमंत्री की बाकी सलाह भी उल्लेखनीय है। निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, कारपूलिंग या साझा यात्रा को बढ़ावा, गैर-जरूरी विदेश यात्रा स्थगित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों, रेल का उपयोग करना जैसी सलाह वाकई कारगर है। अगर इन उपायों को हमने लागू कर लिया, तो हम महंगाई से बच जाएंगे। यह कोई पहला अवसर नहीं है, जब किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से मितव्ययिता बरतने की अपील की है। देश बुनियादी रूप से मजबूत है। उसकी विकास दर भी तुलनात्मक रूप से सराहनीय है। महंगाई काबू में है। अतः यह न केवल अपनी, बल्कि देश की तरक्की को भी बनाए रखने की चिंता का समय है। ईरान युद्ध से भारत के लिए संकट बहुत बड़ा हो गया है। लोग संयम के लिए जरूर प्रेरित होंगे, पर ऐसे संकट के समय वर्तमान सरकारी नीतियों की एक बार अवश्य समीक्षा करनी चाहिए। जो लोग सक्षम हैं, उन्हें भार उठाने के लिए तैयार करना होगा, ताकि अक्षम लोगों को संकट के समय ज्यादा सहारा दिया जा सके।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 12 मई, 1951

जमींदारी उन्मूलन कानून

उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार कानून को उत्तर प्रदेश के चार हजार से अधिक जमींदारों ने राज्य के सबसे उच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी थी। यह कानून उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने दीर्घकालीन विचार के बाद स्वीकार किया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करके इस वर्ष के स्वतन्त्रता-दिवस पर राज्य के किसानों को यह उत्कृष्ट उपहार भेंट किया था। उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस कानून के लिए राज्य की सरकार को हृदय से धन्यवाद दिया। किन्तु इस कानून द्वारा जमींदारों के स्थापित हितों को आघात पहुंचता था और यद्यपि वह यह समझ चुके हैं कि बदले हुए जमाने में उनके स्थापित हित कायम नहीं रह सकते, फिर भी उन्होंने पहले तो इस कानून के विधानसभा द्वारा स्वीकृत होने में ही अधिक से अधिक विलम्ब लगाया और उनकी इच्छा के विरुद्ध जब कानून बन ही गया, तो उस पर अमल न होने देने के लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के सामने अपना पक्ष उपस्थित करने के लिए उन्होंने देश के अच्छे से अच्छे वकीलों की सहायता प्राप्त की। इस सबके बावजूद उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी आपत्तियों को रद्द करते हुए जमींदारी उन्मूलन कानून को नियमित ठहरा दिया है।

जमींदारों की आपत्ति यह थी कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के विरुद्ध है और इसलिए अनियमित है। उनका कहना था कि संविधान ने लोगों की सम्पत्ति हस्तगत करने के संबंध में राज्यों की विधानसभाओं को कानून बनाने की सम्पूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की है। किन्तु हाईकोर्ट ने जमींदारों की इस आपत्ति को तथ्यहीन ठहराया है। न्यायाधीशों का कहना है कि संविधान ने संसद को भारतीय संघ के काम के लिए सम्पत्ति हस्तगत करने की सत्ता प्रदान की है और राज्यों की विधानसभाओं को भारतीय संघ के कामों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सम्पत्ति हस्तगत करने वाला कानून बनाने की सत्ता दी है। सम्पत्ति हस्तगत करने के विरुद्ध संविधान ने एक ही संरक्षण की व्यवस्था की है। संविधान के अनुच्छेद 31 (2) का कहना है कि सम्पत्ति को केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये हस्तगत किया जायेगा और बिना मुआवजा दिये कोई सम्पत्ति हस्तगत नहीं की जायेगी।

सितारे के सामने सियासी चुनौतियां

दक्षिण एक्सप्रेस
यहां स्कैन करें

एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बने सितारे विजय को ध्यान रखना होगा, सिनेमा में चकाचौंध खत्म होते ही सितारा अपने असली रूप में लौट सकता है, पर सियासत में यह सुविधा नहीं है।

बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दे चुके अभिनेता सी जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपने सियासी सफर की शानदार शुरुआत की। बीती 4 मई को सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने के बाद इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें छह दिन लग गए। यह तो महज शुरुआत है, क्योंकि अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते हुए उन्हें अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

सिनेमा की दुनिया में तो सुपरस्टार विजय उन कहानियों से परिचित होते होंगे, जिनमें एक नौजवान को निर्णायक विजय से पहले कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, मगर उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि राजनीति में कदम रखने पर असली दुनिया में भी उन्हें उसी तरह जूझना पड़ेगा। सिने-जगत में चकाचौंध खत्म होते ही सितारा तुरंत अपने असली रूप में लौट सकता है, लेकिन सियासत में ऐसी सुविधा नहीं होती। एक बार राजनीति की दौड़ में शामिल होने के बाद पीछे मुड़ना लगभग नामुमकिन होता है।

विजय को इन कटु सच्चाइयों का अनुभव हो रहा होगा। 4 मई को उनकी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कषगम' (टीवीके) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस द्वारा पांच विधायकों के सशर्त समर्थन का वादा करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों व 2029 के संसदीय चुनावों में साझा भविष्य की कल्पना के अगले दिन से ही विजय के लिए हालात बिगड़ने लगे। कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विजय द्वारा पेश दावे का पत्र पढ़ा, जिसमें चुनाव के बाद गठबंधन के रूप में कांग्रेस के समर्थन का उल्लेख था, मगर तत्काल उन्हें न्योता नहीं दिया। सरकारिया आयोग के दिशा-निर्देश, बोम्मई मामले समेत सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के फैसलों में यह साफ कहा गया है कि सत्ता हस्तांतरण का मौका सबसे बड़ी पार्टी को दिया जाना चाहिए। बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए, न कि राजभवन में, जिसे अब लोकभवन कहा जाता है।

गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका सत्ताधारी दल के साथ टकराव वाली रही है, इसलिए अर्लेकर के फैसलों को भी विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह में एक बाधा के रूप में देखा गया। दरअसल, भाजपा नेतृत्व को सबसे ज्यादा गुस्सा कांग्रेस के साथ टीवीके के गठबंधन से आया। यह तमिलनाडु के साथ केरल, पुडुचेरी, यहां तक कि आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी थी, जहां विजय के काफी अधिक समर्थक हैं।

इन छह दिनों के भीतर एक वक्त ऐसा भी आया, जब सत्ता से बेदखल हुई द्रमुक पार्टी सक्रिय हो गई। कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकलने से नाराज द्रमुक ने विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि अन्नाद्रमुक के प्रस्ताव पर मुखर प्रतिक्रिया देने लगे थे। अन्नाद्रमुक के नेता ई पलानीसामी (ईपीएस) अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे थे, क्योंकि 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही वह लगातार हार का सामना करते आ रहे हैं। चुनावी नतीजे के बाद ईपीएस को अन्नाद्रमुक में संभावित असंतोष की चिंता सताने लगी थी और इसलिए उन्होंने राज्यपाल द्वारा मुहैया कराए गए इस अवसर का लाभ उठाते हुए किसी भी तरह से सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलनी शुरू की दी।

द्रमुक के एक गुट ने अन्नाद्रमुक को समर्थन देने की बेतुकी संभावना पर विचार करना भी शुरू कर दिया, मगर पार्टी के समझदार लोगों ने इस कदम की गंभीरता को समझते हुए कहा कि अगर ऐसा किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव परिणामों ने द्रविड़ दलों की चुनावी अपील पहले ही काफी कम कर दी थी। इन दोनों द्रविड़ दलों ने थोल थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पार्टी वीसीके को बाहर से समर्थन देने की संभावना पर भी गौर किया। इसके पीछे तर्क यह ढूंढ़ा गया कि दलितों की इस पार्टी को समर्थन देना एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है और इससे नवगठित टीवीके को मात दी जा सकती है, मगर एक बार फिर इन दोनों पार्टियों के समझदार लोगों ने ऐसे जोखिम भरे रास्ते को न अपनाने की सलाह दी और इसके खतरे बताए।

वामपंथी दलों को फैसला लेने में दो दिन लग गए, पर इसका असर वीसीके और आईयूएमएल पर भी नैतिक रूप से दिखने लगा। सीपीआई और सीपीएम के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनता के फैसले को सही ढंग से समझा और किसी भी तरह के जोखिम भरे कदम न उठाने की सलाह दी। जब द्रमुक को समझ आ गया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तब उसने अपने सहयोगी दलों- सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल -को निर्देश दे दिए कि वे टीवीके को बाहर से समर्थन दे सकते हैं और कुछ हद तक स्वायत्तता बनाए रख सकते हैं, साथ ही 'सांप्रदायिक ताकतों' को दूर रख सकते हैं। यह सुझाव इन दलों को रास आया और शनिवार तक उन्होंने टीवीके को बिना शर्त अपना समर्थन दे दिया। तस्वीर का दूसरा रोचक पहलू यह है कि अन्नाद्रमुक के लिए हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि उसके 47 में से दो-तिहाई विधायकों ने ईपीएस के नेतृत्व पर अविश्वास जताते हुए बगावत का झंडा उठा लिया है।

बहरहाल, अब जब विजय मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाल चुके हैं, तो उनके सामने कम से कम पांच बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह बेहद कम बहुमत पर टिकी है। दूसरी, अपने समर्थक दलों को जोड़े रखना और अनुभवहीन मंत्रिमंडल का नेतृत्व करना। तीसरी, केंद्र सरकार और राज्यपाल के साथ कठिन संबंधों को संभालना, जो विजय के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चौथी, जनता की बड़ी उम्मीदों को पूरा करना, क्योंकि उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए हैं और उनको पूरा करने के लिए संसाधनों की उन्हें व्यवस्था करनी होगी और पांचवीं, हार से भड़की द्रमुक पार्टी को संभालना।

तमिलनाडु के चुनावी नतीजे साफ बताते हैं कि जन-आकांक्षाएं चरम पर हैं। मुख्यमंत्री विजय पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी यह भी है कि आने वाले वर्षों में अपनी पार्टी को अन्य पार्टियों की तरह बनने से बचाकर रखें, जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि पारंपरिक राजनीतिक वर्ग के गुस्से को उन्हें शांत करना होगा, जिसने अभी तक जनादेश को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भीषण गर्मी से निपटने के लिए कर लें पूरे इंतजाम

यहां स्कैन करें

बहार दत्त | पत्रकार व पर्यावरणविद

आईआईटी बॉम्बे के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लू मुख्यतः स्थानीय कारकों से आती है, न कि कहीं और से आने वाली गर्म हवाओं के कारण। 'स्प्रिंगर नेचर रिसर्च' में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन बताता है कि मिट्टी की नमी, बादल छाने और आर्द्रता जैसी स्थानीय मौसमी परिस्थितियां लू की तीव्रता व अवधि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसका अर्थ है, चरम गर्मी पैदा करने में क्षेत्रीय या जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी मौसमी क्रियाओं से अधिक स्थानीय कारक प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में, स्थानीय स्तर पर किए गए सरल उपाय नागरिकों को चरम मौसमी घटनाओं से तत्काल राहत दे सकते हैं।

हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत उन चंद देशों में शुमार है, जिसके पास 100 से अधिक शहरों के लिए 'हीट एक्शन प्लान' (गर्मी से निपटने की योजना) तैयार है। इनमें स्थानीय और अति-स्थानीय कार्य-योजनाओं का जिक्र है। ये योजनाएं मूलतः राज्य व जिला स्तरीय निकायों द्वारा तैयार की गई रणनीतिक संरचनाएं हैं, जो भीषण गर्मी से निपटने के बहुपक्षीय लक्ष्य से निर्देशित हैं। गर्मी से पैदा होने वाली भयावहता को देखते हुए ये योजनाएं न सिर्फ अनिवार्य हैं, बल्कि जीवन बचाने वाली भी साबित हो सकती हैं।

देश में गर्मी से लड़ने के लिए विशेष योजनाएं तो बनी हुई हैं, लेकिन उनमें कुछ बुनियादी कमियां भी हैं, जिनको दूर करना बहुत जरूरी है।

इन योजनाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें शुरुआती चेतावनी प्रणाली के महत्व, आपात समय के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचों में सुधार व संकट से निपटने के लिए चिकित्सा समुदाय के प्रशिक्षण जैसे कदमों पर उचित जोर दिया गया है। दिल्ली में राममनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा स्थापित विशेष 'हीट स्ट्रोक इमर्शन कूलिंग यूनिट' या राजस्थान के जोधपुर व चुरू जैसे शहरों में कूलिंग सेंटर की स्थापना जैसे कदम मारक गर्मी से बचाने में कारगर साबित हुए हैं। अन्य शहरों में भी जहां अधिक गर्मी में काम के घंटों में बदलाव जैसे उपाय अपनाए जाते हैं, वहीं अहमदाबाद जैसे शहरों में छतों को विशेष रंग से रंगकर घर के तापमान को कम करने की व्यवस्था की जाती है।

हालांकि, कुछ योजनाएं मात्र कागजी बनकर रह गई हैं और कुछ शहरों में ये सिर्फ पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने वाली रिपोर्ट प्रतीत होती हैं। वहीं, कुछ योजनाएं दूसरे राज्यों या क्षेत्रों से नकल करके तैयार की गई लगती हैं। मसलन, राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र की योजना में जम्मू-कश्मीर सरकार के कई निर्देश दिखते हैं, जिनका मतलब है कि 'एक्शन' में हेराफेरी की गई है। इसी तरह, कुछ योजनाएं अधूरी जान पड़ती हैं। जैसे, दिल्ली की योजना में हरियाली बढ़ाने का उल्लेख तो है, पर पौधारोपण के लिए जमीन की कमी और पौधों के जल्द मर जाने जैसी समस्याओं का जिक्र नहीं है।

कई योजनाओं में बुनियादी कमी यह है कि वे शहरी संरचना में मौजूद व्यवस्थागत कमियों पर ध्यान नहीं देतीं। जैसे- राजधानी दिल्ली के बड़े हिस्सों में हरियाली का न होना, जिसके कारण सीमेंट से बने एक्सप्रेस-वे, जो 'हीट आइलैंड इफेक्ट' (शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में औसतन काफी अधिक होना) को और बढ़ा देता है, क्योंकि शहर में प्रवेश करते समय ये सड़कें पूरी तरह से बिना हरियाली के रह जाती हैं। इसी तरह, शहरी नियोजन में अब लू के दौरान पैदल चलने वालों या सड़क/फुटपाथ दुकानदारों के लिए बहुत कम जगह बची है। हालांकि, यहां ठाणे जैसे शहर भी हैं, जहां की योजनाओं में सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन है और उनमें ठोस वैज्ञानिक दृष्टिकोण व नवोन्मेषी नीतिगत उपायों का संतुलित मिश्रण दिखता है।

जाहिर है, इन योजनाओं को उन संवेदनशील लोगों के हित में बनाया जा सकता है, जिनके पास लू में भी काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, जैसे डिलीवरी करने वाले, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर आदि। गर्मी से लड़ने के लिए हमें व्यापक उपाय अपनाने ही होंगे, जैसा कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने बताया है, यानी छायादार पेड़ लगाना, छायादार फुटपाथ बनाना, 'कूल रूफ' तकनीक अपनाना, प्राकृतिक वायु को अधिकतम जगह देने के लिए शहरी संरचना में बदलाव आदि। भीषण गर्मी की भविष्यवाणी को देखते हुए अब 'कूलिंग' को विलासिता मानने से हमें बचना चाहिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

शिक्षक का सही दायित्व

किसी ने पूछा, 'शिक्षक का कार्य क्या है?' एक शिक्षक को बेहतर और श्रेष्ठतर जीवन की दिशा में छात्र का मार्गदर्शन करने के लिए पहले यह जानना होगा कि आप क्या जानते हैं? आप केवल वही जानते हैं, जो आपने अपने पूर्वाग्रहों से सीखा है, जो आपके एक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पूंजीवादी, साम्यवादी होने की संस्कारबद्धता है। इस प्रकार का मार्गदर्शन केवल दुर्दशा व रक्तपात की ओर ले जाता है, जैसा दुनिया भर में दिखलाई पड़ता है। क्या यह शिक्षक का कार्य नहीं है कि वह छात्र की इन संस्कारित करने वाले प्रभावों से स्वयं को मुक्त करने में सहायता करे, ताकि वह भय और आक्रामक असंतोष के बगैर अपने जीवन से मुलाकात कर सके?

अगर एक शिक्षक के रूप में आप छात्र में विचार और भाव भर देते हैं, तब क्या आप उसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने पर निर्भर नहीं बना रहे होते हैं? जब आप उसकी प्रेरणा के रूप में काम करते हैं, जब वह आपकी तरफ किसी नेता या आदर्श की तरह देखता है, तब वह निश्चित ही आप पर निर्भर करने लगता है। क्या निर्भरता भय को नहीं उपजाती और क्या भय प्रज्ञा को विकलांग नहीं बना देता?

आप सोच रहे होंगे कि अगर शिक्षक को एक प्रेरक, एक उदाहरण या एक मार्गदर्शक नहीं होना है, तो भला उसका सही कार्य क्या है? जिस क्षण आप इनमें से कुछ भी नहीं होते, तब आप क्या हैं? आपका छात्र के साथ क्या संबंध है? क्या पहले आपका छात्र के साथ कोई संबंध था भी? उसके साथ आपका संबंध एक धारणा पर आधारित था कि उसकी भलाई किसमें है, उसे यह होना चाहिए या वह होना चाहिए। आप शिक्षक थे और वह विद्यार्थी; आपने उस पर कार्य किया, उसे अपने विशिष्ट संस्कारों के अनुसार प्रभावित किया। इस प्रकार, जान-बूझकर या अनजाने में आपने उसे अपनी छवि के सांचे में ढाल दिया। जब आप उस पर कार्य करना छोड़ देते हैं, तब वह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको उसे समझना है और यह मांग नहीं करनी है कि वह आपको या आपके आदर्शों को समझे, जो वैसे भी बनावटी हैं। तब आपको 'जो है' के साथ पेश आना होता है, न कि 'जो होना चाहिए' के साथ।

जब शिक्षक हर छात्र को अद्वितीय मानकर चलता है, तब उसका एक ही सरोकार होता है, छात्र को संस्कारित करने वाले आंतरिक व बाह्य प्रभावों को समझने में उसकी सहायता करना।

निश्चित ही, जब शिक्षक हर छात्र को अद्वितीय व्यक्ति मानकर चलता है और इसलिए किसी दूसरे से उसकी तुलना नहीं करता, तब उसका प्रणाली या विधि से कोई सरोकार नहीं रह जाता। तब उसका एक ही सरोकार होता है, छात्र को संस्कारित करने वाले आंतरिक और बाह्य प्रभावों को समझने में उसकी सहायता करना, ताकि वह प्रज्ञा के साथ जीने की जटिल प्रक्रिया का सामना कर सके और पहले से ही मौजूद गड़बड़ी में और अधिक समस्याएं न जोड़े।

जे कृष्णमूर्ति

अमित शाह | केंद्रीय गृह मंत्री

हमारे देश के लोकतंत्र की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। इसे मजबूत और स्थिर बनाने में संविधान व न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सुंदर संतुलन ही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है।

सबसे पुरानी पार्टी ने दिखाया अवसरवाद

लगता है, कांग्रेस के जीने का तरीका यही हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा है कि कांग्रेस जिस पार्टी (द्रमुक) के समर्थन से केंद्र की सत्ता में 10 साल तक टिकी रही, मौका देखते ही उसी की पीठ में छुरा भोंक दिया। वह अब सत्ता के लोभ में तमिलनाडु में टीवीके के साथ खड़ी हो गई है। यह घटनाक्रम बताता है कि कांग्रेस कितनी बदहवास हो गई है। इसकी वजह यही है कि वह साल-दर-साल कमजोर होती जा रही है और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई हारती जा रही है। महाराष्ट्र में भी उसने सत्ता में बने रहने के लिए शिव सेना (उद्धव) को अपना समर्थन दे दिया था। खत्म होते वर्चस्व को बचाने के लिए उसे किसी क्षेत्रीय पार्टी के पीछे चलने से बचना चाहिए। इससे अच्छा तो यही होगा कि वह जनता के कामों से जुड़े। इससे वह सत्ता पाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि जनसेवा ही सत्ता के शिखर तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने सत्ता-सुख भोगा है और देश पर उसने अकेला राज किया है। अब उसे अपना 'आर्ट ऑफ लीविंग' बदलना चाहिए और जनता के कामों में रुचि दिखाकर उसका दिल जीतना चाहिए। अन्यथा उसकी गिरती छवि और गिरती चली जाएगी।

महेश नेनावा, टिप्पणीकार

कांग्रेस का लगातार कमजोर होना भारतीय राजनीति का एक बड़ा पक्ष है। कभी देश की सबसे प्रभावशाली पार्टी रही कांग्रेस आज कई राज्यों में अपना जनाधार खो चुकी है। संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व के संकट, वैचारिक अस्पष्टता और क्षेत्रीय दलों पर बढ़ती निर्भरता ने उसकी स्थिति और कठिन बना दी है। कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक धीरे-धीरे क्षेत्रीय दलों और भाजपा के बीच बंटता जा रहा है। नतीजतन, वह सत्ता में बने रहने के लिए हर दल से हाथ मिलाने को तैयार दिखती है। तमिलनाडु में तो उसने विजय को बिना मांगे ही समर्थन का ऑफर दे दिया था। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि वह भाजपा का वैचारिक मुकाबला किस आधार पर करेगी? केवल भाजपा-विरोध की राजनीति लंबे समय तक प्रभावी नहीं हो सकती। जनता अब स्थिर नेतृत्व, साफ दृष्टि व परिणाम आधारित राजनीति को प्राथमिकता देने लगी है। यही कारण है कि कांग्रेस कई राज्यों में मुख्य विपक्ष की भूमिका भी खोती जा रही है। हालांकि, लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक स्थिति स्थायी नहीं होती। जनता अंततः प्रदर्शन, प्रशासन और जनहित के आधार पर निर्णय लेती है, इसलिए कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, तभी वह सत्ता में लौटेगी।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

कांग्रेस

तमिलनाडु में खेला सही राजनीतिक दांव

भारत की सबसे पुरानी पार्टी आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस समय दुविधा की स्थिति में है। उस पर दबाव है कि वह क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन न करके अकेले दम पर धुर दक्षिणपंथियों के साथ संघर्ष करे। सच्चाई यह है कि आज भी कई राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टी ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में, कांग्रेस आखिर क्या करेगी? अगर वह अकेले चुनाव लड़ती है, तो क्षेत्रीय दलों का धर्मनिरपेक्ष मत विभाजित हो सकता है, जिससे भगवा पार्टी का रास्ता और भी सुगम व सरल हो जाता है। अगर कांग्रेस अकेले न लड़े और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर ले, तो उसका अपना अस्तित्व इतिहास के पन्नों में सिमट सकता है। इसलिए पार्टी यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि वह करे, तो क्या करे? यही कारण है कि हम उसे टीवीके के साथ सरकार बनाते हुए भी देख रहे हैं, जबकि वह तमिलनाडु में द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी थी।

सवाल 'इंडिया' ब्लॉक का भी है। कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि उसने अवसर को देखते हुए गठबंधन के प्रमुख दल द्रमुक का दशकों पुराना साथ छोड़ दिया। मगर ऐसा कहने वाले भूल रहे हैं कि राष्ट्रवादियों को सत्ता से बाहर रखने के लिए ऐसा किया गया है। अपने पांच विधायकों को उसने सोच-समझकर टीवीके के साथ जोड़ा है, ताकि एक ऐसी पार्टी को सत्ता न मिल सके, जिसकी विचारधारा भगवा पार्टी के पक्ष में हो। भले ही किसी को यह अवसरवादी निर्णय लगे, लेकिन यह नीतिगत ही है। अभिनेता विजय 'इंडिया' में शामिल हो सकते हैं या नहीं, यह सवाल अभी दूर है, पर भगवा पार्टी से उनकी दूरी स्थापित हो चुकी है। हालांकि, अगर टीवीके पार्टी 'इंडिया' ब्लॉक में शामिल होती है, तो यह सवाल भी उठ सकता है कि द्रमुक इस गठबंधन का हिस्सा रहेगा या नहीं? ऐसे में, यह एक अलग दुविधा है, जिसका सामना 'इंडिया', विशेषकर कांग्रेस को करना है।

कुल मिलाकर, अभी उलझन की स्थिति है। इसे साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि जल्द ही स्थिति साफ होगी और हम एक ऐसी कांग्रेस को देखेंगे, जो पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से राजनीति के मैदान में उतरेगी। अभी ही विजय को समर्थन देकर उसने एक ऐसा दांव खेला है, जिससे उसे चुनावी फायदा हो सकता है। इससे अंततः भगवा पार्टी को ही नुकसान होगा, इसलिए वह तिलमिला उठी है। उसके समर्थक कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं, जबकि भाजपा पूर्व में खुद शिव सेना के साथ ऐसा कर चुकी है। हमें इस घटनाक्रम को वक्ती जरूरत के रूप में देखना चाहिए।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

मन-विचार को वश में करने वाला ही योगी

विचार एक बड़ी शक्ति है। विचार–शक्ति द्वारा अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इस शक्ति का उपयोग करने की सही पद्धति जान लेना आवश्यक है। जिसने इस विचार की शक्ति को जान लिया और इसे वश में करना सीख लिया, वही योगी हो गया।

अध्यात्म

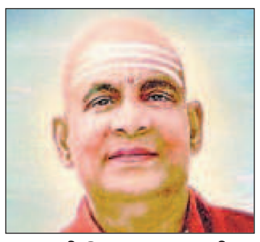

स्वामी शिवानंद सरस्वती

प्रत्येक मनुष्य का अपना-अपना मनोजगत होता है। उसकी अपनी विचार-सारणी होती है। वस्तुओं को समझने का अपना ढंग होता है। काम करने की अपनी पद्धति होती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की मुखाकृति एवं स्वर दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, उसी प्रकार सोचने-समझने की पद्धति भी प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न होती है।

प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के मानसिक कंपन अथवा विचार-कंपन के साथ एकत्व भाव हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी एक-दूसरे को सरलता से समझा जा सकेगा।

इस भूतल पर विचार-शक्ति एक महान शक्ति है। योगी के शस्त्र-भंडार में विचार एक सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र है। विधायक विचार हमें ऊंचा उठाते हैं, स्फूर्ति देते हैं और निर्माण करते हैं।

हमारे पूर्वजों ने इस शक्ति की अत्यंत दूरगामी संभावनाओं को समुचित रीति से समझा था। उनका विकास किया था और उनका यथासंभव उत्कृष्ट उपयोग भी किया था।

सृष्टि का मूल आधार विचार

समस्त सृष्टि का मूलाधार विचार ही है। विश्व-चित्त में जो एक विचार उत्पन्न हुआ, उसी से इस सकल दृश्य जगत का निर्माण हुआ है।

आदि विचार का आविर्भाव ही यह विश्व है। इस आदि विचार के आविर्भाव के कारण ईश्वरीय संकल्प की स्तब्धता स्पंदित हो उठी। यह स्पंदन कोई भौतिक कणों के झूले की तरह आगे-पीछे तीव्र गतिशील नहीं है, परंतु यह इतना सूक्ष्म है कि साधारण मन से उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इससे यह बात स्पष्ट हुई कि कोई भी शक्ति स्पंदन में परिणत हो सकती है। आधुनिक विज्ञान भी भौतिक जगत में सुदीर्घ अनुसंधानों के बाद अब पुनः इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। जिस प्रकार रेडियम एक दुर्लभ वस्तु है। उसी प्रकार विचार-शक्ति को पूर्णतः नियंत्रित करने वाले योगी भी इस संसार में रेडियम की ही तरह दुर्लभ हैं। जिस योगी ने अपने विचारों पर काबू पा लिया है और निरंतर ब्रह्म में अवस्थित कर लिया, उससे दिव्य गंध और दिव्य तेज (ब्रह्म-तेज) उसी प्रकार निःसृत होता रहेगा, जिस प्रकार अगरबत्ती से निरंतर मधुर सुगंधि निकलती रहती है। उसका जो तेज और सुगंध है, वह ब्रह्मवर्चस (ज्ञान का तेज) कहलाता है।

ज्यों-ही आप गुलाब, मोगरा और चंपा के फूलों का गुलदस्ता उठा लेते हैं, तो तुरंत चारों ओर उसकी सुगंध फैल जाती है और सभी को मुग्ध करती है। उसी प्रकार विचार को वश में कर चुके योगी का यश और उसकी कीर्ति दूर-दूर तक फैले बिना नहीं रहती। वह एक विश्व-शक्ति बन जाता है। प्रत्येक विचार का अपना एक भार होता है, आकार होता है, स्वरूप, प्रकार, वर्ण, गुण और शक्ति होती है। योगी अपने योग की अंतर्दृष्टि से यह सब प्रत्यक्ष देख सकता है।

विचार एक शक्ति

विचार भी पदार्थ की तरह है। जिस प्रकार आप एक संतरा उठा कर अपने मित्र को दे सकते हैं और उससे ले सकते हैं। उसी प्रकार उपयोगी और बलशाली विचार भी आप दूसरों को दे सकते हैं और उसे वापिस ले सकते हैं। यही विचार की शक्ति है।

विचार एक बड़ी शक्ति है। वह चलता है, वह निर्माण करता है। विचार-शक्ति के द्वारा अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इसके लिए उसे हस्तगत करने की और ठीक से उपयोग करने की सही पद्धति जान लेना आवश्यक है। मान लीजिए आपका मन पूर्णतया शांत है, विचारों से सर्वथा मुक्त है, लेकिन ज्यों-ही विचार आने लगे, तत्काल वह कोई-न-कोई नाम और रूप धारण कर लेता है।

प्रत्येक विचार का एक-न-एक नाम और कुछ-न-कुछ रूप होता ही है। इस प्रकार आप देखते हैं कि मनुष्य में जो भी विचार आता है या आ सकता है, वह किसी-न-किसी शब्द के साथ अवश्य जुड़ा होता है, मानो वह उसका अंग ही है।

विचार ही समस्त विश्व

शक्ति का एक ही आविर्भाव है, जिसे हम विचार कहते हैं। उसी की स्थूल अवस्था को आकार और सूक्ष्म अवस्था को नाम कहा जाता है, परंतु ये तीनों एक ही हैं। जहां एक होगा, वहां अन्य दो होंगे ही। जहां नाम है, वहां आकार भी है, विचार भी है। आध्यात्मिक विचार का वर्ण पीला है। क्रोध तथा द्वेषयुक्त विचार का वर्ण गहरा काला है। स्वार्थी विचार का वर्ण मटमैला होता है।

विचार एक तेजस्वी, प्राणवान, गतिशील शक्ति है। विचार को कार्यान्वित करने से विधायक शक्ति निर्माण होती है। विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है। मनुष्यों को प्रभावित करता है। जरा भी विचार-शक्ति प्राप्त होने पर दुर्बल विचार वाले सहस्त्रों लोगों को निश्चित रूप से प्रभावित किया जा सकता है। विचार-संस्कृति, विचार-शक्ति, विचार-प्रेरणा आदि विषयों से संबंधित साहित्य आजकल बहुत है। उनको पढ़ने से विचार संबंधी संपूर्ण जानकारी, उसकी शक्ति, काम और उपयोग आदि का समग्र परिचय प्राप्त हो सकता है।

एकमात्र विचार ही समस्त विश्व है। महादुख, वार्धक्य, मृत्यु, महापाप, भूतल, आकाश, जल, वायु, अग्नि सब वही है। विचार मनुष्य को बांधता है। जिस मनुष्य ने विचारों को वश में कर लिया है, वह इस धरती पर साक्षात भगवान है।

आस्था-अनास्था

समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद्

मेष राशि का मंगल देगा सफलता और संपत्ति

मंगल के मेष राशि में होने पर बारह राशियों पर क्या प्रभाव होंगे?

–अणुव्रत मनोहर, मथुरा

मंगल 11 मई, 2026 को दोपहर 12.47 बजे मीन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मेष (रुचक योग) में प्रवेश कर चुका है। यहां यह 20-21 जून, 2026 की मध्य रात्रि 12.01 बजे तक गोचर करेगा। मेष राशि के मंगल का बारह राशियों पर प्रभाव :

मेष : आत्मविश्वास, मान सम्मान बढ़ेगा। चल-अचल संपत्ति में निवेश। विवादित मामलों में सफलता मिलेगी।

वृष : कानूनी विवाद। स्वयं तथा घर के सदस्य की स्वास्थ्य समस्या। विरोधी पराजित होंगे।

मिथुन : बड़ा आर्थिक लाभ होगा। विवादित मामलों में सफलता। कुछ महत्वपूर्ण रुके हुए कार्य बनेंगे।

कर्क : कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। आर्थिक लाभ। चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री। घर में मांगलिक कार्य।

सिंह : भाग्य का साथ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। चल-अचल संपत्ति बढ़ेगी।

कन्या : थोड़े संघर्ष के बाद लाभ। आमदनी में वृद्धि। निकट के लोगों से विवाद। दुर्घटना की संभावना।

तुला : नए संबंध बनेंगे। साझेदारी में सफलता। घर में स्वास्थ्य समस्या का समाधान। खर्च की अधिकता।

वृश्चिक : विवाद में सफलता। व्यावसायिक संबंधों में थोड़ा संघर्ष। नए कार्य में निवेश। स्वभाव में उग्रता।

धनु : छात्रों के लिए बेहतर समय। नए संबंध-संपर्क बनेंगे। अतिरिक्त प्रयास से कुछ रुके काम बनेंगे।

मकर : चल-अचल संपत्ति की खरीदारी। कार्यक्षेत्र में तरक्की एवं आर्थिक मामलों में लाभ की स्थिति।

कुंभ : छोटे भाई- बहन की प्रगति। विवादित मामलों में सफलता। पुराने किए कार्यों में सफलता एवं सम्मान।

मीन : आर्थिक लाभ। नए कार्य में पूंजी निवेश। घर में मांगलिक कार्य।

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन–मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें :
धर्मक्षेत्र, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी–24 सी,
फिल्म सिटी, सेक्टर–16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–201301 (उत्तर प्रदेश)

मां भद्रकाली : शिव शक्ति का एक स्वरूप

भद्रकाली जयंती

ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी (13 मई) को भद्रकाली जयंती मनाई जाती है। भद्रकाली, मां काली का सौम्य रूप है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ये सती के कोप से उत्पन्न दक्ष के यज्ञ की विध्वसंक देवी हैं। भद्रकाली युद्ध की देवी हैं। केरल में इन्हें करियम काली देवी के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती हैं।

मां भद्रकाली के चार रूप हैं- दक्षजित, महिषाजित, रुरुजित और दारिकाजित। इनके हर स्वरूप की एक कहानी है।

दक्षजित : शिव-वायु पुराण तथा महाभारत की कथाओं के अनुसार शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष की यज्ञ अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। इससे क्रोधित शिव ने दक्ष को मारने के लिए वीरभद्र और भद्रकाली को अपनी जटाओं से प्रकट किया, इसलिए वीरभद्र को देवी भद्रकाली का भाई माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने दक्ष की रक्षा के लिए वीरभद्र को कैद कर लिया, तब भद्रकाली ने वीरभद्र को भगवान विष्णु से मुक्त करवाया और दक्ष को मारने में उनकी मदद की, जिससे उनका नाम 'दक्षजित' हुआ।

महिषाजित : कालिका पुराण में वर्णन है कि त्रेता युग में भद्रकाली महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थीं। महिषासुर भी तीन हुए हैं। भद्रकाली ने जिसका वध किया, वह दूसरा महिषासुर था। तीसरे महिषासुर ने जानना चाहा कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, तो उसे गौर वर्ण भद्रकाली के दर्शन हुए, जो पूर्व जन्म में क्षीर सागर से प्रकट हुई थीं और देवी ने उसे वचन दिया था कि वह अठारह भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जन्म लेंगी और उसका वध करेंगी। देवी का यह रूप 'महिषाजित' है।

रुरुजित : वराह पुराण के अनुसार जब देवी रौद्री (पार्वती का एक रूप) नीली पर्वत की तलहटी में ध्यान कर रही थीं। उन्होंने राक्षस रुरु के अत्याचार से पीड़ित देवताओं की दयनीय दशा देखी, तो उनके क्रोध की चिंगारी से भद्रकाली का जन्म हुआ। रुरु का वध करने के कारण उन्हें 'रुरुजित' नाम मिला।

दारिकाजित : केरल में देवी की पूजा ज्यादातर 'दारिकाजित' के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है- 'दारिका का वध करने वाली।' मार्कण्डेय पुराण के अनुसार दारिका असुर ने शक्ति के मद में चूर होकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। दारिका के बुरे कर्मों को देखकर, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भद्रकाली को प्रकट किया, इसलिए देवी को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। भद्रकाली ने दारिका को मारने के लिए एक बेताल को अपनी सवारी बनाया और उसका वध किया। हालांकि, दारिका का वध करने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए देवताओं ने शिव से उन्हें शांत करने के लिए कहा। भगवान शिव शिशु रूप में उनके मार्ग में लेट गए। इससे काली की मातृ प्रकृति जाग्रत हो गई और वह शांत हो कर उस स्थान पर बस गईं।

कुरुक्षेत्र में मां भद्रकाली का देवीकूप मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। महाभारत युद्ध से पहले और विजय के पश्चात भगवान कृष्ण पांडवों के साथ यहां पूजा करने आए थे। पांडवों ने विजय के पश्चात अपने घोड़े देवी को अर्पित किए थे। उस दिन से भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर देवी को यहां टेराकोटा और धातु के घोड़े मंदिर में चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में कृष्ण और बलराम का 'मुंडन' संस्कार भी हुआ था।

उड़ीसा में इस दिन को जलक्रीड़ा एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन यहां भगवान जगन्नाथ की प्रतीकात्मक छवियों को जल कुंड या पवित्र तालाब में स्नान करवाया जाता है।

अरुण कुमार जैमिनि

राम से इस दिन मिले हनुमान

बड़ा मंगल (ज्येष्ठ मास)

ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को 'बड़ा' मंगल या 'बुढ़वा' मंगल कहा जाता है। इसके इस नाम के पीछे दो पौराणिक कथाओं का जिक्र मिलता है। एक कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही भगवान राम वन में सीता को खोजते हुए पहली बार हनुमान से मिले थे। इस कारण इस महीने के सभी मंगलवार को 'बड़ा' मंगल के नाम से जाना जाता है।

वहीं दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धारण कर भीम के बल के अभिमान को नष्ट किया था। कालांतर में इसे 'बुढ़वा' मंगल भी कहा जाने लगा। इस दिन हनुमान के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पवन पुत्र को चोला चढ़ाने से हर प्रकार की बाधा दूर होती है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और मध्य क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है।

एक अन्य कहानी के अनुसार एक बार लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र की तबीयत बहुत खराब हो गई। योग्य चिकित्सकों को दिखाने और हर प्रकार के उपाय करने के बाद भी वाजिद अली के पुत्र का रोग ठीक नहीं हुआ, तब किसी ने उन्हें बताया कि अलीगंज में स्थित हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने से उनके पुत्र का रोग ठीक हो जाएगा। वाजिद अली शाह ने अपने पुत्र के लिए वहां जाकर प्रार्थना की। इससे उनका पुत्र ठीक हो गया। इसके बाद नवाब और उनकी बेगम ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो ज्येष्ठ माह में पूर्ण हुआ। तभी से लखनऊ में बड़ा मंगल के दिन भंडारे और गुड़ के प्रसाद वितरण की परंपरा शुरू हो गई।

सूर्य के वृष राशि में आने पर ज्येष्ठ मास का आगमन होता है। ज्येष्ठ का अर्थ है- बड़ा। इस मास में दिन बड़े होते हैं। ज्येष्ठ मास का स्वामी मंगल अग्निकारक है, इसलिए इस मास में भीषण गर्मी पड़ती है। इस माह में जल का विशेष महत्व है। चाहे वह जल-बचाव के रूप में हो या जल-दान के रूप में। इस माह में जल से जुड़े दो विशेष पर्व आते हैं- गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी। इन पर्वों पर पानी से भरा घड़ा, पंखा, छाता, जूते-चप्पल आदि का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है।

ज्येष्ठ मास में ही 'नौतपा' भी पड़ता है। नौ दिन की यह अवधि आमतौर पर मई के अंत और जून की शुरुआत में होती है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इससे धरती पर भीषण गर्मी पड़ती है। इस अवधि में सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। ऐसी मान्यता है कि नौतपा में धरती जितनी तपती है, मानसून में वर्षा उतनी ही अच्छी होती है। सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ नौतपा समाप्त हो जाता है।

इस मास में विष्णु की पूजा के साथ ही गंगा, सूर्य, वरुण और हनुमान की पूजा का भी विशेष महत्व है। एक मान्यता के अनुसार इस महीने में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए।

अश्वनी कुमार

सप्ताह के व्रत-त्योहार

12 मई से 18 मई 2026 तक

12 मई (मंगलवार) : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 02.53 मिनट तक। भद्रा दोपहर 02.53 मिनट तक। पंचक।

13 मई (बुधवार) : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि दोपहर 01.30 मिनट तक। अपरा एकादशी व्रत। भद्रकाली जयंती। पंचक।

14 मई (गुरुवार) : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि प्रातः 11.21 मिनट तक। पंचक समाप्त रात्रि 10.34 मिनट। प्रदोष व्रत। पंच गौड़ों का त्रिदिनात्मक वट सावित्री व्रतारंभ।

15 मई (शुक्रवार) : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रातः 08.32 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी रात्रि 05.12 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक तदनंतर अमावस्या तिथि। मास शिवरात्रि व्रत। वट सावित्री व्रत का द्वितीय संयम। ज्येष्ठ संक्रांति। गंडमूल रात्रि 08.15 मिनट तक। चतुर्दशी तिथि का क्षय।

16 मई (शनिवार) : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि रात्रि 01.31 मिनट तक। शुद्ध ज्येष्ठ अमावस। शनैश्चर जयंती। शनिवारी अमावस। फलहारिणी कालिका पूजन। पंचगौड़ों का वट सावित्री अमावस्या व्रत।

17 मई (रविवार) : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि रात्रि 09.41 मिनट तक। ज्येष्ठ अधिक (पुरुषोत्तम) मास प्रारंभ। प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारंभ। श्री गंगा स्नान प्रारंभ।

18 मई (सोमवार) : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि सायं 05.54 मिनट तक। चंद्रदर्शन।

–पं. ऋभुकांत गोस्वामी

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

वृष : कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ में वृद्धि भी हो सकती है।

कर्क : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है।

सिंह : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी बहुत रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

तुला : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है। तरक्की के साथ किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

वृश्चिक : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। आय में कमी आ सकती है।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। वस्त्रों पर खर्च बढ़ेंगे।

मकर : मन प्रसन्न रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। किसी संपत्ति से आय में वृद्धि हो सकती है। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

मीन : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

12 मई, मंगलवार, **शक संवत्** : 22 वैशाख (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 29 वैशाख मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 24 जिल्काद, 1447, **विक्रमी संवत्** : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 02.53 मिनट तक। विष्कुंभ योग, विष्टि (भद्रा) करण दोपहर 02.53 मिनट तक। चंद्रमा कुंभ राशि में सायं 07.25 मिनट तक उपरांत मीन राशि में।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 02.53 मिनट तक। पंचक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हम अपने जीवन में हनुमान जी की सहायता से क्या लाभ पा सकते हैं? –अखिल, दिल्ली

■ यदि आपके जीवन, जॉब या व्यापार में समस्या आ रही है, तो आप इन पंक्तियों को नियमित पढ़ें– 'बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।' यदि किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, तो इन पंक्तियों का नियमित पाठ करें– 'नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।' यदि जीवन में कोई संकट आ गया है, तो इन पंक्तियों का नियमित पाठ करें– 'संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।' यदि ऐसा लगता है कि साहस की कमी हो रही है या फिर आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो इनका पाठ नियमित करें– 'सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना।'

वर्ग पहेली : 8326

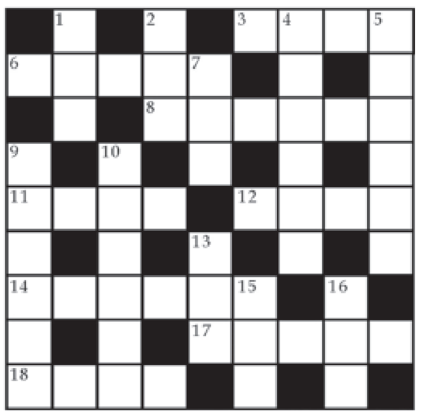

बाएं से दाएं

3 अच्छे विषयों को चुन कर बनाया गया ग्रंथ; संकलित पुस्तक; संग्रह; ढेर (4)
6. आम लोग; जनता; जनसाधारण; सर्वसाधारण (5)
8. बार-बार; रुक-रुक कर (2,2,2)
11. ऊंचा करके बांधना; काम लंबित रखना (4)
12. मोर के पंख; मोर के पंख से बना पंखा (4)
14. अंत कराना; वध करवाना; मरवाना (2,4)
17. तरीका निकालना; रास्ता बनाना; हल निकालना (2,3)
18. नागों का स्वामी; नागपति; नागराज (4)

ऊपर से नीचे

1. तैयार होना; निर्मित होना; पटना; प्राप्त होना (3)
2. कपि; बंदर; मर्कट; वृक्षचर (3)
4. विवाद खड़ा करना; लड़ाई करना (3,3)
5. ध्यान रखना; कृपादृष्टि रखना; मेहरबानी रखना (3,3)
7. झेलना; बर्दाश्त करना; सहन करना; फल भोगना (3)
9. कलेजा कांपना; भयभीत हो उठना; भय से चित्त डांवाडोल होना (2,4)
10. उन्नति करना; प्रगति करना; प्रसार करना; फैलना; बढ़ना; विस्तार करना; वृद्धि करना (3,3)
13. जिसका जीवन अनिश्चित और आचरण अवांछनीय हो; जो व्यर्थ घूमता रहे; निकम्मा; पाजी (3)
15. अनुचित रूप से और अकारण; निष्प्रयोजन; वृथा; फिजूल में; बिना किसी बात के (3)
16. कोना; छोर; सिरा; कूल; तीर; तट (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8325

■	1 जा	■	2 र	3 ज	त	4 प	द	5 क
6 ता	न	ना	■	ल	■	र	■	ठि
■	का	■	7 ब	च	त	क	र	ना
8 न	र	9 क	■	र	■	ट	■	ई
म	■	10 म	त	■	11 सै	वा	■	हो
क	■	ल	■	12 बा	■	13 ना	14 प	ना
15 ह	न	न	क	र	ना	■	स	■
रा	■	य	■	बा	■	16 ध	र	ना
17 म	न	न	क	र	ना	■	ना	■

सुडोकू : 8308

* कठिन

	4		1			3		9
	8		9	2		1		
				1	7	6		
9			6		2			7
		6	5	9				
		3		8	6		5	
4		2			1		7	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8307

7	8	5	1	3	2	4	9	6
9	3	4	7	8	6	2	5	1
6	2	1	9	4	5	8	3	7
1	7	3	8	2	4	5	6	9
8	6	2	5	7	9	1	4	3
4	5	9	3	6	1	7	2	8
5	9	7	4	1	3	6	8	2
2	4	8	6	9	7	3	1	5
3	1	6	2	5	8	9	7	4

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

नमते घेण्याची तयारी ठेवावी लागेल

‘इंडियाची इडा’ हा अग्रलेख (११ मे) वाचला. भाजपला ४० टक्के मतेही घेता आली नाहीत, हे खरेच, पण उर्वरित मते विरोधकांच्या स्वतःच्याच कर्माने कशी विखुरली गेली, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता निघून चालली आहे. ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना ही केवळ एका राजकीय पक्षाची सोय नव्हती, तर तो प्रादेशिक अस्मिता टिकवण्यासाठीचा शेवटचा श्वास होता. पण दुर्दैवाने आघाडीची वीण उसवली जात आहे. तमिळनाडूतील काँग्रेस-द्रमुकचा पेच असो किंवा ममता बॅनर्जींची भूमिका, यातून एकच स्पष्ट होते की, विरोधकांना शत्रूच्या ताकदीपेक्षा स्वतःच्या मर्यादांची भीती अधिक वाटते आहे.

संसदेत महिला आरक्षणाच्या आड मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक रोखणे, हा विरोधकांच्या एकीचा अपघाती विजय होता की जाणीवपूर्वक रणनीती, हा प्रश्न आता उपस्थित होतो. जेव्हा संकट अंगाशी येते, तेव्हाच विरोधक ते शिंगावर घेतात, ही त्यांची हतबलता आहे. पण ही शिंगे एकमेकांत अडकली तर भाजपचा झंझावात रोखणे अशक्य आहे. आता प्रश्न केवळ भाजपला हरवण्याचा नाही, तर स्वतःला राजकीय नकाशावरून पुसले जाण्यापासून वाचवण्याचा आहे. ज्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच उरलेले नाही, त्यांनी आता मोठेपणाचा मुखवटा उतरवून नमते घेण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. तमिळनाडूच्या राजकीय नाट्याने हे सिद्ध केले आहे की, विरोधकांचा अहंकार भाजपसाठी सर्वांत मोठे वरदान ठरतो आहे. आता या पक्षांनी स्वतःच्या मर्यादा ओळखून सामूहिक अस्तित्वासाठी एक पाऊल मागे घेण्याचे शहाणपण दाखवावे.

■ **परेश बंग,** मूर्तिजापूर (अकोला)

…अन्यथा भाजपची पीडाच गोड वाटेल

‘इंडियाची इडा’ हा अग्रलेख वाचला. २०२४च्या पीछेहाटीनंतर खडबडून जागा झालेला भाजप आकाश पाताळ एक करून पुढील निवडणुकांच्या नियोजनाला (यात यंत्रणा व निवडणूक आयोग हे नेहमीचे यशस्वी कलाकारही आले!) लागला.

त्याचवेळी विरोधक मात्र काल्पनिक यशाच्या आशेने एकमेकांतच लढण्यात मश्गूल होत मूळ शत्रू विसरले. सत्ताधारी विरोधकांसारखे आक्रमक व तडफदार, तर विरोधक सत्ताधाऱ्यांसारखे अहंकारी व सुस्तावलेले असे आक्रीत भारतात मागील काही वर्षांपासून दिसू लागले आहे. यातून बलाढ्य भाजपसमोर सततच्या पराभवाने नामशेष होत चाललेले दुर्बल विरोधी पक्ष ही भारतीय लोकशाहीसाठी चिंताजनक बाब उद्भवली आहे. विरोधकांचे ऐक्य हा या राजकीय परिस्थितीच्या कोंडीतून एकच मार्ग आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे त्याची ‘इडा’ नाडी काँग्रेसच्या हाती असली तरी निष्क्रियता झटकून लोकांत जाणे व भाजपसमोर कटाक्षाने एकास एकच उमेदवार उभा करणे या इतर दोन नाड्या एकवटल्या नाहीत तर काँग्रेसच्या इडेपेक्षा भाजपची पीडाच मतदारांना गोड वाटत राहील.

■ **अरुण जोगदेव,** दापोली

अहंकार बाळगला, तर पराभव निश्चित

‘इंडियाची इडा’ हा अग्रलेख वाचला. ‘इंडिया’ आघाडीकडे भाजपला रोखण्याची क्षमता आजही आहे, पण त्यासाठी अहंकार सोडून राजकीय वास्तववाद स्वीकारणे गरजेचे आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३६.५ टक्के मते मिळाली. सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवूनही ४० टक्क्यांचा टप्पा गाठता आला नाही. याचाच अर्थ ६० टक्क्यांहून अधिक जनता आजही भाजपच्या विरोधात आहे. एका सामान्य मतदाराला पर्याय हवा आहे. पण विरोधकांचा अहंकार त्याला तो देत नाही. ही ६० टक्के मते विखुरलेली राहणे हाच भाजपच्या विजयाचा खरा मार्ग आहे.

विरोधकांनी एक साधे व्यावहारिक सूत्र पाळणे आवश्यक आहे. जिथे काँग्रेस मजबूत तिथे त्यांनी लढावे, जिथे प्रादेशिक पक्ष मजबूत तिथे काँग्रेसने मोठेपणा दाखवून मागे राहावे. तमिळनाडूत काँग्रेसने टीव्हीकेबरोबर सरकार स्थापन केले. हा वास्तववादी निर्णय आहे. असाच वास्तववाद संपूर्ण आघाडीने राष्ट्रीय पातळीवर दाखवला, तर ६० टक्के मतदारांना एकसंध पर्याय देणे शक्य आहे. भाजप आधी प्रादेशिक पक्षांशी युती करतो, त्यांची मते वळवतो आणि नंतर त्यांनाच संपवून सत्ता काबीज करतो. एखाद्या प्रादेशिक पक्षाचा मतदार आज एनडीएमध्ये आहे, उद्या तो थेट भाजपचा होतो हे त्या मतदाराला समजते तेव्हा उशीर झालेला असतो. प्रादेशिक अस्मितेला भाजप दीर्घकाळ जगू देत नाही हा इतिहास आहे. जोपर्यंत विरोधक विखुरलेले राहतील, तोपर्यंत भाजप ३७ टक्के मते घेऊनही सत्ता उपभोगत राहील. इतिहास साक्ष आहे की सत्ता बदलते ती विचारांनी नाही… तर एकजुटीने! अहंकार सोडला नाही, तर ‘इंडिया’ आघाडी फक्त नावापुरतीच राहील आणि तो पराभव मतपेटीचा नाही, स्वतःच्या अहंकाराचा असेल!

■ **संदीप देवरे,** कांदिवली (मुंबई)

भाजपला चरफडण्याशिवाय पर्यायच नाही!

‘काँग्रेस विरोधातून भाजपचा विजयला धडा’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला (लोकसत्ता - ११ मे). नुकत्याच झालेल्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसने ५५ वर्षांची द्रमुकची साथ सोडून सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) या पक्षाला पाठिंबा दिल्याने भाजपचा व काँग्रेसच्या हितशत्रूंचा पोटशूळ उठला आहे किंबहुना त्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही!

काँग्रेसने द्रमुकच्या पाठीत खंजीर खुपसला असा खोटा गळा पंतप्रधानांनी काढून त्यांनी एकाच वेळी द्रमुकला खिजविण्याचा आणि काँग्रेसला झोडपण्याचा प्रयत्न केला आहे! तात्पर्य काटा द्रमुकला, आक्रंदने मात्र मोदी आणि भाजपचे सुरू झाले आहे! जातीयवादी व प्रतिगामी शक्तींविरोधात लढण्यासाठी जे सज्ज आहेत अशा समविचारी पक्षांशी मैत्री करणे मुळीच गैर नाही! काँग्रेसने सत्तेसाठी आपल्या सिद्धांतांशी तडजोड केलेली नाही! भाजपला चरफडण्याशिवाय आणि हात चोळत बसण्याशिवाय काही पर्यायच उरला नाही! त्यातूनच मोदींची आणि भाजपची आदळआपट सुरू झाली आहे. यावरूनच मोदी व त्यांच्या भाजपला आजही काँग्रेसचे भय किती आहे याचाच प्रत्यय येतो.

■ **श्रीकांत जाधव,** अतीत (सातारा)

प्रकल्प उभारणे म्हणजे विकास नव्हे

‘न ही ज्ञानेन सदृशं…’ या लेखातून धरणग्रस्तांच्या वेदना, विस्थापन आणि विकासाच्या नावाखाली झालेल्या मानवी संघर्षाचे वास्तव प्रभावीपणे मांडले आहे. मोठे प्रकल्प, धरणे आणि औद्योगिकीकरण यामुळे देशाचा विकास झाला, हे जरी खरे असले तरी त्याची सर्वाधिक किंमत गाव, जमीन, संस्कृती आणि उपजीविका गमावणाऱ्या धरणग्रस्तांनीच चुकवली आहे. विशेषतः कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा इतिहास पाहिला, तर आजही अनेक कुटुंबे पुनर्वसन, रोजगार, जमीनहक्क आणि मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करताना दिसतात.

कोयना धरणामुळे हजारो कुटुंबांचे विस्थापन झाले. अनेकांना स्थलांतरित गावांमध्ये शेतीयोग्य जमीन मिळाली नाही. काही ठिकाणी पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव आजही जाणवतो. अनेक धरणग्रस्तांनी आपल्या सुपीक जमिनी, देवस्थाने, सामाजिक नाती आणि सांस्कृतिक ओळख गमावली; मात्र बदल्यात अपेक्षित स्थैर्य मिळाले नाही. काही संशोधन अहवालांनुसार, पुनर्वसित भागांतील अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा कमकुवत झाली असून युवकांचे स्थलांतर वाढले आहे.

मानसिक आणि सामाजिक विस्थापनाचाही मोठा प्रश्न आहे. पिढ्यान् पिढ्या ज्या मातीत आयुष्य गेले, त्या भूमीपासून दूर जाण्याची वेदना आजही अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या बोलण्यातून जाणवते. विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा सहभाग, सन्मानजनक पुनर्वसन आणि दीर्घकालीन उपजीविकेची हमी या बाबी अनेकदा दुय्यम ठरल्या.

आज हवामान बदल, पाण्याचे वाढते संकट आणि पर्यावरणीय असमतोल यांच्या पार्श्वभूमीवर विकासाच्या मॉडेलकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे. केवळ मोठे प्रकल्प उभारणे म्हणजे विकास नव्हे; तर त्या विकासात स्थानिक माणूस, पर्यावरण आणि सामाजिक न्याय यांना समान स्थान मिळणे आवश्यक आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा अनुभव हा भविष्यातील विकास धोरणांसाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे. विकास मानवी चेहऱ्याचा आणि संवेदनशील असलाच पाहिजे, अन्यथा प्रगतीच्या नावाखाली सामान्य माणूस कायमच उपेक्षित राहील.

■ **डॉ. किरण अजेटराव,** सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)

भाजपने अंग, बंग, कलिंग कसे जिंकले?

पूर्व भारत आता राजकीयदृष्ट्या एक झाला आहे. ही राजकीय एकता विकासात रूपांतरित होणार का, याची प्रतीक्षा येथील जनता प्रदीर्घ काळापासून करत आहे?

प्रेम शुक्ला
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पक्ष

पहिली बाजू

भारताचा भाग्योदय हा पूर्वेकडून होणार आहे. अंग, बंग, कलिंग हे एकत्रितपणे भारताच्या भविष्याचे शिल्पकार असतील आणि यामुळे भारताची वाटचाल आता विकसित देश होण्याकडे सुरू झाली आहे. पूर्व भारतामध्ये एक विशिष्ट खाद्यसंस्कृती आहे जी तुम्हाला पूर्व भारतातील राज्ये, त्यांची गुण-वैशिष्ट्ये, येथील नागरिकांची स्वभाव वैशिष्ट्ये, येथील प्रादेशिक अस्मिता याबद्दल सर्वकाही सांगते.

बिहारमधील ‘लिट्टी-चोखा’ हा खाद्यपदार्थ इथल्या लोकांच्या संघर्षाचे आणि कष्टाचे प्रतीक आहे. बंगालमधील प्रसिद्ध ‘मिश्टी दोई’ हा पदार्थ संयमाचे प्रतीक आहे. ओडिशात प्रसिद्ध असलेला आणि पवित्र मानला गेलेला ‘दालमा’ हा पदार्थ जगन्नाथ मंदिरात येणाऱ्या भाविकांचे वर्षानुवर्षे पोषण करतो. तो सामाजिक एकता आणि प्राचीन संस्कृतीचे प्रतीक आहे. हे तीनही पदार्थ म्हणजे पूर्व भारताचा आत्मा आहेत जे या प्रदेशातल्या संस्कृतीच्या मुळांशी घट्टपणे जोडलेले आहेत.

वर्ष २०२६ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने पूर्वेकडच्या या भारतीय भाषांवर प्रभुत्व मिळवले आणि पूर्वेनेही भारतीय जनता पक्षाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पूर्वेकडील या तीन राज्यांमध्ये पक्षविस्तार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी या धोरणाचा उल्लेख पूर्वेकडील ‘त्रिशक्ती’ असा केला होता. भाजपचे हे ‘अंग-बंग-कलिंग’ मिशन आता पूर्ण झाले आहे. बिहारमध्ये रालोआ भक्कमपणे सत्तेत असताना, ओडिशामध्ये मागील निवडणुकांमध्येच भाजपाने यश मिळवले. आता पश्चिम बंगालमधील ऐतिहासिक विजयानंतर, भाजपाचा भगवा नकाशा भारताच्या संपूर्ण पूर्व किनारपट्टीवर विस्तारला आहे. पूर्व भारतातल्या राज्यांमध्ये भाजपाने जे नेत्रदीपक यश मिळवले आहे त्यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मिळवलेला विजय सर्वांत उठून दिसतो. हा एक असा ऐतिहासिक विजय होता ज्याने या राज्याचा संपूर्ण राजकीय इतिहासच बदलून टाकला.

अनेक वर्षांपासून बंगालमधील भाजप कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे काम करताना राजकीय हिंसाचार आणि धमक्यांना तोंड दिले आणि वेळप्रसंगी प्राणही गमावले. या प्रतिकूल परिस्थितीतही भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक बूथ आणि प्रत्येक गावात कमळ जिवंत ठेवले. ज्या भूमीवर पिढ्यानपिढ्या विचारधारांची तीव्र लढाई सुरू होती तिथे पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार स्थापन झाले आणि बंगालच्या सत्तेवर कमळ फुलले. पश्चिम बंगालमधील विजय हा एका प्रचंड मोठ्या राजकीय यशाचे प्रतीक आहे. या विजयाकडे बघताना केवळ जिंकलेल्या जागांचे आकडे बघून या विजयाचे मूल्यमापन करता येणार नाही, हा विजय समजून घ्यायचा असेल तर या यशामागे दडलेल्या असंख्य माणसांच्या संघर्षकथा, असंख्य कार्यकर्त्यांचे बलिदान आणि पूर्व भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विकासाची आश्वासने हे सर्व काही समजून घेणे आवश्यक आहे.

महाभारतातील महान धनुर्धर कर्णाचे राज्य असलेला प्राचीन ‘अंग’ देश म्हणजेच आजचे बिहार राज्य. युती आणि आघाडीच्या राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणजे बिहार अशी ओळख या राज्याची होती. अनेक राजकीय चढउतारानंतर विकासाचे स्वप्न आणि कायदा-सुव्यवस्था असलेले सुशासन यावर बिहारच्या जनतेने विश्वास दाखवला. डबल इंजिन सरकारच्या नेतृत्वाखाली बांधण्यात आलेले रस्ते आणि पूल या माध्यमातून झालेला विकास आणि विरोधी पक्षांच्या घराणेशाहीच्या राजकारणाबद्दल मतदारांच्या मनात असलेला तीव्र असंतोष या दोन मुद्द्यांवर बिहारमधील ही निवडणूक लढवली गेली. बिहारच्या मतदारांनी मतपेटीतून एक थेट प्रश्न विचारला होताः तुमच्या सरकारमुळे माझे आयुष्य बदलले का? आणि बहुतांश मतदारसंघांतून त्याचे उत्तर ‘हो’ असेच आले. पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेसवेमुळे सुधारलेली दळणवळण व्यवस्था, शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचलेल्या ‘पीएम आवास’, ‘जल जीवन मिशन’ यासारख्या केंद्र सरकारच्या योजना आणि जातीपातीच्या गणितांपेक्षा रोजगार मिळवण्यासाठी उत्सुक असलेला तरुण मतदार, या सर्वांनी मिळून रालोआची पकड मजबूत करण्यास हातभार लावला. बिहार ही ती ‘कोळशाची शेगडी’ ठरली, ज्यावर भाजपची पूर्व भारताच्या विजयाची भाकरी भाजली गेली.

जर बिहार म्हणजे धगधगती आग होती, तर ओडिशा म्हणजे संयमाची परीक्षा होती. ज्याप्रमाणे ‘दालमा’ मंद आचेवर शिजत असताना त्यातील पदार्थ एकजीव होऊन एक अप्रतिम चव निर्माण करतात, तसेच ओडिशामध्ये भाजपचे राजकीय परिवर्तन अत्यंत पद्धतशीर आणि नियोजनबद्ध होते. एकेकाळी नवीन पटनायक यांचा अभेद्य बालेकिल्ला मानले जाणारे हे राज्य अतिशय शांत आणि भक्कमपणे भाजपच्या धोरणांना साथ देत गेले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीने ओडिशामध्ये एक निर्णायक कौल दिला. सत्तेत येताच केवळ दोन वर्षांत ओडिशामधील भाजप सरकारने ‘डबल-इंजिन’ सरकारचा नेमका अर्थ काय असू शकतो हे औद्योगिक विकासामध्ये पिछाडीवर असलेल्या राज्यासाठी दाखवून देण्यास सुरुवात केली आहे.

ओडिशाची निवडणूक प्रामुख्याने आदिवासींचे कल्याण, खाणकाम रॉयल्टीचा मुद्दा आणि पुरीला जागतिक दर्जाचे वारसा व आध्यात्मिक पर्यटन स्थळ बनवण्याच्या आश्वासनावर लढली गेली. कलिंगाचा गौरवशाली वारसा, कोणार्क सूर्यमंदिराचे महात्म्य आणि ओडिया अस्मितेचा हुंकार देऊन भाजपने ओडिया अभिमानाला साद घातली. हे भावनिक आवाहन विरोधकांच्या पटनायक काळातील आठवणी जागवण्यापेक्षा जास्त प्रभावी ठरले. ज्या प्राचीन कलिंग भूमीने भीषण रक्तपातानंतर सम्राट अशोकाचे हृदयपरिवर्तन केले होते, त्या भूमीच्या आधुनिक रूपाने परिवर्तनाला आणि विकासाच्या नव संकल्पनांना पसंती दिली. कमळाला रुजण्यासाठी आणि फुलण्यासाठी महानदीच्या खोऱ्यातील सुपीक माती गवसली होती.

…आणि मग वळण आले ते बंगालचे. हे ‘मिष्टी दोई’चे राज्य. वरून गोड वाटणारे, पण आतून आंबवलेले, ज्याला तयार होण्यासाठी अगदी योग्य परिस्थिती आणि वेळेची गरज असते. २०२६ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगालवर मिळवलेला विजय हा जवळून पाहणाऱ्यांसाठी अजिबात धक्कादायक नव्हता कारण तो सहज मिळवलेला विजय नव्हता. या विजयामागे तळागाळात केलेले काम आणि बांधलेली संघटना होती.

सुरुवातीला लोकभावनेचा आदर करणारे ममता बॅनर्जींचे सरकार २०२६ पर्यंत सिंडिकेट राज, निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार, शिक्षक भरतीमधील घोटाळे आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच मागे राहिलेली अर्थव्यवस्था या ओझ्याखाली दबले गेले होते. तरुण बंगाली मतदार या निवडणुकीत निर्णायक घटक ठरला. भाजपने जो ऐतिहासिक विजय मिळवला तो तीन प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित होताा. पहिला- महिलांची सुरक्षा, ज्याची ठिणगी आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार आणि खून प्रकरणाने पडली. दुसरा मुद्दा- गुंतवणूकविरोधी वातावरण संपवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते आणि तिसरा मुद्दा होता बंगालचा सांस्कृतिक अभिमान. हे राजकारण प्रगल्भ आणि सुनियोजित होते. ज्याप्रमाणे योग्य तापमानात रात्रभर ठेवलेले ‘मिष्टी दोई’ व्यवस्थित आंबवले जाते, तसेच बंगालचे राजकीय वळणही अखेर पूर्णत्वास आले. हा पश्चिम बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय ठरला. बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार स्थापन होणे, हे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे प्रदीर्घ काळापासून पाहिलेले स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखेच होते.

‘अंग-बंग-कलिंग’ या प्रदेशांत भाजपने मिळवलेला विजय ही गोष्ट केवळ राजकारणापुरती किंवा निवडणुकांपुरती मर्यादित नाही. हा विजय भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. सुमारे ३० कोटी लोकसंख्या असलेला हा भाग आतापर्यंत आपल्या विकासाच्या क्षमतेला न्याय देऊ शकलेला नाही. पूर्व भारताला देशाच्या विकासाचे नवे इंजिन बनवणे हा भाजपाचा ‘पूर्वोदय’ विचार राहिलेला आहे. या संकल्पनेला आता तिन्ही राज्यांमध्ये एकाच वेळी राजकीय बळ मिळाले आहे. पूर्वोदयाचा विचार प्रत्यक्षात येताना तीन राज्यांमधील औद्योगिक कॉरिडॉरचा विकास अधिक वेगाने होऊ शकेल. हल्दिया, पारादीप आणि गंगा नदीतील अंतर्गत जलमार्गांना जोडणारे एकत्रित बंदर आणि लॉजिस्टिक धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत मिळेल आणि तिन्ही राज्यांत ‘रालोआ’ सरकार असल्याने, धोरणांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल, केंद्रीय निधीचा ओघ वाढेल आणि राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ मिळेल. बंगालमधील कामगार संघटनांचा अतिआक्रमकपणा आणि बिहारमधील प्रशासकीय उणिवा यामुळे दीर्घकाळ लांब राहिलेला गुंतवणूकदार, आता अखेर पूर्व भारताकडे गुंतवणुकीचे हब म्हणून पाहू शकतो.

कोलकाता-रांची-पटना हा औद्योगिक त्रिकोण, पूर्व जलमार्ग कॉरिडॉर आणि प्रस्तावित ‘बंगाल कोस्टल इकॉनॉमिक झोन’ यांसारख्या प्रत्येक प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे. विजयाचा हा उत्सव साजरा करताना, भाजपने दिलेल्या आश्वासनांचा व्याप किती मोठा आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात जे घडले आहे ते खरोखर ऐतिहासिक आहे. पहिल्यांदाच उत्तर बिहारमधील हिमालयाच्या पायथ्यापासून ते पूर्व किनारपट्टीवरील ओडिसाच्या चिल्का सरोवरापर्यंत आणि उत्तर बंगालमधील चहाच्या मळ्यांपासून ते सुंदरबनच्या खारफुटीच्या जंगलांपर्यंत- संपूर्ण पूर्व किनारपट्टीवर एकाच राजकीय शक्तीची सत्ता आहे.

ज्या पूर्व भारताच्या संस्कृतीने भारताला भगवान बुद्ध, सम्राट अशोकाची करुणा, चैतन्य महाप्रभूंची भक्ती, टागोरांचा मानवतावाद आणि विवेकानंदांचे प्रखर तेज दिले, तो प्रदेश आता राजकीयदृष्ट्या एक झाला आहे. परंतु, ही राजकीय एकता विकासात रूपांतरित होणार का, ज्याची इथली जनता प्रदीर्घ काळापासून प्रतीक्षा करत आहे? कमळ केवळ भाजपच्या बॅनरवरच फुलणार की दरभंगाचा शेतकरी, मुर्शिदाबादचा विणकर आणि पुरीतील कोळी महिला यांच्या आयुष्यातही समृद्धी आणणार? हा तो प्रश्न आहे. ज्याचे योग्य उत्तर येणारा काळ देईल. पूर्व भारताने आपले मत दिले आहे. आता तो प्रतीक्षा करत आहे. बंगालच्या संयमी व गुंतागुंतीच्या मिष्टी दोईप्रमाणे, वेळेनुसार त्यांनाही समजेल की दिलेले आश्वासन खरे होते की होता केवळ वरवरचा गोडवा…

कुतूहल

दिवस लहान-मोठे का होतात?

हिवाळ्यात सकाळी उशिरापर्यंत उजाडत नाही, तर उन्हाळ्यात भल्या सकाळी स्वच्छ ऊन पडलेलं दिसतं, तसंच हिवाळ्यात फार लवकर अंधार पडतो, पण उन्हाळ्यात मात्र बऱ्याच उशिरापर्यंत उजेड राहतो हा आपला नेहमीचा अनुभव आहे.

महाराष्ट्र उष्ण कटिबंधात असल्यामुळे आपल्याला दिवसाची ही लांबी फारशी बदलत नाही. महाराष्ट्रात, उन्हाळ्यात सर्वांत मोठा दिवस १३ तास १८ मिनिटांचा आणि हिवाळ्यात सर्वांत लहान दिवस दहा तास ४२ मिनिटांचा असतो. विषुववृत्तापासून आपण दूर, उत्तरेकडे वा दक्षिणेकडे जाऊ लागतो तसतसा उन्हाळ्या-हिवाळ्यातल्या दिवसाच्या लांबीचा फरक वाढत जातो. ध्रुव प्रदेशात तर महिनोनमहिने हिवाळ्यात सूर्य उगवत नाही आणि उन्हाळ्यात तो मावळत नाही.

हे असं का होतं याचं कारण एकच आहे. पृथ्वीचा स्वतःभोवती फिरण्याचा अक्ष तिच्या कक्षेच्या पातळीशी काटकोनात नसून सुमारे साडेसहासष्ट अंशाच्या कोनात कललेला आहे आणि तो अवकाशातल्या अनंत अंतरावर असलेल्या एका बिंदूकडे रोखलेला आहे. हा बिंदू ध्रुवताऱ्याच्या जवळ आहे. पृथ्वी अशी एकाच दिशेने कलून सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालत असल्याने जून महिन्याच्या शेवटी पृथ्वीचा उत्तर ध्रुव सूर्याकडे झुकलेला असतो आणि दक्षिण ध्रुव सूर्यापासून दूर सावलीत असतो. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटी परिस्थिती त्याच्या उलट असते. दक्षिण ध्रुव सूर्याकडे कललेला असतो आणि उत्तर ध्रुव सावलीत असतो. सूर्याच्या या आकाशातल्या प्रवासाला आपण ‘उत्तरायण’ आणि ‘दक्षिणायन’ म्हणतो. याच्या मोजमापाला ‘स्पष्टक्रांती’ किंवा ’क्रांती’ अशी संज्ञा वापरतात. सूर्याच्या आकाशीय विषुववृत्तापासूनच्या कोनीय अंतराला क्रांती म्हणतात. त्यामुळे २१ जूनला सूर्याची क्रांती उत्तरेला सर्वांत जास्त म्हणजे २३.५ अंश उत्तर इतकी असते. २० मार्च आणि २३ सप्टेंबर या तारखांना ती शून्य होते आणि २१ डिसेंबर रोजी ती २३.५ अंश दक्षिण इतकी असते. परिणामी २१ जूनला सूर्यप्रकाश ६७.५ अंश उत्तर या अक्षांशापासून उत्तर ध्रुवापर्यंत २४ तास दिसत राहतो. त्यापूर्वी आणि त्यानंतर असा २४ तासांचा दिवस हळूहळू अधिकाधिक उत्तरेच्या अक्षांशावरून दिसत राहतो आणि २० मार्च आणि २३ सप्टेंबर या तारखांना उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत संपूर्ण जगभर दिवस आणि रात्र यांची लांबी सारखीच म्हणजे १२ तास असते. २१ डिसेंबरला ६७.५ अंश दक्षिण अक्षांशापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत २४ तास सूर्यप्रकाश दिसतो. सूर्याची क्रांती उत्तरेला असेल तेव्हा उत्तर गोलार्धात उन्हाळा, दक्षिणेला असेल तेव्हा दक्षिण गोलार्धात उन्हाळा असतो.

– सुनील सुळे
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

कुठेही काय डायलॉगबाजी?

अहो, थलपती! *पहिल्याच प्रयत्नात नेत्रदीपक विजय मिळाला म्हणून उगीच हुरळून जाऊ नका. सत्ताकारण करतानाचे संवाद आणि सिनेमातील संवाद यात जमीन अस्मानचा फरक आहे, हे आधी लक्षात घ्या. तिथले पटकथाकार वेगळे. ते मोबदला घेऊन हवे तसे संवाद लिहून देतात. इथे तसे नाही. राजकारणात कोण कुणाची पटकथा लिहील व कोण कुणाला अडचणीत आणेल हे अनेकदा कळतही नाही. तुम्ही मुख्यमंत्री झालात याचा आनंदच आहे पण मीच सत्ताकेंद्र, उजवीकडे, डावीकडे, मागे-पुढे असे काहीच नसेल हे तुमचे वाक्य विजयाचा उन्माद दर्शवणारे. मुख्यमंत्री म्हणजे सिनेमाचा नायक नाही. आजवर तुमचे नायकपण खपून गेले. तीन तासांच्या चलचित्रातल्या समस्या चुटकीसरशी सोडवता येणे सोपे. कारण नायक कधी हरत नसतो. मात्र राजकारणाचे तसे नाही. इथे लोक ज्या वेगाने डोक्यावर घेतात त्याच वेगाने खाली आपटतात. एमजीआर, करुणानिधी, जयललिता यांचे पराभव ठाऊक आहेत ना तुम्हाला? नसेल तर इतिहासाची पाने चाळा! सत्ताकारण वास्तवातल्या सिनेमासारखे असते. अशी डायलॉगबाजी तिथे चालत नाही. तुमच्या टीममधील सर्वांनी चांगली कामगिरी केली तरच तुम्ही यशस्वी ठरता. ती करण्यासाठी जे जे पदावर आहेत त्यांना लोककल्याणाचे अधिकार हवेत. मीच सत्ताकेंद्र असे म्हणून तुम्ही तुमच्याच सहकाऱ्यांची अवस्था दात नसलेल्या वाघांसारखी कराल तर अपयश पक्के समजा.*

नायक मी, मग माझी नायिका कोण, साहाय्यक नायक व खलनायक कोण हे मीच ठरवणार हे सिनेमापुरते ठीक. इथे तुम्ही जे सहकारी निवडले त्यांना वास्तवातला अभिनय कसा करायचा हे सांगत बसू नका. त्यांनाही त्यांच्या त्यांच्या खात्याचे नायक होऊ द्या की जरा! सध्या ते सारे नवखे आहेत म्हणून तुमचे सत्ताकेंद्र खपवून घेतील. एकदा का त्यांना सत्तेची चटक लागली की तेही लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होतील. नेमके हेच तुम्हाला नकोय का? तसे असेल तर तुमच्या नवजात पक्षात बेदिली ठरलेली हे ध्यानात ठेवा. कारण त्यांच्यावर एक मोठा राष्ट्रीय पक्ष डोळा ठेवून बसलाच आहे. आजवर तुम्ही अनेक पटकथाकारांबरोबर बैठका केल्या असतील पण राजकारणात तुम्हाला यशस्वी करण्यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रशासनाची पटकथा कुणीच ऐकवली नसेल. ती आहेच गुंतागुंतीची. राजकारणातले नायकपण हे सर्वांच्या साथीने सिद्ध होत असते. सध्या तुमच्या ‘गोट’ सिनेमातील एक चित्रफीत प्रचंड व्हायरल होतेय. त्यात तुमच्या वाहनाचा क्रमांक टीएन-सीएम-२०२६ असा आहे. याच्याच प्रेमात पडून लोकांनी बसवले तुम्हाला खुर्चीवर. आता त्यांना बसणारे वास्तवातले चटके दूर करण्यासाठी ‘मी तुमच्यातलाच’ म्हणून काम करावे लागेल. त्यासाठी भाषा सौजन्याची हवी, अहंकाराचा दर्प येणारी नको.

सत्ताकेंद्र न बोलता निर्माण करायचे असते. विजय मिळवल्यावर राज्यपालांनीच तुम्हाला पहिला झटका दिलाच ना! राजकारण ही अडथळ्याचीच शर्यत असते. तेव्हा यातून सावध व्हा व लोकप्रिय होण्यासाठी अशी संवादफेक करू नका. तुम्हाला विजय अजूनही स्वप्नवत वाटत असेल तर काहीही बोलण्यापूर्वी एकदा अंगाला चिमटा काढा. भानावर येण्यासाठी अशी कृती केव्हाही चांगली.

राजवाडे विचारविश्व

सरकारांचे व शेजवलकरांचे ग्रंथलेखन

राजवाडे यांनी साधनसंग्रहाच्या पहिल्या खंडाला जी पल्लेदार, विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना लिहिली, तिचा समकालीनांवर मोठा प्रभाव पडला. ऐतिहासिक साधनांच्या स्वदेशी अभ्यासाला व संशोधनोत्तर अन्वयार्थ मांडणीला कोणती वैचारिक, शास्त्रशुद्ध शिस्त हवी, याचे मार्गदर्शन तर त्या प्रस्तावनेमुळे झालेच; पण मराठ्यांच्या स्वराज्यसाधनेवर व विस्तारावर पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून आगपाखड करणाऱ्या अनेक लब्धप्रतिष्ठितांना खणखणीत उत्तरही त्यामुळे मिळाले होते. ‘बारा महिन्यांपैकी आठ महिने मराठी सैन्याने परकीय देशांत चरावे व त्या प्रांतातील लोकांना लुटावे, हाच एक उद्देश शिवाजीने आपल्या लोकांना घालून दिला होता’, असे यदुनाथ सरकारांसारख्या ज्येष्ठ इतिहासकारांनी ‘मॉडर्न रिव्ह्यू’मधील ‘लेसन्स फ्रॉम दि करीअर ऑफ शिवाजी’ या लेखात म्हटले होते; परंतु त्यांचे ते म्हणणे किती विपर्यस्त होते, हे सप्रमाण सिद्ध करून राजवाड्यांनी मराठ्यांच्या इतिहासाच्या दृष्टीने मोलाची कामगिरी पार पाडली होती, हे निःसंशय!

तथापि याचा अर्थ असा नाही की, राजवाड्यांच्या त्या प्रस्तावनेतील विवेचनावर किंवा त्यांच्या भूमिकेवर कुणी आक्षेपच घेतले नाहीत. काही तारखा, काही स्थलनामे वगैरे बाबतीतल्या तर दुरुस्त्याही झाल्याच; परंतु आज इतिहासाचार्यांची स्मृतिशताब्दी साजरी करीत असताना आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की, पुढे जवळजवळ ५० वर्षे पानिपतच्या त्या तिसऱ्या युद्धाबद्दलचे संशोधनपर लेखन फारसे प्रसिद्धच झाले नाही. एकतर काही स्फुट विवेचनात्मक लेख प्रसिद्ध झाले किंवा कादंबऱ्या, नाटके, काव्ये मिळून दहा-बारा ललित साहित्यकृती प्रसिद्ध झाल्या. शिवाय अपुऱ्या साधनसामग्रीच्या कारणास्तव राजवाड्यांनी जरी आपली पानिपत-मीमांसा अर्धवटच सोडून दिली असली, तरी मोगलाईच्या ऱ्हासपर्वाचा इतिहास लिहिण्याच्या ओघात जदुनाथ सरकार यांनी दुसऱ्या खंडात केलेले सुमारे दोनशे पृष्ठांचे पानिपतविषयक विवेचन अभ्यासकांसमोर प्रश्न उभे करत होतेच. त्यांच्या त्या विवेचनासाठी त्यांनी मूळ फार्सी साधने अभ्यासल्यामुळे आणि ती साधने इतर अभ्यासकांनी वापरलेली नसल्यामुळे बरीच नवी माहिती उपलब्ध झाली, मराठ्यांच्या शत्रुपक्षाकडची माहिती विशेष महत्त्वाची ठरली. तथापि त्याच वेळी जदुबाबूंनी मराठी साधनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे (त्यांना मराठी भाषेचे चांगले ज्ञान नसतानाही त्यांनी मराठेशाहीबद्दल दडपून केलेली विधाने वर्षानुवर्षे ग्राह्य मानली जात आली, कारण ती साहेबी इंग्रजीमध्ये केलेली असत, ही बाब मुद्दाम नोंदवण्याजोगी) आणि भूगोलाच्या व विशेषतः नकाशांच्या सूक्ष्म अभ्यासाचा अभाव असल्यामुळे त्यांच्याकडूनही स्थलनामांमध्ये व प्रत्यक्ष लढाईतील डावपेचांच्या वर्णनांमध्ये चुका झाल्या; शिवाय मराठे व त्यांच्या बखरी यांना एक नियम, तर मुसलमान व त्यांच्या बखरी यांना दुसरा नियम असा पक्षपातही त्यांनी केला.

या सर्व पार्श्वभूमीवर १९४६ साली पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजने प्रा. त्र्यं. शं. शेजवलकर यांचा पानिपतवरचा ग्रंथ प्रकाशित केला आणि ऐतिहासिक अन्वयार्थांची एक आगळीवेगळी घुसळणच सुरू झाली. शेजवलकरांनी जरी प्रारंभी मराठीतूनच हा ग्रंथ लिहावयाचा संकल्प सोडला होता, तरी प्रत्यक्षात मात्र तो ग्रंथ इंग्रजीत होता. विशेष म्हणजे त्यांनी त्यासाठी तोपर्यंत उपलब्ध झालेल्या बहुतेक सर्व मराठी, इंग्रजी संदर्भसामग्रीचा तसेच निवडक फार्सी साधनांच्या अनुवादाचाही अभ्यास केला होता. १९३९पासून जवळजवळ सात वर्षे त्यांनी त्याच विषयावर साधकबाधक चिंतन केले होते. त्याला जोड दिली होती ती पानिपतच्या प्रकरणाशी संबंधित असणाऱ्या स्थळांना भेटी देऊन केलेल्या डोळस निरीक्षणांची. त्या ऐतिहासिक घटनाक्रमाचा विविधांगी लेखाजोखा मांडणारा तो ग्रंथही अल्पावधीतच मान्यता पावला, चर्चाविषयही ठरला. अर्थातच राजवाडे यांनी मांडलेल्या काही निष्कर्षांना खोडून काढणारे सप्रमाण विवेचन शेजवलकरांच्या त्या पुस्तकामुळे पुढे आले.

मीमांसा तेथे थांबली नाही. रेंगाळल्यासारखी झाली खरी; परंतु १८६१ मध्ये पानिपतच्या युद्धाची द्विशताब्दी स्मरणपूर्वक साजरी झाली; त्या निमित्ताने शेजवलकरांनीच स्वतंत्रपणे लिहिलेला मराठी ग्रंथ पुण्यातल्या जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन संस्थेने प्रसिद्ध केला. इतरही विद्वान संशोधकांचे अभ्यासपूर्ण ग्रंथ त्याच सुमारास प्रसिद्ध झाले.

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

अदृश्य अर्थदृष्टी

देश म्हणजे एक मोठे कुटुंबच आहे मोदींसाठी. कुटुंबातील सदस्यांनी कसे वागावे, काय करावे, हे मोठ्या हक्काने ते कुटुंब हाकणारा म्होरक्याच ठरवत असतो ना?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचे सर्वात लोकप्रिय राजकीय नेते निःसंशयच. जनतेशी संवादाची उत्तम कला त्यांना चांगलीच अवगत आहे. या अजोड वक्तृत्वशैलीचा खास गुण म्हणजे अगदी भयंकर क्लिष्ट अर्थशास्त्रातील संकल्पनाही माणसाच्या रोजच्या जगण्याशी जोडून ते त्याचा अत्यंत सोपा-सुलभ अर्थ उलगडून सांगतात. आजच्या त्यांच्या उत्तुंग प्रतिमेला साजेशा अन्य अनेक अद्वितीय गुणांतील त्यांच्या ठायी असलेला हा अर्थातच सर्वात मोठा गुणविशेष नक्कीच. रविवारी त्यांनी देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या भाषणाचेच पाहा. अर्थशास्त्रातील 'मॅक्रो' समस्येच्या 'मायक्रो' निवारणाचा मार्ग सांगणारा तो एक मार्मिक दृष्टान्तच म्हणावा.

पंतप्रधान म्हणाले, पेट्रोल-डिझेलादी इंधनाचा वापर जपून करा; इंधन वाचवण्यासाठी घरूनच काम करा. करोनाकाळात जसे काम सुरू होते, त्याप्रमाणे ऑनलाइन बैठका घेऊन कामाची पद्धत पुन्हा राबवण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. घराबाहेर पडलात तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचाच वापर करा; शक्य तेथे रेल्वे, मेट्रोने प्रवास करा. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील वर्षभर सोने खरेदी टाळा. परदेशात सहली, सोहळ्यांचा सोस सोडा. खते, रसायनांचा वापर टाळणाऱ्या नैसर्गिक शेतीची कास धरण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांनाही केले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पश्चिम आशियातील युद्धसंकटाच्या परिणामांपासून वाचवण्यासाठी जनसामान्यांचा सहभाग आणि योगदानाची त्यांनी दिलेली ही हाक आहे. देश म्हणजे एक मोठे कुटुंबच आहे मोदींसाठी. कुटुंबातील सदस्यांनी कसे वागावे, काय करावे, हे मोठ्या हक्काने ते कुटुंब हाकणारा म्होरक्याच ठरवत असतो ना?

पण चांगल्या गोष्टींचा विपर्यास करणे हे टीकाकारांचे कामच. मोदी यांनी मांडलेला दृष्टान्त आणि त्याचे आर्थिक मर्म समजेपल्याड असणाऱ्या कूपमंडुकांचा आपल्याकडे तोटा नाही. अगदी शेअर बाजाराचे म्हणाल, तर सरळपणे सांगितलेल्या गोष्टीतूनही वाकडा अर्थ काढण्याच्या प्रवृत्तीचाच तिथे बोलबाला आहे. 'करोना टाळेबंदीचीच ही नवीन आवृत्ती की काय?' अशी आवई उठवणारे मंदीवाले जणू तेथे टपूनच बसलेले. यातून तिथला निर्देशांक कोसळला आणि गुंतवणूकदारांचे काहीसे नुकसान झाले, तर तो त्याग पंतप्रधानांच्या आवाहनाशी भावनिकदृष्ट्या जोडले गेलेल्यांपुढे कस्पटासमानच.

अगदी ताज्या निवडणुकीत पूर्वेकडील राज्यांमध्ये विरोधी पक्षीयांची अवस्था 'तृणवत' अर्थात गवताच्या काडीसारखी करून ठेवणाऱ्या पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अश्वमेधापुढे या बोलघेवड्या कस्पटांची किंमत ती काय? पाण्यासारखा पैसा उडवलेल्या निवडणुका उरकल्यानंतर आणि त्यात मतदारांना भूल घालणाऱ्या रेवड्या वाटून झाल्यावर आता काटकसरीचा उपदेश तर अत्यावश्यकच ठरतो. आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य लोकांना पटवून देताना, जे जे काही करणे आवश्यक आहे, ते ते पंतप्रधानांनी निःसंकोच सांगितले. अर्थात हे काम अर्थतज्ज्ञांची मदत न घेता आणि आकड्यांची झूल पांघरून न घेता, अगदी सफाईदार व प्रभावीपणे त्यांनी केले याबद्दल खरे तर त्यांचे कौतुकच.

अर्थशास्त्राला पुस्तकी सिद्धांतातून थेट लोकांच्या घर-अंगणात नेण्याच्या त्यांच्या या कसबाचा वेध एकवार घेऊन तर पाहा. अनेक पूर्वग्रह आपोआपच गळून पडतील. वित्तीय तूट, व्यापार तूट, सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) या अंक-आलेखांच्या जंजाळात अर्थतज्ज्ञ तुम्हाला अडकवून ठेवतील. परंतु याच क्लिष्ट गोष्टींची शिकवण देताना, विदेशांतून आयात होणाऱ्या इंधनाबाबत काटकसर, सोने खरेदीचा मोह आवरता घ्या... वगैरे सांगून आता तेच आपले 'राष्ट्रीय धोरण' अशी मोदी सहजतेने मांडणी करतात. 'परदेशांत लग्नाचा थाट कशाला हवाय?' असा प्रश्न करून त्यांनी देशाबाहेर जाणाऱ्या डॉलरला, पर्यायाने अमेरिकी चलनापुढे शंभरीपर्यंत केव्हा ढासळेल अशा स्थितीला पोहोचलेल्या भारतीय रुपयाच्या परवडीला रोखण्याचा बेमालूमपणे धडा दिला.

पण चांगल्या गोष्टींचा विपर्यास करणे हे टीकाकारांचे कामच. मोदींनी मांडलेला दृष्टान्त आणि त्याचे आर्थिक मर्म समजेपल्याड असणाऱ्या कूपमंडुकांचा आपल्याकडे तोटा नाही.

पश्चिम आशियातील युद्ध संकटाच्या परिणामांतून, महाग बनलेल्या आयातीचा वाढता बोजा, ढासळती निर्यात, वेगाने देशाबाहेर पाय फुटत असलेला डॉलर, त्यातून आर्थिक तुटीचे विस्तारत असलेले ठिगळ, परिणामी नवनवीन उंची गाठत असलेला उधार-उसनवारीचा डोंगर, किमती भडकलेल्या खत-इंधनावर सरकारला द्यावे लागत असलेले आणि डोईजड बनलेले अनुदान आणि यातून संथ विकास आणि कोलमडलेला जीडीपी वगैरे आपली लुळी पडलेली आर्थिक आघाडी पंतप्रधानांनी जशीच्या तशी लोकांपुढे न ठेवता हा कावेबाज पवित्रा घेतला. आर्थिक धोरणातील अपयशाचे रूपांतर राष्ट्रीय संकटात करण्याचे आणि त्याचे खापर स्वतःवर न घेता नागरिकांच्या राष्ट्रीय कर्तव्य आणि देशभक्तीशी जोडण्याचा हा एक कावाच, असा विरोधकांचा आरोप. पण तोही उथळ आणि खरे तर अदखलपात्रच. काटकसरीची हाक देऊन, खुद्द पंतप्रधानांनी 'कसर' अर्थात कमतरता, उणीव असल्याची कबुली दिलीच आहे. ती कसर भरून काढण्यासाठी खर्चाला काट म्हणजे कात्री लावावी, इतका हा स्पष्ट अर्थ. तोच अर्थ पुन्हा विस्कटून सांगण्याच्या विरोधकांच्या कर्तबात चातुर्य ते काय?

पेट्रोल-डिझेल इंधनाच्या विक्री करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना त्यांचा कच्चा माल अर्थात आयात होणारे खनिज तेल प्रचंड महागले असतानाही, तयार माल कोणतीही दरवाढ न करता विकायला भाग पडत आहे. महिन्याला ३० हजार कोट वा अधिक नुकसान सोसावे लागत आहे. जागतिक ऊर्जा संकटाचाच हा परिणाम असला तरी जर्मनी वा तत्सम प्रगत देशांनी इंधन हे तात्पुरते का होईना करमुक्त करून लोकांचे किंमतवाढीपासून संरक्षण केले. पण असा काही निर्णय घेणे म्हणजे वेडपणाच. न पेक्षा पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल, खते, रसायनांच्या उपभोगावरच बंधने आणली तर लोकांचे पैसे वाचतील, आयातही कमी करून देशाला वाचवता येईल, हे अधिक परिणामकारक नाही काय?

अर्थशास्त्राला कोरड्या आकडेवारीतून बाहेर काढून, लोकांच्या मन-हृदयाची आर्थिक शिस्तीसाठी घडण करण्याचे वळण देण्याची ही कला खरोखरच अजोड आहे. आधीच वाट्याला चतकोर आलेल्या सामान्य मध्यमवर्ग, पगारदार, कष्टकरी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या इच्छा, आकांक्षांना मुरड घालण्यास सांगणे हे एक खास तंत्रच आहे. ते सहजासहजी नव्हे तर दांडगा अनुभव आणि मेहनतीने अंगी बाणवले जाऊ शकते. निष्णात अर्थवेत्त्यालाही मात देईल असे हे सुलभीकरण आता कुणाच्या पचनी पडो अथवा ना पडो पण ते स्वीकारणे क्रमप्राप्तच. लोकशाही, सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेतील मूल्यऱ्हास, निकृष्टीकरण असे जर कोणी याला म्हणत असेल तर तो त्यांच्या अल्पदृष्टीचा दोष. मोदींचा मंत्र अगदी सुस्पष्ट आहे- 'बचत हेच राष्ट्रीय कर्तव्य आणि स्वदेशीचा मंत्र व आत्मनिर्भरतेच्या या नाऱ्यात खुसपट शोधणारे हे देशद्रोहीच!' संकटकाळातच राजा प्रजेकडे देशप्रेम, बलिदानाची याचना करत असतो. अशा प्रसंगी तार्किक वादाला जागा नसते. म्हणूनच परिणामी बाजारात मागणी कमी होईल, असे म्हणणे अप्रस्तुतच. तशीही अनेक करसवलतींचे उपाय योजूनही मागणी उत्साहवर्धक नव्हतीच. त्या उप्पर देशांतर्गत मागणी-उपभोगावरच आधारित आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली, तरी बेहत्तर. यातून जास्तीत जास्त काय घडेल? गेली काही वर्षे मनी बाळगलेल्या 'पाच ट्रिलियन डॉलर'ची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला मुरड घालावी लागेल. तूर्त हा त्याग देश सहन करेल. मात्र त्याबदल्यात लोकांनीही मग काहीसा त्याग करावाच. सध्याच्या भयंकर उन्हाळ्यात तलावांमधील वेगाने घसरत असलेला पाणीसाठा पाहता, प्रत्यक्ष पाणीकपात करण्याआधी, जसे पाणी जपून वापरा असे पालिकांकडून सांगितले जाते तसेच हे आहे. आगामी महागाई, दरवाढ आणि आर्थिक हलाखीची ही हाळीच असे समजावे आणि आतापासून पूर्वतयारीला लागावे. पण लक्षात ठेवा, दरवाढ, करवाढ होणारच नाही, असे मोदी राजवटीचेच वचन आहे. तथापि स्व-वाट्याला आलेल्या चतकोरातूनही शक्य तितका त्याग मात्र आवश्यकच. त्याग हाच आता नवीन कर समजावा. या त्यागाची सीमा आणि व्याप्ती आपल्या परोक्षच ठरविली जाणार!

तापमानवाढीचे अर्थकारण

लेख

डॉ. नितीन बाबर
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
श्री संपतराव माने महाविद्यालय,
खानापूर, जि. सांगली
nitinbabar200 @gmail.com

यंदा मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच भारतातील अनेक राज्यांमध्ये तापमानाने ४४ ते ४७ अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला आहे. राजधानी दिल्लीपासून गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि विदर्भापर्यंत उष्णतेच्या लाटेने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. हवामान बदलाचा परिणाम भविष्यात दिसेल, अशी एके काळी व्यक्त केली जाणारी भीती आता वर्तमानातील वास्तव बनली आहे. यंदा एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यातच भारतातील वीज मागणीने २५६ गिगावॅटचा विक्रमी स्तर गाठला, जो भारताच्या ऊर्जा इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. वाढते तापमान हा केवळ हवामानाचा प्रश्न नसून ते आर्थिक विकास, सार्वजनिक आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक समता यांच्यासमोरील गंभीर आव्हान बनते आहे. प्रश्न एवढाच नाही की तापमान किती वाढले, तर हा आहे की या तापमानवाढीची किंमत कोण मोजत आहे? अर्थातच शेतकरी, मजूर, शहरी गरीब, विद्यार्थी, वृद्ध, महिला आणि लहान उद्योग हे सर्व घटक या संकटाच्या केंद्रस्थानी आहेत. हे विचारात घेता निसर्गाचा समतोल राखणे ही आता केवळ नैतिक जबाबदारी नसून आर्थिक निकड बनली आहे.

तापमानाचे बदलते स्वरूप

भारतात एप्रिल-मे महिन्यांत उष्णता असणे नवीन नाही; मात्र उष्णतेची तीव्रता, कालावधी आणि भौगोलिक विस्तार चिंताजनक वेगाने बदलत आहे. आंतरराष्ट्रीय हवामान संशोधन मंचाच्या 'क्लायमामीटर'च्या एप्रिल २०२६च्या अहवालानुसार भारतातील एप्रिल २०२६ उष्णतेची लाट ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा सुमारे दोन अंश सेल्सिअस अधिक तीव्र होती आणि तिचा परिणाम सुमारे १४.६ कोटी लोकसंख्येवर झाला. हा बदल केवळ तापमानाच्या आकड्यांत दिसत नाही; रात्रीचे तापमान कमी न होणे ही अधिक गंभीर बाब आहे. विदर्भ, गुजरात आणि उत्तर भारतातील अनेक शहरांमध्ये रात्रीचे तापमान ३० अंशांच्या आसपास नोंदवले गेले. परिणामी शरीराला नैसर्गिक शीतलता मिळत नाही आणि उष्माघाताचा धोका वाढतो. भारतातील शहरीकरण, काँक्रीटीकरण, हरित क्षेत्रांची घट, वाहनांची वाढती संख्या आणि औद्योगिक उत्सर्जन यामुळे ''अर्बन हीट आयलंड'' परिणाम तीव्र होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागापेक्षा शहरे अधिक तापत आहेत. पुणे, नागपूर, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये हा परिणाम स्पष्ट दिसतो. हवामान बदल हा आता भविष्यातील धोका नसून विकासाच्या प्रत्येक समीकरणात समाविष्ट करावा लागणारा वास्तव घटक बनला आहे.

उत्पादन, शेती आणि ऊर्जा क्षेत्रासमोरील संकटे

वाढत्या उष्णतेच्या लाटेचा सर्वाधिक परिणाम देशाच्या उत्पादनक्षमतेवर होत आहे. बांधकाम, वाहतूक, शेती, लघुउद्योग, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची कार्यक्षमता यामुळे मोठ्या प्रमाणात घटते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार उष्णतेमुळे भारतात दरवर्षी अब्जावधी श्रम-तासांचे नुकसान होते. 'लॅन्सेट'च्या अहवालानुसार, अतिउष्णतेमुळे भारतात कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रात दरवर्षी अंदाजे १० ते १५ हजार कोटी मनुष्य-तासांचे नुकसान होत आहे. वाढत्या तापमानामुळे गव्हांच्या उत्पादनात १०-३० टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊन महागाई वाढते. उष्णतेमुळे देशात आधीच सुमारे १५९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतक्या उत्पादकतेचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. शेती क्षेत्रात रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, डाळी, फळबागा आणि भाजीपाला उत्पादनावर उष्णतेचा परिणाम होत आहे. जमिनीतील आर्द्रता कमी झाल्याने सिंचनाचा खर्च वाढतो आहे. पाण्याची मागणी वाढते आहे आणि उपलब्धता कमी होते आहे.

तापमानवाढीचे रोजचे वाढते आकडे हा केवळ हवामानाचा प्रश्न नसून ते आर्थिक विकास, सार्वजनिक आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक समता यांच्यासमोरील गंभीर आव्हान बनले आहे. तापमान किती वाढले हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण त्याची किंमत कोण मोजत आहे, हे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातही या परिस्थितीमुळे प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये भारतातील वीज मागणीने २५६ गिगावॅटचा विक्रम केला. त्याच काळात गुजरातमध्ये राज्यस्तरीय वीज मागणी २५,३६० मेगावॅटपर्यंत पोहोचली. साहजिकच वीज मागणी वाढली की उत्पादन खर्च वाढतो, कोळसा वापर वाढतो, कार्बन उत्सर्जन वाढते आणि पुन्हा हवामान बदल तीव्र होतो हे एक दुष्टचक्र आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे अन्नधान्य पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास बाजारात महागाई वाढते. फळे, भाज्या, दूध आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढण्यामागे वाहतूक खर्च आणि उत्पादन घट ही महत्त्वाची कारणे ठरतात.

गरीब, कामगार आणि आरोग्यव्यवस्था

हवामान बदलामुळे वाढणारे तापमान आता केवळ पर्यावरणीय प्रश्न राहिलेला नाही; तो सामाजिक न्याय, श्रम अर्थकारण आणि सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. भारतासारख्या उष्ण कटिबंधीय देशात त्याचे परिणाम सर्वाधिक गरीब, असंघटित कामगार आणि आधीच ताणाखाली असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर दिसून येत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२४च्या विश्लेषणानुसार, २००० ते २०१९ या कालावधीत जगभर दरवर्षी सरासरी सुमारे ४.८९ लाख उष्णतासंबंधित मृत्यू नोंदवले गेले. यातील जवळपास ४५ टक्के मृत्यू आशिया खंडात झाले आहेत. उष्णतेचा सर्वाधिक परिणाम वृद्ध, बालके, हृदयविकार, मधुमेह आणि किडनीच्या आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींवर होतो. आरोग्य व्यवस्थेवर अचानक वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येचा मोठा दबाव निर्माण होतो.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या २०२४ अहवालानुसार, जगभर ७० टक्क्यांहून अधिक कामगार वर्षातून किमान एकदा अतिउष्णतेच्या धोक्याला सामोरे जातात. शेती, बांधकाम, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक आणि रस्त्यावर व्यवसाय करणारे सर्वाधिक जोखमीच्या गटात आहेत. तापमान ४० अंशांच्या पुढे गेले की मानवी श्रमक्षमता झपाट्याने घटते; परिणामी कामाचे तास कमी होतात, उत्पन्न घटते आणि कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर होतो. एकंदरीतच गरिबांसाठी उष्णता ही केवळ तापमानाची समस्या नसते; ती निवारा, पाणी, रोजगार आणि आरोग्य या सर्वांशी जोडलेली असते. झोपडपट्ट्या, पत्र्याची घरे, अपुरी हवा खेळती व्यवस्था आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा अभाव यामुळे उष्णतेचा परिणाम अनेक पटींनी वाढतो. भारतातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. लॅन्सेटच्या २०२५ अहवालानुसार, भारतातील प्रत्येक व्यक्तीने २०२४ मध्ये सरासरी १९.८ उष्णतेचे दिवस अनुभवले. त्याच वर्षी उष्णतेमुळे भारतात २४७ अब्ज संभाव्य श्रमतासांचे नुकसान झाले, जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे.

वाढत्या तापमानाचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाला बसतो. वातानुकूलन, सुरक्षित निवास, पुरेसे पाणी किंवा आरोग्यसेवा यांची उपलब्धता नसलेला वर्ग अधिक असुरक्षित असतो. बांधकाम मजूर, शेतमजूर, रस्त्यावरचे विक्रेते, डिलिव्हरी कर्मचारी, वाहतूक क्षेत्रातील कामगार यांना काम थांबविणे परवडत नाही. यावर्षी अनेक कंपन्यांनी कामाच्या वेळेत बदल, विश्रांती केंद्रे आणि घरून कामाचे पर्याय लागू केले असल्याच्या बातम्या आहेत. आरोग्य क्षेत्रावरही मोठा दबाव येतो. उष्माघात, डिहायड्रेशन, रक्तदाब, हृदयविकार, मूत्रपिंडाशी संबंधित आजार, त्वचारोग आणि श्वसनाचे त्रास वाढतात. वृद्ध नागरिक आणि लहान मुले विशेषतः जोखमीच्या गटात असतात. शाळा-कॉलेजांचे वेळापत्रक बदलणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, दुपारी सार्वजनिक कार्यक्रम टाळणे अशा उपाययोजना राज्यांना कराव्या लागत आहेत. वाढती उष्णता ही सामाजिक विषमता अधिक तीव्र करते. श्रीमंत वर्गासाठी ती असुविधा असू शकते; गरिबांसाठी ती जगण्याचा प्रश्न बनते.

हवामानस्नेही विकासाची अपरिहार्यता

भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे; मात्र हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या उष्णतेच्या संकटाकडे दुर्लक्ष केल्यास ही प्रगती असमतोल ठरू शकते. उष्णतेच्या लाटा या केवळ तापमानवाढीचा विषय नाहीत; त्या रोजगार, शेती, आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा आणि सामाजिक न्याय यांच्याशी थेट जोडलेल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत उष्णतेमुळे कामाच्या तासांत होणाऱ्या घटीमुळे भारताच्या जीडीपीला सुमारे २.८ ते ४.५ टक्क्यांचा फटका बसू शकतो. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या तापमानाच्या झळा फक्त तात्पुरत्या उपायांनी कमी होणार नाहीत. यासाठी राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल आवश्यक ठरतील. प्रथम, प्रत्येक राज्याने 'हीट ॲक्शन प्लॅन' अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे. उष्णतेचा अंदाज, सार्वजनिक सूचना, पाणी उपलब्धता, आरोग्य केंद्रांची तयारी आणि कामगार संरक्षण यांचा समन्वय हवा. दुसरे म्हणजे शहर नियोजनात हरित पट्टे, जलसंधारण, उष्णता परावर्तित करणारे बांधकाम साहित्य, छतांवरील सौर ऊर्जा आणि पावसाचे पाणी साठवण या उपाययोजना अनिवार्य कराव्या लागतील. तिसरे म्हणजे कृषी क्षेत्राला हवामान-संवेदनशील तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, दुष्काळसहिष्णू बियाणे आणि डिजिटल हवामान सूचना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. चौथे म्हणजे अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. यंदाच्या विक्रमी वीज मागणीत सौर ऊर्जेचे योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे. एकंदरीतच विकासाचा पुढचा टप्पा केवळ जीडीपी वाढीऐवजी नागरिकांना सुरक्षित, शाश्वत आणि हवामानस्नेही जीवन देता येते का, यावर ठरणार आहे. उष्णतेच्या या वाढत्या लाटांच्या माध्यमातून निसर्ग आपल्याला इशारा देत आहे. आता निर्णय आपणच घ्यायचा आहे.

अन्वयार्थ

रोग आणि इलाज

वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागावृद्धीस मिळालेली वाढीव मुभा हा देशातील वैद्यकीय सेवेच्या विस्तारासाठीचा योग्य उपचार, की खासगी महाविद्यालयांच्या नफेखोरीसाठी मोकळे रान मिळाल्याने रोगापेक्षा इलाज भयंकर, याची चर्चा प्रसंगोपात होणारच आहे. सध्या या दोन्ही मुद्द्यांच्या अनुषंगाने त्याची चिरफाड करणे क्रमप्राप्त. देशात पाच राज्यांतील प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना संबंधित निर्णय जाहीर झाल्याने त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. पण, भाषेपासून राज्यांच्या स्वायत्ततेपर्यंत उत्तर-दक्षिण असा जो राजकीय वाद या देशात सुरू असतो, त्याचीही याला किनार आहेच.

ऑगस्ट २०२३ मध्ये वैद्यकीयच्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी (एमबीबीएस) तयार केलेल्या अधिनियमांत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) गेल्या २३ एप्रिलला एक दुरुस्ती अधिसूचना जाहीर करून काही बदल केले. त्यानुसार, एमबीबीएस अभ्यासक्रमांसाठीच्या महाविद्यालयांत जागा वाढवायच्या असतील, तर त्यांची संख्या १५० हून अधिक झाली तरी चालेल. राज्यांसाठी असलेला दहा लाख लोकसंख्येमागे १०० जागा हा निकषही काढून टाकण्यात आला आहे. तसेच, महाविद्यालयापासून संलग्न रुग्णालय अर्ध्या तासाच्या अंतरावर असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ती अटही काढून हे अंतर १० किलोमीटरपर्यंत असेल तरी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन भागांत तर हे अंतर १५ किलोमीटरपर्यंत असले तरी चालणार आहे. जागा वाढविताना महाविद्यालयांना त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची व अन्य बंधने असतीलच, पण त्यावर 'मात' कशी केली जाते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. 'लॅन्सेट' या वैद्यकीय विषयाला वाहिलेल्या नियतकालिकाने मध्यंतरी त्यातील फोलपणा पुरेसा उघडकीस आणला होता.

आधी या निर्णयाची शैक्षणिक बाजू. देशात दरवर्षी जवळपास २४ लाख विद्यार्थी 'नीट' परीक्षा देऊन वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यास इच्छुक असतात. सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांत मिळून 'एमबीबीएस'साठी सध्या जागा आहेत सुमारे सव्वा लाख. म्हणजे, 'नीट' देणाऱ्यांपैकी जेमतेम पाच टक्के विद्यार्थ्यांना 'एमबीबीएस'ला प्रवेश मिळू शकतो. जागा वाढविण्याचे निकष शिथिल केल्याने यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना 'एमबीबीएस'ला संधी मिळेल. देशाला वैद्यकीय तज्ज्ञांची असलेली गरज पाहता, वैद्यकीय शिक्षणाचा पैस वाढविण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न होते, त्या धोरणाशीही हे सुसंगत.

आता याची राजकीय बाजू. ऑगस्ट २०२३ चे अधिनियम जाहीर झाले, त्या वेळेस काँग्रेससह दक्षिणेतील पक्षांनी त्याला विरोध करताना, दर १० लाख लोकसंख्येमागे १०० 'एमबीबीएस'च्या जागा हा नियम जाचक असल्याचे म्हटले. या राज्यांत आत्ताच जागांचे प्रमाण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, पावणेसात कोटींच्या कर्नाटकात ११,६९५, तर ७.६८ कोटी लोकसंख्येच्या तमिळनाडूत ११,६०० 'एमबीबीएस'च्या जागा आहेत. त्यामुळे ऑगस्ट २०२३ चा नियम दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय करणारा असल्याची हाकाटी देण्यात आली. महाराष्ट्रात १० लाख लोकसंख्येमागे १०० जागा यानुसार किमान १३ हजार 'एमबीबीएस'च्या जागा हव्यात, त्या मात्र सध्या पाचच हजारांच्या आसपास आहेत. म्हणजे २०२३ चा नियम ठेवला असता तरी वाढायला मुभा होती, आता तर आणखीनच.

आता याची तिसरी बाजू. 'एनएमसी'ने २०२३ मध्ये प्रवेशासाठी अधिनियम केले, तेव्हा वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाची गुणवत्ता राखावी, हा मुख्य उद्देश होता. 'एमबीबीएस'च्या देशात उपलब्ध सव्वा लाख जागांपैकी निम्म्याहून अधिक खासगी महाविद्यालयांतील आहेत. यांचे शुल्क सामान्यांना न परवडणारे असल्याने एकदा का सरकारी जागा भरल्या, की या खासगी जागा भरण्यासाठी 'नीट'च्या गुणांची जोरदार घसरण सुरू होते. आता निकष शिथिल होऊन जागा वाढल्यावर ती आणखी होईल, ही भीती. आणखी एक धोका म्हणजे 'नीट'च्या अतिशय कमी गुणांना प्रवेश मिळायला सुरुवात झाली, की त्यासाठी बसणाऱ्यांची संख्या आणि पर्यायाने त्यांचे शिकवणी वर्ग घेणाऱ्यांचे पीकही आणखी जोमाने वाढणार. यामुळे गुणवत्तेची बूज राखली जाणार का? शिवाय, शिक्षणासाठी भरलेले शुल्क व्यवसायातून वसूल करायचे तर खासगी आरोग्य सेवा निरंतर महाग होणार, हे आलेच. डॉक्टर अधिक निर्माण व्हावेत, हे आकडेवारी म्हणून सांगायला ठीक, पण त्याने सार्वजनिक आरोग्य; गेला बाजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तरी सुधारावीत, ही अपेक्षा चूक कशी? 'एमबीबीएस'च्या जागा वाढण्याचा प्रशस्त झालेला मार्ग याचे उत्तर देत नाही.

वाघांसाठी 'कॅनाईन डिस्टेंपर' ठरतोय नवा मृत्यूचा सापळा?

विश्लेषण

राखी चव्हाण
rakhi.chavhan@expressindia.com

मध्य प्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातील वाघिणीसह तिच्या पाच बछड्यांच्या मृत्यूनंतर देशभरातील व्याघ्र संवर्धन व्यवस्थेची चिंता वाढली आहे. 'कॅनाईन डिस्टेंपर' या विषाणूमुळे आता वाघांसाठी जंगलातच नवा अदृश्य धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातील घटनेने खळबळ का?

कान्हा व्याघ्र प्रकल्प परिसरात एका वाघिणीसह तिच्या बछड्यांचा 'कॅनाईन डिस्टेंपर' विषाणूमुळे मृत्यू झाल्यानंतर देशातील व्याघ्रसंवर्धन व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. वाघीण आणि बछड्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्यानंतर वनविभागाने त्यांना ताब्यात घेऊन उपचार सुरू केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) सर्व व्याघ्र प्रकल्पांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत. आतापर्यंत शिकारी आणि अधिवास नष्ट होणे हाच वाघांसाठी सर्वात मोठा धोका मानला जात होता. मात्र, आता संसर्गजन्य रोगही मोठे संकट ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

'कॅनाईन डिस्टेंपर' म्हणजे काय? तो किती घातक?

'कॅनाईन डिस्टेंपर' हा विषाणू मुख्यतः श्वानांमध्ये आढळतो. मात्र तो वाघ, बिबट्या, सिंह, लांडगे यांसारख्या मांसाहारी वन्यप्राण्यांमध्येही पसरू शकतो. ताप, अशक्तपणा, डोळे आणि नाकातून स्राव, श्वसनाचा त्रास, असामान्य हालचाली आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम अशी त्याची प्रमुख लक्षणे आहेत. गंभीर संसर्ग झाल्यास प्राण्यांचा मृत्यू होण्याची शक्यता असते. हा विषाणू एका प्राण्यापासून दुसऱ्या प्राण्यात वेगाने पसरू शकतो. विशेषतः एखाद्या वाघिणीला संसर्ग झाल्यास तिच्या बछड्यांनाही तो होण्याची शक्यता अधिक असते. कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातील घटनेने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

या विषाणूचा जीनपूलवर परिणाम होतो का?

एखाद्या व्याघ्र प्रकल्पात एकाच कुटुंबातील अनेक वाघ मृत्युमुखी पडल्यास त्या परिसरातील आनुवंशिक विविधतेवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः बछड्यांची संख्या अधिक असलेल्या वनक्षेत्रासाठी हे दीर्घकालीन संकट ठरू शकते. आफ्रिकेत सेरेन्गेटी परिसरात सिंहांमध्येही 'कॅनाईन डिस्टेंपर'चा मोठा उद्रेक झाला होता. त्यामुळे भारतातील ही परिस्थिती जागतिक संवर्धन आव्हानांचा भाग असल्याचे म्हणता येईल.

जंगलात हा संसर्ग कसा पोहोचतो?

हा विषाणू प्रामुख्याने श्वानांमध्ये आढळतो. मात्र, जंगलालगतच्या गावांमधील पाळीव किंवा भटकी श्वाने वनक्षेत्रात गेल्यानंतर त्यांचा संपर्क वाघ, बिबट, सिंह यांसारख्या मांसाहरी प्राण्यांशी येतो आणि संसर्गाची साखळी तयार होते. मोहफुले, तेंदुपत्ता किंवा इतर वनउत्पादनांच्या हंगामात गावकऱ्यांचा जंगलातील वावर वाढतो. अनेकदा ते सुरक्षेसाठी श्वानांना सोबत नेतात. हे श्वान जंगलातील पाणवठ्यांवर जातात आणि त्याच ठिकाणी नंतर वाघ किंवा इतर वन्यप्राणी येतात. त्यामुळे संसर्गाची साखळी तयार होण्याचा धोका वाढतो, असे ज्येष्ठ वन्यजीवतज्ज्ञ अजय दुबे यांनी नमूद केले आहे. भविष्यात हा धोका अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भारतात याआधीही अशा घटना घडल्या आहेत का?

गीर अभयारण्यात २०१८ मध्ये अनेक सिंहांचा मृत्यू 'कॅनाईन डिस्टेंपर'मुळे झाल्याची नोंद आहे. अधिकृत आकड्यांपेक्षा मृत्यूंची संख्या अधिक असल्याचा दावा काही वन्यजीवतज्ज्ञांनी केला होता. तसेच पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात २०१५ मध्ये एका वाघिणीचा मृत्यू याच विषाणूमुळे झाला होता. भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्थेने २०१२ ते २०१७ दरम्यान तपासलेल्या नमुन्यांमध्ये ११ वाघ, १७ बिबट आणि ५४ सिंहांना या विषाणूची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे हा धोका अचानक निर्माण झालेला नसून अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. मात्र, वन्यजीवांच्या आरोग्य व्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, ही वस्तुस्थिती कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातील घटनेने सिद्ध केली आहे.

'एनटीसीए'ने कोणत्या सूचना दिल्या आहेत?

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर श्वानांचे लसीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पशुसंवर्धन विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि वनविभाग यांच्या समन्वयातून 'इम्युनायझेशन बफर' उभारण्यावर भर दिला जात आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प येथे गेल्या दोन वर्षांपासून परिसरातील गावांमध्ये श्वान आणि पाळीव जनावरांचे सातत्याने लसीकरण केले जात आहे. कान्ह्यातील घटनेनंतर मध्य प्रदेशातही मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू करण्यात आली असून हजारो जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या दोन वर्षांपासून परिसरातील गावांमध्ये श्वान आणि पाळीव जनावरांच्या लसीकरणाची मोहीम राबवली जात आहे.

'वन हेल्थ' संकल्पनेचे महत्त्व काय?

ही घटना 'वन हेल्थ' संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. मानव, पाळीव प्राणी आणि वन्यजीव यांचे आरोग्य परस्परांशी जोडलेले असल्याने एका घटकातील संसर्ग संपूर्ण परिसंस्थेला प्रभावित करू शकतो. त्यामुळे व्याघ्र संवर्धनाचा विचार केवळ वाघांची संख्या वाढवण्यापुरता मर्यादित ठेवून चालणार नाही. जंगलांवरील मानवी दबाव, भटकी श्वाने, पर्यटन विस्तार आणि हवामान बदल यांचाही त्यात विचार करावा लागणार आहे. भविष्यात व्याघ्र संवर्धनाचा मोठा लढा हा शिकारीविरोधातच नव्हे, तर अशा अदृश्य विषाणूंविरोधातही असणार असल्याचे या घटनेने स्पष्ट केले आहे. वाघांसह आता जंगलाचे आरोग्यदेखील सुरक्षित ठेवावे लागणार, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे.

प्रेरणा

जो सीखते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। सीखना एक यात्रा है। इसलिए सीखने की प्यास बुझने मत दीजिए। - नागार्जुन

संपादकीय

हमें अब आर्थिक अनुशासन में जीना सीखना होगा

खाड़ी युद्ध से पैदा हुए बहुआयामी संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री की जनता से अपील भले ही पांच राज्यों के चुनाव के बाद आई, लेकिन देश के भविष्य के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि भारत में तेल के कुंए नहीं हैं यानी इसके लिए विदेशी मुद्रा देनी होती है, लिहाजा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें। साथ ही यह भी कहा है कि कोरोना काल की तरह उद्यमों में वर्क-फ्रॉम-होम फिर से शुरू किया जाए। देश की माली हालत पर नजर रखने वाली संस्थाओं- आरबीआई, मूडीज, एसएंडपी, वर्ल्ड बैंक, फिच और अब एडीबी- सभी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ घटाई है। सरकार ने टैक्स घटाकर तेल के दाम रोके रखे, एमएसएमई के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये का असुरक्षित लोन देना शुरू किया और अधिकांशतः आयातित खादों की कीमतें नहीं बढ़ने दीं। लेकिन इन सब का प्रभाव यह रहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य स्थायी विकास मदों में पूंजीगत निवेश की गुंजाइश कम हो गई। अब पीएम की अपील है कि लोग आयातित सामान न खरीदें, मितव्ययिता से रहें, विदेश यात्रा न करें आदि। चूंकि तेल संकट और ऊंचे दामों से ऊर्जा की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं और इसका अगले कई वर्षों तक प्रभाव पड़ने की आशंका है, लिहाजा यह तो सच है कि बगैर जनता के खर्च-आचरण में बदलाव के स्थिति पर नियंत्रण संभव नहीं। देशवासियों को आर्थिक अनुशासन में जीना सीखना होगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

प्रेम, श्रद्धा, स्नेह से जीवन में भक्ति आसानी से उतर आती है

ईश्वर संदेह का नहीं, जिज्ञासा का विषय है। संदेह की जब अति हो जाती है तो लोग अपना अज्ञान भी भगवान पर आरोपित कर देते हैं। हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार हमको ईश्वर से दूर कर देता है। काकभुशुंडि जी कह रहे हैं- ते सठ हठ बस संसय करहीं, निज अग्यान राम पर धरहीं। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीराम जी पर आरोपित करते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि पक्षीराज गरुड़ को संदेह हो गया था श्रीराम जी के ऊपर। उसके निवारण में काकभुशुंडि जी ने रामचरित उनको सुनाया। ईश्वर से जुड़ने का, उन पर भरोसा करने का सबसे सरल तरीका है- भक्ति की जाए। तीन बातें छंदोबद्ध हो जाएं तो जीवन में भक्ति आसानी से उतर जाती है- प्रेम, श्रद्धा और स्नेह। प्रेम समान लोगों से होता है। यह समतल होता है। श्रद्धा अपने से बड़ों से होती है। स्नेह छोटों के प्रति रहता है। ये तीनों यदि रिद्मिक हो जाएं, एक-दूसरे में घुलमिल जाएं तो भक्ति बन जाती है। भक्त जिज्ञासु तो होता है, पर संदेहग्रस्त नहीं रहता।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • भारत अब विदेशी पूंजी से नहीं डरता है

सबसे कटकर नहीं जुड़कर भी बन सकते हैं आत्मनिर्भर

विकास

शशि थरूर
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद
office@tharoor.in

पहले भारतीय बाजार अपने में बंद और अलग-थलग हुआ करता था, लेकिन अब वह वैश्विक व्यापार का अग्रदूत बनता जा रहा है। भारत के बाजार का यह रूपांतरण शायद 21वीं सदी की विश्व-अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव है। देश ने एक बंद, रक्षात्मक आर्थिक रुख से हटकर बाहर की दुनिया पर नजर रखने वाले, वैश्विक रूप से आक्रामक रवैये को अपनाया है। जो देश कभी वैश्वीकरण का हिचकिचाता हुआ सहभागी हुआ करता था, वो अब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को आकार देने वाली एक आत्मविश्वास से भरी शक्ति बन गया है।

दशकों तक भारतीय बाजार लाइसेंस-परमिट-कोटा राज से परिभाषित होता रहा था। यह नौकरशाही की जकड़न और भारी शुल्क की घुटन भरी व्यवस्था थी, जिसे विदेशी पूंजी के कथित शोषण से घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए रचा गया था। आजादी के बाद की अधिकांश अवधि के दौरान, भारत की आर्थिक रणनीति आत्मनिर्भरता, आयात सब्स्टिट्यूशन (दूसरों से खरीदे जा सकने वाले सामानों का घरेलू उत्पादन) और वैश्विक बाजारों के प्रति गहरी शंका पर आधारित थी।

हालांकि इस दृष्टिकोण ने औद्योगिक क्षमता के कुछ छिटपुट केंद्र जरूर विकसित किए, लेकिन यह आखिरकार दीर्घकालिक अक्षमता, तकनीकी ठहराव और भारत की आर्थिक क्षमता और उसके प्रदर्शन के बीच एक निरंतर बढ़ती खाई का ही कारण बना था। अर्थशास्त्री राज कृष्ण ने तो इसे 'हिंदू विकास दर' करार दे दिया था। हमारी अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकीय वृद्धि और बढ़ती जरूरतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करती रही थी।

1991 के उदारीकरण ने रूपांतरण की शुरुआत को चिह्नित किया। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से खुद को बचाने से लेकर उसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने, और उसमें प्रतिस्पर्धा करने तक पहुंच गया। यह बदलाव आर्थिक रूप से जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही इसका मनोवैज्ञानिक महत्व भी था। खुलेपन की संभावनाओं को अपनाने के लिए भारत को अपनी चिंताओं और असुरक्षा की भावना को त्यागना पड़ा। समय के साथ, वैश्विक व्यापार, पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी नेटवर्क में एकीकरण ने विकास की गति, शहरीकरण के पैटर्न और उद्यमी संस्कृति को नया आकार दिया।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2026 का भारत अपनी बेड़ियों को तोड़कर दुनिया की सबसे खुली और उदारीकृत उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। यह परिवर्तन एक मौलिक अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुआ और वो यह है कि एक डिजिटलीकृत दुनिया में सच्ची आर्थिक सम्प्रभुता अलग-थलग रहने से नहीं, बल्कि जुड़ने से मिलती है। 1991 के शुरुआती सुधारों ने जहां दरवाजे खोलना शुरू किया था, वहीं भारत ने पिछले वर्षों में व्यवधानों को पूरी तरह से हटा दिया है।

अब भारत हाशिये का खिलाड़ी नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक प्रवाहों में केंद्रीय मंच है। सेवाओं के निर्यात, डिजिटल क्षमताओं और मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं ने हमें ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है, जिसके आर्थिक विकल्प हमारी सीमाओं से बहुत आगे तक गूंजते हैं। बहुपक्षीय मंचों के भीतर, भारत ने यूएई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ईयू के साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, न्यूजीलैंड और अमेरिका दोनों ने सैद्धांतिक रूप से समझौतों की घोषणा की है।

विदेशी पूंजी के विरोध से लेकर उसे आकर्षित करने तक; घरेलू अक्षमताओं से लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तक- हमारी यात्रा की दिशा स्पष्ट है। भारत अब वैश्विक व्यवस्था में मूकदर्शक नहीं, अपने भविष्य का प्रमुख निर्माता भी है।

इस बदलाव के आधार में भारत सरकार के 'आत्मनिर्भरता' के मंत्र की एक सूक्ष्म पुनर्व्याख्या भी है। भारत के नेता अब समझते हैं कि आत्मनिर्भरता वैश्विक जुड़ाव के माध्यम से भी हासिल की जा सकती है, दूसरों से अलग-थलग होकर नहीं। भारत अब विदेशी पूंजी से नहीं डरता है और वह पूर्वी एशिया के पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग समूहों के प्रमुख विकल्प के रूप में उत्सुकता से प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

इस प्रकार, भारत के खुलेपन ने अब एक सामरिक महत्व प्राप्त कर लिया है। जो कभी घरेलू सुधार का एजेंडा लगता था, वह अब एक वैश्विक अवसर बन गया है। उभरते डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नए व्यापार समझौतों के बीच तालमेल एक ऐसे भविष्य का संकेत देता है, जहां भारत केवल वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि दुनिया के डिजिटल आर्किटेक्चर का भी निर्यात करेगा। एक बड़े, स्थिर लोकतंत्र, युवा कार्यबल, बेहतर हो रहे बुनियादी ढांचे और एक ऐसे नियामक वातावरण का संयोजन- जो अधिक पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है- भारत को केवल चीन का विकल्प ही नहीं, बल्कि एक बहुध्रुवीय आपूर्ति-शृंखला संरचना में महत्वपूर्ण केंद्र भी बनाता है।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

विश्लेषण • डबल इंजन सरकार का नारा कितना सही?

केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार होने से क्या होता है?

संघवाद

नीरज कौशल
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर
nk464@columbia.edu

हाल के सालों में भाजपा ने नियमित रूप से 'डबल इंजन सरकार' के नारे का इस्तेमाल किया है। लेकिन कानून के जानकारों का तर्क है कि यह नारा भारतीय शासन-व्यवस्था की संघीय संरचना को कमजोर करता है। इसमें यह संकेत निहित है कि केंद्र और राज्य में अगर अलग-अलग दलों की सरकारें हों तो यह बात राज्य की जनता के हित में नहीं होती। बेशक, इस नारे की विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की जा सकती हैं, लेकिन इसका प्रचलित अर्थ यही है कि जब केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टियों की विचारधारा अलग होती है, तब उनके बीच समन्वय कमजोर रहता है।

इस नारे के व्यापक इस्तेमाल से दो प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या यह दावा सच है कि जिन राज्यों की जनता केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को चुनती है, वे कहीं अधिक तेज आर्थिक विकास और बेहतर शासन का अनुभव करते हैं? दूसरा, क्या इस नारे ने भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने में सफलता दिलाई है? पहले प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, और दूसरे का उत्तर कुछ चुनावों में 'हां' है।

पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और इसका उत्तर हाल के कुछ विधानसभा चुनावों के संदर्भ में देते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को पिछले वर्ष बिहार और इस वर्ष असम में दोबारा सत्ता मिली। 'डबल इंजन सरकार' के तर्क के अनुसार, दोनों राज्यों को तेज आर्थिक प्रगति के चमत्कार के रूप में उभरना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों राज्य देश की आर्थिक सीढ़ी में सबसे निचले पायदानों पर हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, जबकि बड़े राज्यों में असम की प्रति व्यक्ति आय चौथी सबसे कम है। सुप्रशासन के मामले में भी इन राज्यों को आदर्श नहीं माना जा सकता।

दूसरी ओर, भाजपा ने कभी भी केरल या तमिलनाडु में शासन नहीं किया है। 'डबल इंजन सरकार' के तर्क के अनुसार, दोनों राज्यों को आर्थिक रूप से बदहाल होना चाहिए था। इसके बिलकुल विपरीत, दोनों राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हैं और तमिलनाडु को सबसे बेहतर शासित राज्यों में से एक भी माना जाता है।

साथ ही, अकसर ऐसी रिपोर्टें सामने आती रही हैं कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भागीदारी करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, बंगाल में तृणमूल के शासनकाल के दौरान राज्य को 2022 से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों से वंचित रखा गया। केंद्र ने व्यापक भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और केंद्रीय निर्देशों के अनुपालन में विफलता के आरोपों के आधार पर इन दोनों योजनाओं को रद्द कर दिया। यद्यपि ये आरोप पूरी तरह असत्य नहीं हो सकते, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की अनियमितताओं के बावजूद फंड्स को निरस्त नहीं किया गया था। बंगाल में यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का संकेत देती है।

इसी प्रकार, केंद्र ने तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूल शिक्षा निधि में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोक दी थी। आरोप लगाया गया कि तमिलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों और पीएमश्री योजना का अनुपालन नहीं किया है। संक्षेप में, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से आर्थिक विकास तो नहीं होता, लेकिन केंद्र उन राज्यों के प्रति अधिक उदार रवैया अपनाता जरूर पाया जाता है, जहां उसकी अपनी पार्टी सत्ता में होती है।

एनडीए को पिछले वर्ष बिहार और इस वर्ष असम में दोबारा सत्ता मिली। लेकिन ये दोनों राज्य देश की आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदानों पर हैं। वहीं केरल और तमिलनाडु प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल हैं।

अब दूसरा सवाल। क्या यह नारा सत्तारूढ़ पार्टी को वोट दिलाता है? लोकनीति-सीएसडीएस ने 2014 से 2022 के बीच 22 सर्वेक्षण किए, जिनमें उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे मानते हैं विकास के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी एक हो? 22 में से 5 सर्वेक्षणों में इस कथन से पूर्णतः असहमत उत्तरदाताओं की संख्या सहमत लोगों से अधिक थी; जबकि शेष 17 में इसका उलटा था। सर्वेक्षणों के समय चार राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दल सत्तारूढ़ थे। लेकिन चुनावों के बाद भाजपा और उसके सहयोगी 12 राज्यों में सत्ता में आए। दो राज्यों में भाजपा सत्ता खो बैठी। लब्बोलुआब यह है कि यह नारा भाजपा को चुनाव जिताने में सहायक तो हो सकता है, लेकिन जो राज्य इस नारे का अनुसरण कर भाजपा को चुनते हैं, वहां इससे आर्थिक समृद्धि आने के प्रमाण नहीं हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर
अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

राजनीति भरोसेमंद रहे अधिकारियों पर भी कार्रवाई

चीन में सरकार और सेना के बीच तनातनी, दर्जनों जनरल बर्खास्त

क्रिस बकले

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और देश की सेना के बीच गंभीर खींचतान के संकेत सामने आ रहे हैं। शी अब उन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने कभी खुद आगे बढ़ाया था। पिछले कुछ महीनों में चीन की सेना से दर्जनों बड़े जनरल बर्खास्त किए जा चुके हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और निष्ठा से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। दो जनरलों को सैनिक अदालत मौत की सजा सुना चुकी है। सजा कम होने पर भी उन्हें उम्र भर कैद में रहना पड़ सकता है।

चीन सरकार इसे सेना को 'भीतर से मजबूत' करने का अभियान बता रही है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इस सफाई अभियान ने सेना की युद्ध की तैयारियों को झटका पहुंचाया है। जो कार्रवाई कभी सीमित भ्रष्टाचार विरोधी अभियान लग रही थी, वह अब शीर्ष सैन्य नेतृत्व की व्यापक सफाई में बदल चुकी है। इस संकट का सबसे बड़ा संकेत साल की शुरुआत में दिखा, जब चीन के सबसे प्रभावशाली सैन्य अधिकारियों में गिने जाने वाले जनरल झांग यूशिया की स्थिति कमजोर पड़ गई। झांग लंबे समय तक शी के सबसे भरोसेमंद सैन्य चेहरों में रहे थे। लेकिन जब शी ने उनके प्रतिद्वंद्वी अधिकारी को समान स्तर का पद दिया तो तनाव खुलकर सामने आ गया। कुछ ही महीनों बाद झांग को सत्ता से बाहर कर दिया गया। हाल में हुई चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक में भी सेना के भीतर उथल-पुथल की झलक दिखाई दी। सरकारी टीवी फुटेज में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम वरिष्ठ जनरल दिखाई दिए। इससे संकेत मिला कि शीर्ष सैन्य नेतृत्व में व्यापक बदलाव जारी हैं। शी-जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सेना की वफादारी केवल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति होनी चाहिए और किसी भी तरह का विश्वासघात बर्दाश्त नहीं होगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी राजनीति में इस तरह की भाषा बेहद गंभीर मानी जाती है। ताइवान की नेशनल चेंगची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चिएन वेन कोऊ के मुताबिक इस तरह की भाषा और शब्द पुराने चीनी राजनीतिक दस्तावेजों में विश्वासघाती जनरलों के संदर्भ में इस्तेमाल होते रहे हैं। यह संकट ऐसे समय सामने आया है जब शी जिनपिंग पिछले एक दशक से चीन की सेना को तेजी से आधुनिक बनाने में जुटे रहे हैं। नए एयरक्राफ्ट कैरियर, हाइपरसोनिक मिसाइलें और बढ़ता परमाणु शस्त्रागार उसी रणनीति का हिस्सा रहे हैं।

चीनी सेना में भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण सेंट्रल मिलिटरी कमीशन के रिटायर्ड वाइस चेयरमैन जनरल 'शू काईहाउ' हैं। चीनी सेना में उनका ऊंचा दर्जा था। जनरल शू पर अधिकारियों के प्रमोशन सहित अन्य कामों के लिए रिश्वत लेने के आरोप हैं। उनकी जांच चल रही है। अमेरिका के साथ बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच सेना में यह अंदरूनी अस्थिरता चीन के लिए नई चुनौती बन सकती है। चेयरमैन माओ के दौर में चले सफाई अभियान की तरह यह उलटफेर अभी खत्म नहीं हुआ है।

सेना की क्षमता पर असर

भ्रष्टाचार के खिलाफ शी की कार्रवाई वास्तविक है। पहले अपने अंदरूनी भाषणों में शी ने इनका विस्तार से जिक्र नहीं किया था। विश्लेषकों का कहना है, शी ने सेना को आधुनिक बनाने के लिए जिन कमांडरों का चयन किया, अब उन पर यकीन नहीं किया जा सकता है। रिश्वत और पक्षपात से उनकी वफादारी और प्रभाव दोनों ही कमजोर हुए हैं।

दो बड़े उद्देश्यों को आघात

विश्लेषक कहते हैं, सेना में उलटफेर ने शी के दो उद्देश्यों -युद्ध की तैयारी और वफादारी- के बीच तनाव का खुलासा किया है। उनके स्थान पर एक सख्त अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वे शी जिनपिंग के साथ चीन की टॉप मिलिटरी काउंसिल के अकेले सदस्य हैं।

सत्ता का अंतिम दौर?

नेशनल चेंगजी यूनिवर्सिटी ताईवान में प्रोफेसर चियेन वेन कोउ कहते हैं, शी जिनपिंग का शासन अपने अंतिम दौर में है। इस दौर में पहुंचने के बाद उनके राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। अपने नजदीकी लोगों के प्रति उनकी चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही है।

© The New York Times

कूटनीति युद्ध में खुलकर ईरान का विरोध न करने से यूएई और पाकिस्तान में मतभेद बढ़ रहे हैं

पाकिस्तान से नाराज यूएई, हजारों नागरिकों को बाहर निकाला

एलियन पेल्टियर, जिया उर रहमान, विवियन नेरीम

ईरान युद्ध में मध्यस्थता के कारण पाकिस्तान की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पुराने सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से उसके रिश्तों पर गंभीर असर पड़ा है। खाड़ी के इस अमीर देश ने पाकिस्तान के वर्करों को निकालने की कार्रवाई और तेज कर दी है। पाकिस्तान में शिया संप्रदाय के नेताओं का अनुमान है कि अप्रैल मध्य के बाद से हजारों पाकिस्तानी शियाओं को डिपोर्ट किया जा चुका है। अमीरात इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान ने यूएई पर ईरानी हमलों की जोरदार तरीके से भर्त्सना नहीं की है। जबकि वह अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता कराने के प्रयास कर रहा है।

यूएई में अमीराती कंपनियों में काम करने वाले बीस पाकिस्तानी शियाओं ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्हें अचानक गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया। इसके बाद पिछले महीने पाकिस्तान भेज दिया गया। अमीरात में बिजनेस करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों में उनके पाकिस्तानी कर्मचारियों को डिपोर्ट किया गया है। पाकिस्तान के साढ़े तीन करोड़ शिया मुसलमानों के ईरान से गहरे आध्यात्मिक संबंध हैं। उन्हें सुन्नी बहुल पाकिस्तान में अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता है।

यूएई से पाकिस्तानियों को निकालने के कारण अस्पष्ट हैं। दोनों देश दावा करते हैं कि उनके रिश्ते मजबूत हैं। पाक विदेश मंत्रालय ने इन्कार किया है कि उसके नागरिकों को बड़े पैमाने पर डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने सिर्फ शियाओं को निकालने के सवालों का जवाब नहीं दिया। प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा जिन पाकिस्तानियों ने अमीरात में अपराध किए हैं, उन्हें निकाला गया है। अमीरात सरकार ने भी इस मसले पर कोई जवाब नहीं दिया है। अमीरात ने पिछले साल पाकिस्तान को दिया गया 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज वापस ले लिया है। इसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 28 हजार करोड़ रु. का कर्ज दिया है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्कानी का कहना है, यूएई को धक्का लगा है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ उसका समर्थन नहीं किया। यूएई को ठेस पहुंचने से पाकिस्तान स्तब्ध है। अमीरात में बीस लाख से अधिक पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान को 76 हजार करोड़ रुपए से अधिक भेजे थे। पाक के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, अमीरात से अच्छे संबंध रखना पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

© The New York Times

डिपोर्ट करने के पहले हिरासत में भी रखा

- उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में कुछ शिया गांवों में 900 लोग यूएई से लौटे हैं।
- शिया संगठन के मोहम्मद अमीन शहीदी के अनुसार संगठन ने पांच हजार परिवारों का डिपोर्टेशन दर्ज किया है।
- एक दर्जन पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें हिरासत में रखा गया। फिर पाकिस्तान भेज दिया गया।
- अमीरात में प्राइवेट स्कूल, होटल और अन्य कारोबार चलाने वाले 12 लोगों ने बताया कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने पाकिस्तानी कर्मचारियों को डिपोर्ट कर दिया है या उनके वीसा रिन्यू नहीं किए हैं।

युद्ध का असर

बीस लाख से अधिक लोग हुए बेरोजगार

लिली निकाउनजर

ईरान पर युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों का असर अब उसकी अर्थव्यवस्था में साफ दिखाई देने लगा है। सरकारी अधिकारी गुलाम हुसैन मोहम्मदी के मुताबिक युद्ध के कारण करीब 10 लाख नौकरियां खत्म हुई हैं, जबकि 20 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हुए हैं। सरकार द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने से देश की टेक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। एक टेक इंडस्ट्री ग्रुप का अनुमान है कि इंटरनेट बंदी से रोज लगभग 760 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ईरान की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी डिजिकाला ने 200 कर्मचारियों की छंटनी की है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से औद्योगिक ठिकाने प्रभावित हुए हैं। वहीं होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। युद्ध से पहले ही प्रतिबंधों और महंगाई से जूझ रही ईरानी अर्थव्यवस्था अब और दबाव में है। निजी कारोबार कमजोर होने से सरकार की आय और सार्वजनिक खर्च दोनों प्रभावित होंगे। © The New York Times

शिक्षा अमेरिका में घटती जन्मदर का प्रभाव

सरकारी स्कूलों में तेजी से घट रहे छात्र, कई बंद हो सकते हैं

सारा मर्वोश, क्लेयर मिलर

अमेरिका में घटती जन्मदर से स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई है। 2010 के दशक के बाद से तीस राज्यों में किंडरगार्टन से 12वीं ग्रेड तक के छात्रों की संख्या घटी है। महामारी के बीच पब्लिक स्कूलों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में दस लाख से अधिक गिरावट आई थी। इसके बाद भी यह सिलसिला जारी है।

लॉस एंजिलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क सहित बड़े शहरी स्कूल में छात्रों की भर्ती कम हुई है। कई जिलों में संख्या 10 से 20 प्रतिशत तक घटी है। छात्र संख्या घटने से पब्लिक स्कूलों की आमदनी कम हो रही है। कई डिस्ट्रिक्ट स्कूलों को बंद करने पर विचार होने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सबसे बड़ी वजह जन्मदर में गिरावट है। बीस साल से लगभग हर वर्ष जन्मदर कम हो रही है। 2025 में प्रति महिला जन्म दर 1.63 रही। यह 2024 से एक फीसदी कम है। इसके अलावा शहरों में मकानों की कीमतों और किराए के साथ अन्य खर्च बढ़े हैं। ट्रम्प प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई होने से दूसरे देशों से भी कम बच्चे आ रहे हैं। कई पब्लिक स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों, घर में पढ़ाई, चार्टर स्कूलों और वर्चुअल स्कूलों के कारण ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है।

महामारी में अमेरिका के निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। कई राज्यों में प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकारों से मदद मिलती है। अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा सांख्यिकी सेंटर का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में गिरावट का दौर जारी रहेगा। कुछ राज्यों में बड़े मेट्रो शहरों के बाहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी हाल में ऐसे राज्यों में गिरावट देखी गई है।

© The New York Times

इस हफ्ते चर्चा में...

यूक्रेन से दोगुने से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं

3 लाख 52 हजार रूसी

सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन युद्ध में 2025 तक। यूक्रेन के एक लाख 40 हजार सैनिकों की मौत का अनुमान है।

5.23 लाख करोड़ रुपए

खर्च करने की योजना बना रही है इलॉन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स एआई चिप्स बनाने पर।

2.38 लाख करोड़ रुपए

के हथियार अमेरिका से खरीदने की मंजूरी ताइवान की संसद ने दी है। इसके लिए कई महीने बहस चली।

स्मार्ट निवेश • बफे को पेटीएम में 40% नुकसान, पर देश की दिग्गज कंपनियों को कच्चे माल की सप्लाई करने वाली छोटी-छोटी फर्मों से बड़ा मुनाफा

बफे को लो प्रोफाइल भारतीय बिजनेस से सालाना 4,378 करोड़ रुपए की आय

भास्कर न्यूज | मुंबई

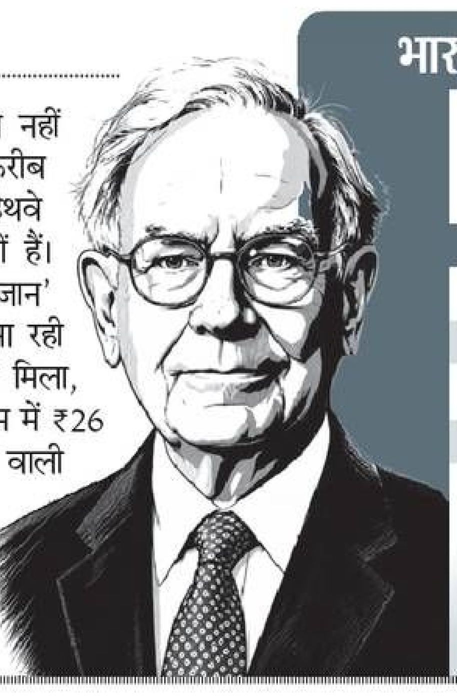

मशहूर निवेशक वॉरेन बफे कभी भारत नहीं आए। फिर भी उनकी 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब ₹95 लाख करोड़) की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने यहां मजबूत कारोबारी जड़ें जमा ली हैं। ग्रेग एबेल के सीईओ बनते ही इस 'अनजान' पोर्टफोलियो की असली तस्वीर सामने आ रही है। एबेल को ऐसा भारतीय पोर्टफोलियो मिला, जो दशकों से चुपचाप बढ़ रहा है। पेटीएम में ₹26 करोड़ के निवेश पर 40% नुकसान झेलने वाली बर्कशायर की असली ताकत उसकी 58 गैर-लिस्टेड कंपनियों में हैं, जिनमें से कई भारत में सक्रिय हैं। इससे बीते साल ₹4,378 करोड़ की आय हुई।

भारत की हर बड़ी इंडस्ट्री में बफे की 'अदृश्य' पैठ ... आपकी कार के इंजन से लेकर शैंपू तक फैला है बर्कशायर का साम्राज्य

इन कंपनियों से हो रहा बर्कशायर हैथवे का भारत में कारोबार

कंपनी	आय
लुब्रिजोल इंडिया	3,292
आईएमसी ग्रुप इंडिया	1,086
कंपनी निवेश CPVC मैन्युफैक्चरिंग	1,238
3 साल का कुल निवेश	2,380

(आंकड़े करोड़ रुपए में 2025 के, स्रोत: फॉर्च्यून इंडिया)

• इंजन ऑयल से लेकर मेडिकल उपकरण तक, पाइप से लेकर शैंपू तक बर्कशायर का इंडिया कनेक्शन उतना ही गहरा है, जितना कम चर्चित।

भारत में लुब्रिजोल इंक की मौजूदगी 6 दशकों से

• शुरुआत इंडियन ऑयल के साथ 60:40 जॉइंट वेंचर से। अब भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 26%

• **मूल बिजनेस:** मोबिलिटी एडिटिव्स- कार, ट्रक, 125 सीसी मोटरसाइकिलों के इंजन ऑयल की केमिस्ट्री।

• **दूसरा बड़ा दांव:** सीपीवीसी पाइप रेजिन- ग्रासिम के साथ जॉइंट वेंचर, सालाना उत्पादन क्षमता 1 लाख टन।

पेंट बिजनेस से रोजमर्रा के एफएमसीजी तक में पैठ

• एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, बिड़ला ओपस को उच्च गुणवत्ता वाले रेजिन्स और हाइपर-डिस्पर्सेंट्स की निर्बाध सप्लाई।

• पॉलिहेंस (चेन्नई) के साथ जॉइंट वेंचर-मेडिकल डिवाइस के लिए पॉलियूरेथेन्स की सप्लाई।

• यूनिलीवर को शैंपू, साबुन और फार्मा फार्मा फॉर्मूलेशन के लिए पॉलिमर सप्लाई करती है।

विस्तार | भारत में क्विक कॉमर्स से लेकर फूड बिजनेस पर फोकस

• ₹30 करोड़ का टेक्नोलॉजी सेंटर निर्माणाधीन। यहां भारतीय इंजीनियर, भारतीय समस्याओं पर रिसर्च करेंगे।

• रूपा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप से आगे ब्रैंडफोर्ड के जरिए नए पार्टनर की तलाश कर रही बफे की कंपनी।

• ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पर फोकस, बीमा इनरवियर में बड़ी संभावना देख रही बर्कशायर हैथवे।

• देवयानी इंटरनेशनल से हाथ मिलाया।

हम परदे के पीछे से काम करते हैं

जब मेरे ससुर ने स्किपर पाइप्स का वो विज्ञापन देखा जिसमें एमएस धोनी हैं तो उन्हें लुब्रिजोल का नाम कहीं नजर नहीं आया। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने कहा- यही तो चाहिए था। हम परदे के पीछे काम करते हैं, सामने नहीं आते।
- अभिषेक श्रीवास्तव, एमडी, लुब्रिजोल इंडिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका

सुधार • टिकटों की कीमतें औसतन 22% बढ़ीं, जिया माइज की बिक्री से ₹222 करोड़ आए

पीवीआर की 'धुरंधर' तिमाही... ₹187 करोड़ मुनाफा, 1 साल पहले 125 करोड़ घाटे में थी

भास्कर न्यूज | मुंबई

सिनेमाघरों में लौटती भीड़ और धुरंधर जैसी फिल्मों ने पीवीआर-आइनॉक्स के वित्तीय नतीजों को 'सुपरहिट' बना दिया। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 187 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले एक बड़ा टर्नअराउंड है। तब कंपनी ने करीब 125.3 करोड़ का घाटा झेला था।

दरअसल कंपनी ने जनवरी में सहायक कंपनी जिया माइज प्राइवेट लिमिटेड में 93.27% हिस्सेदारी ₹222 करोड़ में बेची। इससे चौथी तिमाही में असाधारण लाभ हुआ। बीती तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 26% बढ़कर ₹1,547 करोड़ हो गई। कंपनी अब 'डेट फ्री' होने की राह पर आगे बढ़ रही है। इसकी वजह औसत टिकट दरों में 22% उछाल और फूड-बेवरेज से मोटी कमाई है। इतना ही नहीं, सालभर में 15 करोड़ दर्शकों की फुटफॉल और अब तक के सबसे ऊंचे एबिटा के साथ 2025-26 पीवीआर के लिए सबसे सफल साल रहा। सिनेमाघरों में सीटें भरने की दर भी बढ़कर 24% हो गई है, जो पिछले साल 20.5% थी। फिर भी सोमवार को कंपनी के शेयर 4.5% गिर गए।

पीवीआर: जनवरी-मार्च तिमाही और पूरे साल का रिजल्ट (कन्सॉलिडेटेड) एक नजर में

मापदंड	Q4 FY26	Q4 FY25	अंतर	FY25-26	FY24-25	अंतर
ऑपरेटिंग रेवेन्यू	1,547.3	1,229.9	25.8%	6,646.2	5,699.9	16.6%
टैक्स पूर्व लाभ	21	↓163	-	227	↓358	-
ऑपरेटिंग मार्जिन	33.9%	28.3%	19.8pp	33.6%	30.3%	10.7pp
टैक्स बाद लाभ	187	↓125	-	334	↓280	-

आंकड़े करोड़ रुपए में, स्रोत: कंपनी फाइलिंग

480 रु. चौथी तिमाही में औसत प्रति दर्शक खर्च (टिकट + खाना) पहुंचा

मार्केट कैप | पीवीआर आइनॉक्स का मार्केट कैप 31 मार्च 2026 तक 9,022 करोड़ रहा।

जिया माइज के अलावा घाटे से भारी मुनाफे में आने के 3 बड़े कारण...

1. रिकॉर्ड 15 करोड़ दर्शक: वित्त वर्ष 2026 में 15 करोड़ दर्शक पहुंचे, जो पिछले साल के मुकाबले 9.6% अधिक है। सीटों के भरने की दर 23% से बढ़कर 26.2% हो गई है।

2. टिकट और खान-पान पर रिकॉर्ड खर्च: चौथी तिमाही में औसत टिकट कीमत 22.4% बढ़कर 315 हो गई। पिछले साल यह 258 थी। पूरे वित्त वर्ष के लिए औसत टिकट 280 रुपए रहा। एक दर्शक ने औसतन 427 खर्च किए (टिकट + खाना), जबकि 2025 में 393 रुपए खर्च किया था। चौथी तिमाही में यह खर्च 480 रुपए रहा।

3. लागत नियंत्रण, वर्कफोर्स एफिशिएंसी: महंगाई बढ़ने के बावजूद कंपनी ने आंतरिक खर्चे सीमित रखे। वित्त वर्ष 2020 से 2026 के बीच महंगाई 37% बढ़ी, वहीं कंपनी ने 'प्रति स्क्रीन फिक्स्ड कॉस्ट' को स्थिर रखा। प्रति स्क्रीन कर्मचारियों की संख्या 17.7 से घटाकर 12.1 कर दी है।

बड़े परदे का रिपोर्ट कार्ड... मिड-बजट फिल्में जीतीं, मेगा स्टार्स की पकड़ अब ढीली पड़ रही

1. हिंदी, हॉलीवुड की दमदार वापसी
पूरे भारत का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (जीबीओसी) 11% बढ़कर 13,519 करोड़ रहा। हिंदी फिल्मों का कलेक्शन 55% बढ़ा। हिस्सेदारी 29% से 42% हो गई।
• हॉलीवुड कलेक्शन में 54% वृद्धि। स्ट्राइक के बाद जब हॉलीवुड की बड़ी रिलीज लौटी, तो दर्शकों ने उन्हें हाथों-हाथ लिया।
रीजनल सिनेमा: बाजार में हिस्सेदारी 52% (FY25) से घटकर 46% रह गई है। इसके बावजूद 'कांतारा: द लीजेंड' जैसी फिल्मों ने (कुल 724 करोड़ कलेक्शन) साबित किया कि क्षेत्रीय कहानियों में दम बरकरार है।

2. 500 करोड़+ कमाने वाली फिल्मों का कुल कलेक्शन में हिस्सेदारी घटी
चौंकाने वाला ट्रेंड यह रहा कि अब इंडस्ट्री 500 करोड़ वाली मेगा फिल्मों के भरोसे नहीं। 500 करोड़ से अधिक कमाने वाली फिल्मों की हिस्सेदारी 30% से घटकर 19% रह गई है। यानी केवल 'मेगा स्टार्स' के दम पर फिल्म चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है।

3. मिड-बजट फिल्मों का उदय: 100-200 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 20% हो गई है। 8% अंक की बढ़त बताती है कि दर्शक अब स्टार पावर के बजाय कंटेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं।

म्यूचुअल फंड • एसआईपी मार्च से 3% कम, पर 1 साल पहले से 18% ज्यादा

निवेशक अब ज्यादा रिस्क ले रहे, स्मॉल कैप फंड्स में निवेश सर्वाधिक 10% बढ़ा

भास्कर न्यूज | मुंबई

मार्च में रिकॉर्ड निवेश के बाद अप्रैल में एसआईपी थोड़ी थमी पड़ी। लेकिन एक साल पहले की तुलना में निवेशकों का भरोसा अब भी मजबूत बना हुआ है। हालांकि एक नया ट्रेंड देखने को मिला, निवेशक ज्यादा सुरक्षित लार्ज कैप फंड से पैसे निकालकर अधिक रिस्की स्मॉलकैप फंड (सबसे ज्यादा 10% बढ़ोतरी) में लगा रहे हैं।

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एम्फी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिये निवेश घटकर 31,115 करोड़ रह गया। यह मार्च के रिकॉर्ड 32,087 करोड़ से 3% कम, लेकिन अप्रैल 2025 के 26,400 करोड़ की तुलना में 18% ज्यादा है।

सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते माह एसआईपी एसेट्स ₹16,85,126 करोड़ हो गए। यह इंडस्ट्री के कुल एयूएम का 20.6% है। कंट्रीब्यूटिंग एसआईपी अकाउंट्स भी 9.64 करोड़ हो गए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एयूएम मार्च के 73.7 लाख करोड़ से बढ़कर अप्रैल में 81.9 लाख करोड़ हो गया। नई स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) कैटेगरी भी रफ्तार पकड़ रही है। अप्रैल में इस कैटेगरी का एयूएम 16% बढ़कर 12,329 करोड़ और निवेश 1,218 करोड़ रहा।

अब 20% से ज्यादा फंड निवेश एसआईपी के जरिए

एसआईपी निवेश अप्रैल, 2026
₹31,115 करोड़
मार्च से 3% कम, पर...
सालाना बढ़त +18%

कुल एसआईपी एसेट्स
₹16.85 लाख करोड़, ये
कुल एयूएम का 20.6%

कंट्रीब्यूटिंग एसआईपी
अकाउंट्स: 9.64 करोड़
कुल फोलियो: 27.53 करोड़
नए फोलियो: 13.77 लाख

इंडस्ट्री का नेट एयूएम
अप्रैल: ₹81.9 लाख करोड़
मार्च: ₹73.7 लाख करोड़
बढ़ोतरी: 11%

एक्टिव इक्विटी फंड में निवेश अप्रैल Vs मार्च: लार्ज-कैप से सबसे ज्यादा निकासी

फंड कैटेगरी	अप्रैल	मार्च	बढ़ा/घटा
फ्लेक्सी-कैप फंड्स	10,148	10,054	↑1%
स्मॉल-कैप फंड्स	6,886	6,264	↑10%
मिड-कैप फंड्स	6,551	6,064	↑8%
लार्ज-कैप फंड्स	2,525	2,998	↓15%
सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स	1,949	2,699	↓3.3%

(निवेश के आंकड़े करोड़ रुपए में, स्रोत: एम्फी)

निवेशक ज्यादा रिस्क लेने के मूड में

• फ्लेक्सी-कैप फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश हुआ, लेकिन इसमें बढ़ोतरी बेहद धीमी रही।

• लार्ज-कैप फंड्स में निवेश सबसे ज्यादा 473 करोड़ रुपए घटा, निवेशक ज्यादा रिस्क ले रहे।

डेट फंड्स: अप्रैल में पलट गया रुझान

कैटेगरी	अप्रैल-करोड़ में	मार्च-करोड़ में
लिक्विड फंड्स	↑1,65,000	↓1,34,000
ओवरनाइट फंड्स	↑31,420	↓40,228
कुल डेट फंड्स	↑2,47,000	↓2,94,000

ऐसा क्यों? डेट फंड्स में यह बदलाव सीजनल है- वित्त वर्ष के अंत (मार्च) में कंपनियां अमूमन पैसा निकालती हैं, अप्रैल में वापस लगाती हैं।

गोल्ड ईटीएफ में निवेश 34% बढ़ा, हाइब्रिड, आर्बिट्रेज में ट्रेंड पलटा

अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ में ₹3,040 करोड़ निवेश हुआ। यह मार्च में ₹2,266 करोड़ के निवेश से 34% ज्यादा है। बीते महीने हाइब्रिड स्कीम्स में भी 20,565 करोड़ निवेश हुआ, जबकि मार्च में 16,538 करोड़ की निकासी हुई थी। इस बीच आर्बिट्रेज फंड्स में भी यही हुआ। मार्च में ₹21,114 करोड़ निकासी की जगह अप्रैल में ₹12,378 करोड़ निवेश हुआ।

बिजनेस ब्रीफ

जीवन बीमा का न्यू प्रीमियम अप्रैल में 39 फीसदी बढ़कर ₹30,550 करोड़

नई दिल्ली | अप्रैल में जीवन बीमा कंपनियों का न्यू बिजनेस प्रीमियम (एनबीपी) 39% बढ़कर 30,550 करोड़ हो गया। एलआईसी का एनबीपी 38% और प्राइवेट कंपनियों का 40.9% बढ़ा। जीएसटी शून्य होने से टर्म इंश्योरेंस को मजबूती मिली। ग्रुप बिजनेस 50% से ज्यादा बढ़ गया। 2025-26 में इंडस्ट्री का एनबीपी पहली बार 4 लाख करोड़ पार कर गया।

दौरे से पहले ट्रम्प से चीनी कारों के लिए अमेरिकी बाजार न खोलने की अपील

वॉशिंगटन | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चीन के दौरे से पहले अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री, यूनियन और सांसदों ने चीनी कारों के लिए अमेरिकी बाजार न खोलने की अपील की है। डेटा सुरक्षा और सब्सिडी वाली सस्ती ईवी से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को खतरा बताया गया है। मिशिगन के सांसदों ने बिल लाकर चीनी वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है।

इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में बैंक ऑफ अमेरिका ने सेबी से सेटलमेंट किया

मुंबई | बैंक ऑफ अमेरिका ने भारतीय बाजार नियामक सेबी से इनसाइडर ट्रेडिंग का एक मामला सुलझा लिया है। बैंक ने नियमों के तहत स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस न बनाए रखने के मामले में 58.5 लाख का सेटलमेंट फीस जमा करके विवाद सुलझाया है। कंपनी ने दोष स्वीकार नहीं किया, पर सेटलमेंट के बावजूद गलत जानकारी देने पर भविष्य में कार्रवाई हो सकती है।

ऑस्कर विजेता डायरेक्टर ने डिजाइन किया दुनिया का सबसे आलीशान ट्रेन कोच, एक सफर का किराया 19 लाख रुपए

लंदन | मशहूर फिल्म निर्देशक बैज लुहरमन और उनकी पत्नी कैथरीन मार्टिन ने लग्जरी ट्रैवल ब्रांड बेलमंड के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलमैन ट्रेन में सीलिया नाम का प्राइवेट डाइनिंग कोच डिजाइन किया है। 1930 के हॉलीवुड ग्लैमर और शेक्सपियर थीम वाले इस कोच में 12 यात्री बैठ सकते हैं। इसमें लाइव ओपन किचन और कॉकटेल बार है। लंदन से चलने वाले इस लग्जरी कैरिज की बुकिंग ₹19 लाख से शुरू होती है।

सोना-चांदी पर आयात शुल्क अभी नहीं बढ़ेगा: केंद्र

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

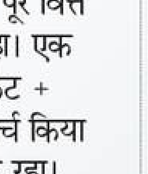

सरकार के एक आधिकारिक सूत्र ने स्पष्ट किया है कि सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सोमवार को आया यह स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के बीच डॉलर विदेशी करेंसी बचाने के लिए एक साल तक सोने की खरीदारी और विदेश यात्रा टालने के लिए कहा था। मोदी ने ईंधन के विवेकपूर्ण इस्तेमाल, सोने की गैर-जरूरी खरीदारी कम करने और डॉलर बचाने को राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया था। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोने का आयात बिल रिकॉर्ड 72 अरब डॉलर (₹6.8 लाख करोड़) तक पहुंच गया। मोदी के बयान के बाद ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। कई कंपनियों के शेयर 8-12% तक टूट गए। सरकार घरेलू बचत को बैंक, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड की ओर मोड़ना चाहती है।

कंपनियों की वैल्यू ₹6 लाख करोड़ घटी

सेंसेक्स 1,313 अंक टूटा, 40 दिन की बड़ी गिरावट

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी का सिलसिला सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में जारी रहा। निफ्टी 360 (-1.49%) अंक टूटकर 23,815 पर और सेंसेक्स 1,313 अंक (-1.7%) गिरकर 76,015 पर बंद हुआ। यह 30 मार्च के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप एक ही दिन में ₹6.1 लाख करोड़ घट गया। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के मुताबिक, 27 अप्रैल के बाद पहली बार निफ्टी 20-दिन के ईएमए (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) से नीचे बंद हुआ है, जो गिरावट का संकेत है। बाजार में डर मापने वाला इंडेक्स इंडिया विक्स 10% से ज्यादा उछल गया, जो निवेशकों के बीच बढ़ती घबराहट दर्शाता है।

क्रूड और तनाव बढ़ने से सेंटिमेंट कमजोर

विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन के इस्तेमाल में कटौती, एक साल तक सोना न खरीदने और विदेश यात्राएं सीमित करने की अपील की थी। निवेशकों ने इसे इस संकेत के रूप में लिया कि सरकार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी या आयात नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकती है। क्रूड के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर टिकने और रुपए में ऐतिहासिक कमजोरी से भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर हुआ।

बिजनेस इंफो

छोटे लोन लेने वाले 23% घटे, पर औसत कर्ज 18% बढ़ा

मुंबई | छोटे कर्ज की राह कठिन हो रही। जनवरी-मार्च में बांटे गए छोटे कर्ज 23%, कर्जदार 17% घटे। कर्जदार परिवार 8.3 करोड़ से 6.9 करोड़ रह गए। कुल पोर्टफोलियो भी 13% घटकर 3.31 लाख करोड़ पर आ गया। हालांकि, औसत कर्ज राशि 18% बढ़कर 61,500 हो गई।

लोन लेने वाले परिवार 1 साल में 1.4 करोड़ कम हुए

मुख्य संकेतक	Q4 25	Q4 26	घट/बढ़
लोन संख्या	14 करोड़	10.7 करोड़	↓23.2%
कर्जदार परिवार	8.3 करोड़	6.9 करोड़	↓16.9%
लोन पोर्टफोलियो	3.81 लाख करोड़	3.31 लाख करोड़	↓13.2%
औसत कर्ज राशि	₹52,000	₹61,500	↑18.3%

देश के 82.9% माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो पर 10 राज्यों का दबदबा

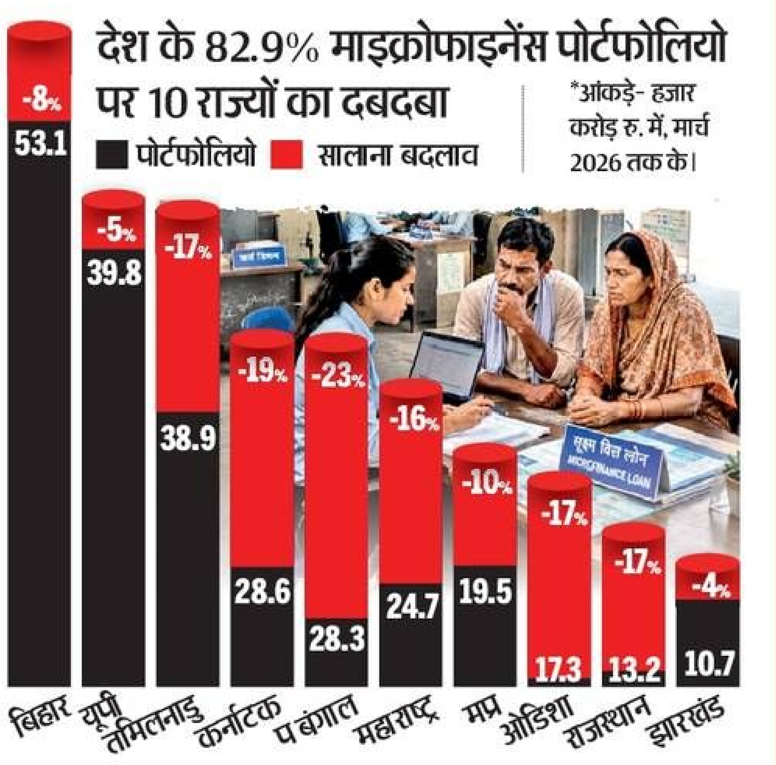

बड़े लोन की हिस्सेदारी बढ़ रही, छोटे की घट रही

लोन राशि	जन.-मार्च-25	जन.-मार्च-26	वृद्धि
30 हजार तक	5.8%	3.2%	↑8.1%
30-50 हजार	39.5%	23.6%	↑21.0%
50-80 हजार	36.0%	41.8%	↑25.1%
80 हजार-1 लाख	11.0%	19.2%	↑33.4%
1 लाख से अधिक	7.7%	12.2%	↑32.6%

• बांटे गए कुल लोन की राशि 1 साल में 25.8% बढ़ी। यह जन.-मार्च-25 के 65,192 करोड़ से बढ़कर जन.-मार्च-26 में 77,555 करोड़ हो गई।

• बांटे गए लोन की संख्या भी 22.8% बढ़ी। यह जन.-मार्च-25 के 125.4 लाख से बढ़कर जन.-मार्च-26 में 126.1 लाख हो गई

• 50 हजार से अधिक रकम वाले लोन की हिस्सेदारी 54.7% से बढ़कर 73.2% हुई।

57 फीसदी नए कर्ज पुराने कर्जदारों को ही दिए गए।

(स्रोत: क्रिफ माइक्रोलेंड तिमाही रिपोर्ट - मई 2026)

बिजनेस एंकर आर्थिक फैसलों में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी से बदली रोजगार की तस्वीर, शहरों में असर ज्यादा स्पष्ट

महिला मुखिया वाले घरों में कम हुई दिहाड़ी, पक्की नौकरियां बढ़ीं: रिपोर्ट

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश में महिलाओं की आर्थिक भूमिका सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रह गई। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया है कि महिला मुखिया वाले परिवारों में रोजगार की गुणवत्ता तेजी से सुधर रही है। जब घर में महिला की चलती है, तो परिवार की निर्भरता असुरक्षित दिहाड़ी मजदूरी से हटकर सम्मानजनक नियमित वेतन वाली नौकरियों की ओर बढ़ जाती है। ऐसी महिलाओं में नियमित रोजगार की संभावना 4.4% बढ़ी है, जबकि दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भरता 4.2% घटी है। यह संकेत है कि महिलाएं संरक्षित रोजगार की ओर बढ़ रही हैं।

देशभर के 2.70 लाख परिवारों और 11.48 लाख से अधिक लोगों के आंकड़ों पर आधारित सर्वे...

शहर: सुरक्षित नौकरियों की ओर बड़ी छलांग

शहरी क्षेत्रों में जिन घरों की मुखिया महिला है, वहां नियमित वेतन वाली नौकरियों की संभावना 10 फीसदी तक बढ़ गई है। यह डेटा चौंकाने वाला है क्योंकि यह दर्शाता है कि महिलाएं अनिश्चित छोटे-मोटे व्यवसायों के बजाय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा वाले कॉर्पोरेट या संस्थागत काम को प्राथमिकता दे रही हैं।

ग्रामीण भारत: दिहाड़ी मजदूरी में 5% तक की कमी आई

महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण घरों में दिहाड़ी में शामिल होने की संभावना 5% घटी। इसकी जगह परिवार अब खुद के छोटे उद्यमों या नियमित काम की ओर बढ़ रहे हैं, जो उनकी बढ़ती बार्गेनिंग पावर को दर्शाता है।

महिला शिक्षित होती है तो तेजी से उन्नति

अध्ययन में शिक्षा को भी महिलाओं के रोजगार बदलाव का बड़ा कारण बताया गया है। अशिक्षित महिलाओं में दिहाड़ी मजदूरी की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन शिक्षा बढ़ने के साथ यह तेजी से घटती है। उच्च माध्यमिक और उससे ऊपर की पढ़ाई करने वाली महिलाओं में नियमित वेतन वाली नौकरी की संभावना सबसे अधिक पाई गई।

श्रम में हिस्सेदारी रिकॉर्ड 40 फीसदी पहुंची

देश में महिला श्रम भागीदारी दर 40% तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 45.9% और शहरों में महज 27.7% है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं में स्वरोजगार की संभावना बढ़ी है। यदि प्रशिक्षण, रोजगार योजनाओं का विस्तार किया जाए तो महिलाओं को बेहतर रोजगार मिल सकता है।

यहां दी मात... परिवहन में महिलाओं की नौकरी पुरुषों से ज्यादा

रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प बदलाव परिवहन क्षेत्र में दिखा। यहां नियमित वेतन वाली नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा पाई गई। लंबे समय तक पुरुष प्रधान माने जाने वाले इस क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी नए रोजगार रुझान का संकेत मानी जा रही है। दूसरी ओर खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की नियमित नौकरी हिस्सेदारी अब भी काफी कम बनी हुई है।

यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो उसे बदल दें। यदि आप उसे बदल नहीं सकते, तो अपना नजरिया बदल लें। — माया एंजेलो

नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली की एक कड़वी सच्चाई उजागर की है। देश के तकरीबन सभी बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे खोल देना बेशक एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन शिक्षा के असल उद्देश्य तभी पूरे होंगे, जब बच्चों को पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ने पर मजबूर न होना पड़े।

दूसरे चरण की चुनौती

देश की शिक्षा व्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक ऐसे संकट की ओर इशारा करती है, जो कहीं अधिक गंभीर और जटिल है। रिपोर्ट कहती है कि भारत ने बच्चों को स्कूल तक लाने की चुनौती को तो काफी हद तक हल कर लिया है, लेकिन उन्हें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूल में टिकाए रखने की मुश्किल अब भी बनी हुई है। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी देश की मानव संसाधन क्षमता सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा से विकसित नहीं हो सकती। वर्तमान दौर में केवल पढ़ना-लिखना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे में, अगर लाखों बच्चे पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ रहे हैं, तो यह केवल शिक्षा का संकट नहीं, बल्कि देश की उत्पादकता और सामाजिक प्रगति पर भी प्रश्नचिह्न है। दरअसल, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्कूल तक लाने में मध्याह्न भोजन, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं ने भूमिका निभाई और अभिभावकों को भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। लेकिन, माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचते-पहुंचते समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है। आर्थिक दबाव, सामाजिक बाधाएं, शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार की चिंता और पारिवारिक हालात बच्चों को स्कूल से दूर करने लगते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी समस्या आर्थिक ही है। गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किशोरावस्था में पहुंच चुके बच्चों की पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं होता। खासकर लड़कों को कमाने और लड़कियों को घरेलू जिम्मेदारियों की ओर धकेल दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और गंभीर है, जहां माध्यमिक विद्यालय अक्सर दूर होते हैं और परिवहन की सुविधाएं सीमित रहती हैं। रिपोर्ट का यह कहना गंभीर है कि देश के एक लाख से भी अधिक स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिनमें से 89 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हैरानी की बात है कि देश में तकरीबन आठ हजार स्कूल ऐसे हैं, जो केवल नाम के लिए चल रहे

हैं और जिनमें एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। इसके अतिरिक्त भी, देश में हजारों स्कूल ऐसे हैं, जहां पानी, शौचालय, बिजली और प्रयोगशाला वगैरह कुछ नहीं है। यह विडंबना ही है कि एक ओर भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश बनने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ, बड़ी संख्या में युवा अधूरी शिक्षा के साथ श्रम बाजार में प्रवेश कर असंगठित रोजगार का दायरा बढ़ा रहे हैं। देश ने शिक्षा के पहले चरण की लड़ाई काफी हद तक जीत ली है। अब चुनौती स्कूलों के दरवाजे खोलने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि हर बच्चा सिर्फ स्कूल पहुंचे ही नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा पूरी भी करे।

बंगाल के लोगों ने बदलाव को चुना है

बंगाल ने कभी नवजागरण की दिशा दिखाई थी, उदार चिंतन का साहस दिया था। उसी बंगाल के लोगों ने सत्ता परिवर्तन के साथ नई उम्मीदें जगाई हैं। चुनाव के नतीजों की बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों द्वारा आलोचना उनके दोहरेपन का ही नमूना है।

पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता में बदलाव के लिए नहीं था, यह लंबे समय से व्याप्त क्षोभ, थकान और धोखा दिए जाने की विस्फोटक प्रतिक्रिया का अवसर भी था। राज्य के लोगों ने सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए नहीं, तृणमूल को हराने के लिए भी वोट दिया। जो पार्टी एक समय परिवर्तन का प्रतीक बन गई थी, समय के साथ वह सत्ता के अहंकार, कदाचार और दलीय अंकुश का प्रतीक बन गई थी। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की सूची लंबी थी। पार्टी के विरोधी लंबे समय से कह रहे थे कि राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण लगातार बढ़ रही है, पुलिस और प्रशासन पार्टी के पुर्जे के रूप में काम कर रहे हैं, पंचायत से लेकर शीर्ष स्तर तक कदाचार और उगाही ने सांस्थानिक रूप ले लिया है। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार, कट मनी की दुष्प्रवृत्ति और स्थानीय स्तर पर नेताओं-कार्यकर्ताओं का अस्वाभाविक आर्थिक उत्थान-ये सब आम लोगों को नजर आ रहे थे। गांवों के लोगों ने देखा कि जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, वे कुछ ही साल में अथाह संपत्ति के मालिक बन बैठे।

तस्लीमा नसरीन
जानी-मानी लेखिका

लोगों में यह धारणा भी बनी कि उद्योग-धंधे, रोजगार और स्थायी विकास पर जोर देने के बजाय लाभार्थी योजनाओं के जरिये वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश की गई। 'लक्ष्मी भंडार' या दूसरी योजनाओं से असंख्य लोगों को लाभ मिलने के बावजूद ममता के विरोधी इसका प्रचार करने में सफल हुए कि विकास के बजाय लाभार्थी योजनाओं के जरिये वोटों की खरीद की राजनीति चल रही है।

सरकारी कर्मचारी भी तृणमूल सरकार से नाराज थे। महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन, नौकरी से जुड़े असंतोष और प्रशासन से दूरी ने अनेक शिक्षित, मध्यवर्गीय वोटरों को तृणमूल का विरोधी बना दिया था। सत्ताधारी दल के आतंक, बूथों पर कब्जे, विरोधियों पर हमले और चुनावी अराजकता के आरोपों के कारण लोगों में लोकतंत्र के प्रति क्षोभ और अनास्था की भावना बढ़ रही थी। महिलाओं की असुरक्षा, बलात्कार और स्त्री शोषण के मामलों

में प्रशासन की भूमिका से भी लोगों में क्षोभ था। सबसे बड़ी बात कि लोगों के एक वर्ग की यह धारणा बन गई थी कि ममता बनर्जी अब पहले की तरह योद्धा नेत्री नहीं रहीं। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण उनके चारों तरफ व्यक्तिपूजा, अति केंद्रीकरण और सत्ता के अहंकार का वातावरण तैयार हुआ है। इतिहास में कई बार यह देखा गया है कि कोई सरकार तभी हारती है, जब जनता को लगने लगता है कि सत्तासीन सरकार अब उनकी बातें नहीं सुन रही। प. बंगाल में इस बार इस धारणा ने बड़ी भूमिका निभाई है।

एक समय था, जब बंगाल की पहचान सिर्फ एक भूखंड के तौर पर नहीं, बल्कि एक बौद्धिक सभ्यता के रूप में थी। बंगाल चिंतन और नवजागरण का केंद्र था। राजा राममोहन राय, विवेकानंद, रवींद्रनाथ और सुभाषचंद्र से लेकर सत्यजित राय और महाश्वेता देवी तक बंगाल में प्रतिभाओं की कतार रही है। बंगाल के लेखक, कलाकार सत्ता के अन्याय का विरोध करते थे। रवींद्रनाथ ने अंग्रेजों की 'नाइटहुड' उपाधि लौटा दी थी, सत्ता का विरोध कर नजरुल जेल गए थे। आज का बंगाल क्या उसके अनुरूप है? अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर भी बंगाल में क्षोभ था। अनेक लोगों की धारणा थी कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़-फोड़, घरों और जमीनों पर जबरन कब्जे की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल पहुंचती रहीं। इस कारण पश्चिम बंगाल के अनेक हिंदुओं में मौलवियों की संख्या और उनके असर में हुई वृद्धि के कारण यह आशंका पैदा हुई कि राजनीतिक हित साधने के लिए कट्टरवाद को बढ़ावा देने से सामाजिक संतुलन नष्ट होगा। हिंदुओं में व्याप्त यह आतंक सच हो या अतिरंजित-चुनाव में इसका असर पड़ा हो, तो आश्चर्य नहीं।

दूसरी ओर, बांग्लादेश के कट्टरवादी समूहों ने भाजपा की बंगाल विजय को 'हिंदुत्व की जीत' बताते हुए आलोचना की है। यह उनके दोहरेपन का ही नमूना है। पृथ्वी के ज्यादातर ईसाई, यहूदी या हिंदू बहुसंख्यक देशों ने खुद की धर्मनिरपेक्ष छवि बनाई है। जबकि अनेक मुस्लिम बहुल देशों में इस्लाम ही राष्ट्रधर्म है। यह दोहरापन मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण में रोड़ा है।

पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक दिन वाम शासन को सत्ता से हटाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण माकपा के नेतृत्व में वाम मोर्चा का आम जनता से कोई संबंध नहीं रह गया है। उद्योग-धंधों के मोर्चे पर उदासीनता, पार्टीतंत्र और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाकर जनता ने वाम मोर्चे को हटाया था। उस जनक्षोभ के जरिये तृणमूल परिवर्तन के वादे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन समय के साथ-साथ अनेक लोगों की नजरों में तृणमूल भी उसी रास्ते पर चलने लगी थी। फर्क सिर्फ यह था कि उसने इन मामलों में ज्यादा दुस्साहस और आक्रामकता का परिचय दिया। मैं खुद इस राजनीति का शिकार बनी थी। माकपा ने कट्टरवाद के खिलाफ लिखी मेरी किताबों पर प्रतिबंध लगाया और मुझे पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए भी मजबूर किया था। तृणमूल ने भी मुझे वहां रहने नहीं दिया। मेरी किताबों के कार्यक्रम बंद किए गए, मेरी रचनाओं पर आधारित टीवी धारावाहिक के प्रसारण पर रोक लगाई गई। यह सिर्फ एक लेखक पर हमला नहीं था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रश्न पूछने के अधिकार पर हमला था। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हूं, न ही किसी दल की अंध समर्थक हूं। मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी आलोचना के दायरे से बाहर नहीं है। जो अच्छा काम करेगी, उसकी प्रशंसा और जो गलत काम करेगी, उसका विरोध करना होगा। नागरिकों का पहला दायित्व किसी दल के प्रति अंधभक्ति के बजाय अपने विवेक को जगाए रखना है।

लोगों ने चूंकि बदलाव की उम्मीदों से वोट दिया है, इसलिए उनकी उम्मीदें भी विराट हैं। वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, भय के माहौल पर विराम लगे, प्रशासन निरपेक्ष हो, नौकरियों में पारदर्शिता आए, उद्योग और निवेश बढ़े, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। वे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल एक बार फिर चिंतन, संस्कृति, कला, साहित्य एवं मानवीयता का उज्ज्वल दृष्टांत पेश करे। पर सिर्फ सरकार बदलने से समाज नहीं बदलता। समाज तब बदलता है, जब लोग खुद में बदलाव लाते हैं। पश्चिम बंगाल के सामने आज बड़ा सवाल है- क्या यह फिर अपने उदार, तार्किक और मानवतावादी स्वर्णिम दौर में लौटेगा या ध्रुवीकरण, घृणा और प्रतिशोध की राजनीति की ओर बढ़ेगा?

बंगाल ने कभी नवजागरण की दिशा दिखाई थी, उदार चिंतन का साहस दिया था, साहित्य और संस्कृति की नई भाषा दी थी। उस बंगाल से लोगों को आज भी उम्मीदें हैं। ऐसे में, सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ राजनीतिक संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ, तो इतिहास खुद को दोहराने के लिए अभिशप्त होगा और बंगाल के लोग बार-बार ठगे जाते रहेंगे।

जीवन धारा

ओरिसन स्वेट मार्डेन

बहुत-से लोग धन तो कमा लेते हैं, परंतु उस प्रक्रिया में आनंद लेने की अपनी क्षमता खो देते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए सुख खोजता है, वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता।

स्वार्थ और सुख एक साथ नहीं रह सकते

संसार के अधिकांश लोगों से उनके जीवन की तीन सबसे बड़ी इच्छाएं पूछी जाएं, तो वे स्वास्थ्य, धन और सुख का ही नाम लेंगे। यदि किसी से उसकी सर्वोच्च अभिलाषा पूछी जाए, तो वह निस्संदेह कहेगा, 'मैं सुख चाहता हूं।' वास्तव में हर मनुष्य निरंतर सुख की खोज में लगा हुआ है। चाहे वह स्वयं इस बात को स्पष्ट रूप से न समझे, फिर भी यह उसके जीवन का एक शक्तिशाली प्रेरक तत्व है। हम सब अपने जीवन को थोड़ा बेहतर, थोड़ा अधिक सहज और अधिक संतोषजनक बनाने का प्रयास करते रहते हैं। हम कठिनाइयों, परिश्रम और तनावपूर्ण परिस्थितियों से धीरे-धीरे मुक्ति पाने की चाह रखते हैं। किन्तु आश्चर्य की बात है कि जब से मानव सभ्यता का आरंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक सुख की खोज जारी है, फिर भी बहुत कम लोग वास्तव में इसे प्राप्त कर पाए हैं या इसकी सही परिभाषा समझ पाए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग सुख को गलत स्थानों पर खोजते हैं। सुख किसी शिकार की तरह नहीं है, जिसे दौड़ कर पकड़ा जा सके; यह तो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। सच्चा सुख अत्यंत सरल होता है, इतना सरल कि अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। यह जीवन की छोटी-छोटी, शांत, साधारण और विनम्र बातों में छिपा होता है। सुख कभी भी नीच विचारों, स्वार्थ, आलस्य या कलह में नहीं रहता। वह सत्य, सौंदर्य, प्रेम, सामंजस्य और सरलता का साथी है। बहुत से लोग धन तो कमा लेते हैं, परंतु उस प्रक्रिया में आनंद लेने की अपनी क्षमता खो देते हैं। अक्सर हम सुनते हैं, 'उसके पास पैसा तो है, लेकिन वह उसका आनंद नहीं ले सकता।' जो व्यक्ति केवल अपने लिए सुख खोजता है, वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। स्वार्थ और सुख एक साथ नहीं रह सकते। सुख का वास्तविक स्रोत दूसरों के कल्याण में निहित है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। जो लोग केवल अपनी इच्छाओं और सुविधाओं के बारे में सोचते रहते हैं, वे अंततः निराश ही होते हैं। सुख मानो जुड़वां के समान है- दूसरों का भला चाहने वाला ही उसे पा सकता है।

यह एक भ्रम है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्ष केवल धन कमाने में लगा दे, संबंधों, आत्मविकास और जीवन के वास्तविक मूल्यों की उपेक्षा करे, और फिर अंत में सुख की अपेक्षा रखे। यदि उसने अपने भीतर सुंदरता, सत्य और अच्छाई को महसूस करने की क्षमता को जीवित नहीं रखा, तो बाद में वह उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या बदले की भावना रखता है, वह कभी भी वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में छिपा होता है। जब हम सही कार्य करते हैं, सच्चाई का पालन करते हैं और दूसरों के जीवन में आनंद लाते हैं, तभी हम स्वयं भी गहरे और स्थायी सुख का अनुभव करते हैं।

-द जॉय ऑफ लिविंग के अनूदित अंश

अपने विचारों को मजबूत करें

सूत्र

सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में छिपा होता है, जब हम स्वार्थ त्यागकर सत्य, प्रेम और सद्भावना के साथ दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं, तभी हमारे भीतर स्थायी आनंद जन्म लेता है, और यही वह सच्ची संतुष्टि है जो जीवन को सार्थक, शांत और वास्तव में पूर्ण बनाती है।

दूसरा पहलू

यह दावा कि फल और सब्जियां युवा लोगों में फेफड़ों के कैंसर की वजह बन सकती हैं, स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाला है।

क्या वाकई फल और सब्जियों में कैंसर छिपा है

यह विचार कि फल और सब्जियां कैंसर का कारण बन सकती हैं, सुनने में अजीब लगता है! दशकों से किए गए शोध लगातार यह बताते आए हैं कि जो लोग अधिक मात्रा में पौधों पर आधारित भोजन करते हैं, वे सामान्यतः अधिक स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। उनमें हृदय रोग, स्ट्रोक और कई प्रकार के कैंसर का खतरा भी कम पाया जाता है। ऐसे में यह दावा कि फल और सब्जियां युवा लोगों में फेफड़ों के कैंसर की वजह बन सकती हैं, स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाला है। दरअसल, यह चिंता किसी बड़े और ठोस शोध से नहीं, बल्कि एक छोटे अध्ययन से उत्पन्न हुई है, जिसमें केवल 187 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था, जिन्हें कम उम्र में फेफड़ों का कैंसर हुआ। इनमें से अधिकांश धूम्रपान नहीं करते थे। जब उनके खानपान के बारे में पूछा गया, तो कई लोगों ने बताया कि वे फल, सब्जियां और साबुत अनाज भरपूर मात्रा में लेते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अध्ययन में कीटनाशकों का सीधा मापन नहीं किया गया। शोधकर्ताओं ने केवल औसत आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया कि इन खाद्य पदार्थों में मौजूद संभावित कीटनाशक कैंसर से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना कि फल और सब्जियां खुद हानिकारक हैं, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। यह अध्ययन पहले से बीमार लोगों को देखकर उनकी आदतों का अनुमान लगाकर किया गया था। इस प्रकार के अध्ययन यह साबित नहीं कर सकते कि बीमारी का कारण क्या था। इसके विपरीत, बड़े और दीर्घकालिक अध्ययन हजारों लोगों को वर्षों तक ट्रैक करते हैं और अधिक विश्वसनीय परिणाम देते हैं।

जस्टिन स्टेबिंग

शोध तो यह दिखाते हैं कि अधिक फल और सब्जियां खाने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और कैंसर का जोखिम घटता है।

जहां तक कीटनाशकों की बात है, यह सही है कि उसके कुछ अवशेष फल व सब्जियों पर रह सकते हैं। जो लोग लंबे समय तक और अधिक मात्रा में इनके संपर्क में रहते हैं, उनमें कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

ऐसे शोध बार-बार दिखाते हैं कि अधिक फल और सब्जियां खाने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और कैंसर का जोखिम घट सकता है। छोटे अध्ययनों में अक्सर संयोग और अन्य कारकों का प्रभाव ज्यादा होता है। जहां तक कीटनाशकों की बात है, यह सही है कि उसके कुछ अवशेष फल और सब्जियों पर रह सकते हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग लंबे समय तक और अधिक मात्रा में इनके संपर्क में रहते हैं, जैसे किसान, उनमें कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य मात्रा में फल और सब्जियां खाने से आम लोगों को कैंसर होता है। संतुलित और पौधों पर आधारित आहार ही बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सबसे भरोसेमंद विकल्प बना रहता है। -द कन्वर्सेशन

आंकड़े

भारत में डाटा सेंटर

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार में डाटा सेंटर अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत में डाटा सेंटर क्षमता वृद्धि में मुंबई 44 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है।

शहर	प्रतिशत
मुंबई	44
चेन्नई	27
दिल्ली	15
कोलकाता	5
हैदराबाद	4

आंकड़े डाटा सेंटर के प्रतिशत में। | स्रोत : कोलियर्स

अनुचित दंड देने के कारण ऋषि मांडव्य ने यमराज को श्राप दिया, जिसके परिणामस्वरूप यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया।

कर्म का फल

पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऋषि मांडव्य एक महान तपस्वी थे, जो अपने आश्रम में गहन ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन कुछ चोर राजकोष लूटकर भागते हुए उनके आश्रम में आ छिपे। सैनिक पीछा करते हुए वहां पहुंचे और खोजबीन में चोरी का धन आश्रम में मिल गया। सैनिकों ने मांडव्य ऋषि को ही दोषी मान लिया और उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने बिना सत्य की पड़ताल किए उन्हें मृत्युदंड सुना दिया। ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु उनके तपोबल के चलते प्राण नहीं निकले।

जब यह बात राजा को ज्ञात हुई, तो उसने ऋषि से क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने उसे क्षमा तो कर दिया, परंतु न्याय के लिए वह यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने प्रश्न किया कि बिना अपराध के उन्हें इतना कठोर दंड क्यों मिला। यमराज ने उत्तर दिया कि बचपन में उन्होंने एक छोटे जीव को कष्ट पहुंचाया था, उसी कर्म का फल उन्हें मिला। यह सुनकर मांडव्य ऋषि ने कहा कि अज्ञानावस्था में किए गए छोटे पाप के लिए इतना कठोर दंड देना अन्याय है। यह शास्त्रों के विरुद्ध है।

अंतर्यात्रा
संकलित

अतः उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि वह मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। उसी श्राप के फलस्वरूप यमराज का जन्म कुरु वंश में दासी-पुत्र विदुर के रूप में हुआ।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 12 मई, 1960

भ्रष्टाचारी अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश

भ्रष्टाचारी अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के आदेश

कुछ पुलों के निर्माण कार्य में बड़ी अनियमितता पाई गई थी। इसके बाद गृहमंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने प्रशासन के निगरानी विभाग को सभी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने व भ्रष्टाचारी अफसरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

अब बाजार का अनुभव बदल गया है

अब ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियां मिनटों में जरूरी सामान को घरों तक पहुंचाकर देश के रोजगार क्षेत्र के साथ बाजार के स्वरूप को भी बदल रही हैं।

मधुरेन्द्र सिन्हा | **वाणिज्य**

भारत में उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री लंबे समय से हो रही थी, लेकिन जब कोविड महामारी फैली, तो फिर इसमें जबर्दस्त तेजी आई। तब लोगों को समझ में आया कि आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन क्या जादू कर सकता है। कच्चे माल की आपूर्ति, कारखानों में तैयार उत्पादों को डीलरों तक भेजना और फिर ग्राहकों तक पहुंचाना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देश के किसी भी कोने से कहीं भी कोई सामान खरीदा-बेचा जा सकता है और यह कमाल कर रही हैं ई-कॉमर्स कंपनियां। इन्होंने देश ही नहीं, दुनिया में व्यापार करने का तरीका बदल दिया।

यह ऐसा व्यापार है, जिसमें ग्राहकों को विक्रेता का पता नहीं होता, पर यह यकीन होता है कि उसे सही चीज सही कीमत पर मिल रही है। अगर पसंद नहीं है, तो सामान वापस। इसके अलावा सुरक्षित भुगतान। यानी ग्राहकों को मालूम है कि उसका पैसा सुरक्षित है। इनकी

डिलिवरी भी बहुत तेज और समय पर होती है। यह ऐसी दुनिया है, जिसमें ग्राहक राजा है, क्योंकि उसे एक ही चीज के सैकड़ों विकल्प मिलते हैं। यही कारण है कि 2024 में भारत का ई-कॉमर्स बाजार 147.3 अरब डॉलर का हो गया और इसमें 18.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो मार्ट, टाटा क्लिक वगैरह ऐसी कंपनियां हैं, जो अरबों रुपये का सामान बेचती हैं और उनके ग्राहक लगातार बढ़ते हैं।

भारत में स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सस्ते होने से लोगों के सोचने व खरीदारी के तरीके बदलने के चलते यह बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ये कंपनियां सुई से लेकर मोटर कार तक ऑनलाइन बेच रही हैं। अब इनकी पैठ छोटे शहरों तक हो गई है। उम्मीद है कि 2027 तक ई-कॉमर्स के 40 करोड़ ग्राहक होंगे। एक अनुमान है कि 2030 तक इनकी कुल बिक्री 250 से 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसने देश में खपत को बढ़ावा दिया है, जिसका सकारात्मक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

स्वदेशी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की शुरुआत एक किताबों की दुकान के रूप में हुई थी, जो एक व्यापक ऑनलाइन बाजार के रूप में विकसित हुई। इसने कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) जैसी क्रांतिकारी सुविधाएं पेश कीं, जिन्होंने ऑनलाइन खरीदारी को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई।

व्यापार के इस खेल मे अब क्विक कॉमर्स कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसी कंपनियां मिनटों में जरूरी सामान ग्राहकों के घर पर पहुंचा देती हैं। इसी का नतीजा है कि ये ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अब टक्कर दे रही हैं। इनके कारोबार में वृद्धि सालाना 40 फीसदी की दर से हो रही हैं और एक मोटे अनुमान के अनुसार, इस साल इनका कुल कारोबार लगभग सात अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कॉर्नेल एससी जॉनसन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्विक कॉमर्स का भारत में कारोबार इस साल (2026) बढ़कर 65,645.40 करोड़ हो गया है। 2022 की तुलना में यह बढ़ोतरी 24 गुना है। बेन ऐंड कंपनी की एक रिपोर्ट बताती है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों के ऑर्डर 2024 में उल्लेखनीय तरीके से बढ़े। देश के कुल ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर का दो-तिहाई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हुआ था। ई-कॉमर्स बाजार में क्विक कॉमर्स कंपनियों ने पकड़ बना ली है, क्योंकि लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारा ई-कॉमर्स परिदृश्य देश की दृढ़ता, नवाचार और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों से लेकर सिख एक्सेसरीज डॉट कॉम जैसे विशिष्ट प्लेटफॉर्म तक, ने उपभोक्ता अनुभव को नया रूप देने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में अपना अनूठा योगदान दिया है।

सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनियां बड़े पैमाने पर रोजगार दे रही हैं। पीआईएफ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों ने पिछले साल 1.58 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। इनमें 35 लाख महिलाएं हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां आम वेंडरों की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। थ्री टायर शहरों में ग्राहक औसतन 5,000 रुपये से ज्यादा की ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, जो बड़े शहरों से कहीं ज्यादा है। ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ डिलिवरी बॉय ही नहीं नियुक्त करतीं, बल्कि स्किल्ड लोगों को भी रोजगार देती हैं। ये कंपनियां वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फाइनेंस वगैरह में भी बड़े पैमाने पर रोजगार दे रही हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार और बढ़ेगा, इनका कारोबार भी बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स कंपनियां सुनियोजित तरीके से काम करती हैं।

edit@amarujala.com

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

रेलवे बोर्ड में निकली भर्ती

असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर रिक्तियां

11,127 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 14 जून, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष
यहां आवेदन करें : rrbapply.gov.in

एनवीएस, लखनऊ ■ 217 पद

पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन व स्टाफ नर्स के पद रिक्त

आवेदन की अंतिम तिथि : 18 मई, 2026
पात्रताएं : ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन व अन्य योग्यताएं
यहां आवेदन करें : nvsrolko.org

उत्तराखंड होम गार्ड में मौके ■ 152 पद

होमगार्ड स्वयंसेवक के पदों पर आवेदन आमंत्रित

आवेदन की अंतिम तिथि : 22 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष
यहां आवेदन करें : dehradun.nic.in/

यूकेएसएसएससी की अधिसूचना ■ 120 पद

पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर संभावनाएं

आवेदन की अंतिम तिथि : 02 जून, 2026
वेतनमान : रुपये 35,400 से रुपये 1,12,400 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : sssc.uk.gov.in

एम्स, ऋषिकेश में मौके ■ 119 पद

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पद रिक्त

आवेदन की अंतिम तिथि : 18 मई, 2026
पात्रताएं : एमडी, एमएस व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : aiimsrishikesh.edu.in

भारतीय वन्यजीव संस्थान ■ 20 पद

प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट एसोसिएट आदि पद खाली

आवेदन की अंतिम तिथि : 22 मई, 2026
वेतनमान : रुपये 30,000 से रुपये 1,20,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : wii.gov.in

यहां भी हैं रोजगार की संभावनाएं...

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक : स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद खाली।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 29 मई, 2026
- sidbi.in/en/

राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान : अधीक्षक (लेखापरीक्षा) और तकनीशियन (फिटर) के पद रिक्त।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 31 मई, 2026
- rgipt.ac.in/

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

जब आप सवाल के लिए तैयार न हों

ऑफिस में अचानक पूछे गए सवालों का शांत और स्पष्ट जवाब देना आपके आत्मविश्वास और पेशेवर रुख को दर्शाता है

मेलोडी विल्डिंग
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

ऑफिस में काम करते समय कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, जब कोई प्रबंधक या एग्जीक्यूटिव अचानक आपसे कोई सवाल पूछ लेता है। यह सवाल किसी प्रोजेक्ट की प्रगति, किसी गलती, डाटा, या भविष्य की योजना से जुड़ा हो सकता है। ऐसे समय में कई लोग घबरा जाते हैं, जल्दी-जल्दी बोलने लगते हैं या गलत जानकारी दे बैठते हैं। लेकिन सही तरीका अपनाकर आप इस स्थिति को अपने आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म दिखाने के अवसर में बदल सकते हैं। इस तरह, जब कोई एग्जीक्यूटिव आपसे अचानक सवाल पूछे, तो घबराने के बजाय संयम, स्पष्टता और ईमानदारी के साथ जवाब दें। यही गुण एक अच्छे पेशेवर की पहचान होता है।

Harvard Business Review

■ सवालों को ध्यान से सुनें

जब कोई प्रबंधक या एग्जीक्यूटिव आपसे अचानक सवाल पूछता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अक्सर सिर्फ काम की स्थिति या प्रोजेक्ट की जानकारी समझना चाहते हैं। जवाब देने से पहले एक से दो सेकंड रुककर सोचें, ताकि आप सही और स्पष्ट उत्तर दे सकें। सवाल को ध्यान से सुनें और पूरा समझें। अगर सवाल साफ न हो, तो उसे विनम्रता से दोबारा पूछना बिल्कुल सही है, जैसे-क्या आप इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? ऐसा करने से आपकी समझदारी और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल बेहतर दिखती है।

■ भरोसेमंद जानकारी दें

जब कोई सीनियर आपसे सवाल पूछे, तो केवल वही जानकारी दें, जो आपको सही तरीके से पता हो। कई लोग जल्दी प्रभावित करने के लिए अंदाजा लगाकर जवाब दे देते हैं, लेकिन अगर वह जानकारी गलत निकली तो विश्वसनीयता कम हो सकती है। इसलिए गलत जवाब देने से बेहतर है कि आप ईमानदारी से कहें कि मैं सटीक जानकारी जांच करके आपको तुरंत अपडेट करता हूं।

■ दबाव में शांत रहें

जब प्रबंधक सवाल पूछे, तो सिर्फ आपके शब्द ही नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आंखों में देखकर, साफ और शांत आवाज में जवाब देने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहीं घबराहट या डर दिखाने से आत्मविश्वास कम नजर आता है। शांत व्यवहार यह दिखाता है कि आप दबाव वाली परिस्थितियों को भी समझदारी से संभाल सकते हैं।

- *ऐसे समय में घबराने के बजाय स्थिति को आत्मविश्वास और प्रोफेशनल तरीके से संभालने की कोशिश करें।*
- *सवाल सुनते समय शांत रहें और जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुककर सोचें।*
- *अगर सवाल स्पष्ट न हो, तो विनम्रता से उसे दोबारा पूछें ताकि सही समझ बन सके।*

■ जवाब को छोटा रखें

जवाब हमेशा छोटा, स्पष्ट और व्यवस्थित होना चाहिए। लंबे और उलझे हुए जवाब देने के बजाय सीधे मुद्दे पर बात करें। पहले समस्या, फिर उसका कारण और अंत में समाधान बताने से सामने वाला आपकी बात आसानी से समझ पाता है। हर सवाल को सीखने का अवसर मानना चाहिए। अगर किसी सवाल का जवाब न पता हो, तो उसकी तैयारी करें।

फेलोशिप प्रोग्राम

रोटरी पीस फेलोशिप

- **पात्रताएं :** स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
- **अनुभव व कौशल :** अंतरराष्ट्रीय शांति और समझ से संबंधित पेशेवर और शैक्षणिक उपलब्धियां और व्यक्तिगत या सामुदायिक सेवा का अनुभव हो। साथ ही, अंग्रेजी में निपुणता प्राप्त हो।
- **आवेदन लिंक :** rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships
- **अंतिम तिथि :** 15 मई, 2026

अंतरराष्ट्रीय पहल

पोस्टर हीरोज कॉन्टेस्ट

- **उद्देश्य :** प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना ही नहीं, बल्कि इसके प्रभावों और कल्पनाओं को दृश्यमान बनाना है।
- **पुरस्कार :** फेविनी मेंशन : 2,500 यूरो व फोंडाजियोन टाइम टू मेंशन : 1,500 यूरो
- **आवेदन की अंतिम तिथि :** 31 जुलाई, 2026
- **आधिकारिक वेबसाइट :** posterheroes.org

इंटर्नशिप अलर्ट

ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

- **संस्थान :** विदेश व्यापार महानिदेशालय
- **पात्रताएं :** लोक नीति/अर्थशास्त्र/वित्त/प्रबंधन/कानून में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- **लाभ :** इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र।
- **आवेदन लिंक :** dgft.gov.in/
- **अंतिम तिथि :** 17 मई, 2026

आवेदन आमंत्रित

फार्म रेजीडेंसी प्रोग्राम-2027

- **पात्रताएं :** आप एक व्यक्तिगत दृश्य कलाकार हों।
- **आयु :** न्यूनतम 18 वर्ष
- **अवधि :** आठ हफ्ते
- **लाभ :** 15,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की फीस से रेजीडेंसी के दौरान रहने और परियोजना से संबंधित खर्चों में सहायता मिलेगी।
- **आवेदन लिंक :** tinyurl.com/2h48c95y
- **अंतिम तिथि :** 01 जून, 2026

खुद को परखें

1. यिल्दिरिमहान मिसाइल किस देश ने विकसित की?
(a) ईरान (b) इस्राइल
(c) तुर्की (d) रूस

2. छाई उल्सूर झील किस शहर में स्थित है?
(a) बंगलूरू (b) चेन्नई
(c) हैदराबाद (d) मुंबई

3. भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था?
(a) नई दिल्ली (b) चेन्नई
(c) हैदराबाद (d) बंगलूरू

4. हाल ही में खबरों में रहने वाली साइफोस्टेम्मा अन्नामलाई क्या है?
(a) हाल ही में खोजी गई पादप प्रजाति
(b) एक प्रकार का कवक
(c) आक्रामक खरपतवार
(d) एक प्रकार का विषाणु

उत्तर-1.c, 2.a, 3.a, 4.a

12 मई, 2008

आज का दिन

चीन में आए विनाशकारी भूकंप ने 87 हजार लोगों की जान ले ली थी। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में हजारों लोग लापता और बेघर हो गए थे।

- 1847 : विलियम क्लेटन ने ओडोमीटर का आविष्कार किया।
- 1926 : रोनाल्ड अमुंडसेन, लिंकन एल्सवर्थ और अम्बर्टो नोबिल ने उत्तरी ध्रुव पर पहली उड़ान भरी थी।
- 1944 : भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता घनश्याम नायक का जन्म हुआ था।
- 1993 : हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी।
कल : अपरा एकादशी व्रत, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : दिन में 12.00 से 13.30 तक।

- सूर्योदय : 05.36
- सूर्यास्त : 18.59

(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 23 वैशाख मास शक 1948, वैशाख मास 30 प्रविष्टे, 25 जिल्काद हिजरी 1447, प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी 13.29 तक उपरांत द्वादशी, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र 24.17 तक उपरांत रेवती नक्षत्र, विष्कुम्भ योग 20.54 तक उपरांत प्रीति योग,बालव करण 13.29 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा मीन राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : भाग्य सहायक रहेगा। योजना में सफलता मिलेगी। आय का नया स्रोत बन सकता है।

वृष : स्वजन सहयोग मिलेगा। विवाह वार्ता चल सकती है। नौकरी में व्यस्तता बढ़ेगी। विरोधी परास्त होंगे।

मिथुन : मन में आशा का संचार होगा। अटका कार्य बन सकता है। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।

कर्क : दिनमान प्रतिकूल रहेगा। अनैतिक कार्यों से बचें। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। विरोधी से बचें।

सिंह : दिनमान सहायक रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र में रुचि रहेगी। रोजगार प्राप्ति का अवसर मिलेगा।

कन्या : राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में उन्नति के संकेत मिलेंगे। विरोधी परास्त होंगे।

तुला : मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। किसी कार्य में साहसिक निर्णय लेंगे। नौकरी में नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।

वृश्चिक : पूर्वनियोजित कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्य भार बढ़ सकता है।

धनु : लोकप्रियता में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा।

मकर : मन अशांत रहेगा। नौकरी में अनावश्यक परेशानी संभव है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

कुंभ : मनोइच्छा पूर्ति का अवसर मिल सकता है। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। अटका धन मिल सकता है।

मीन : राजनीतिक संबंध सहायक रहेंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर मिल सकता है। वाद-विवाद से बचें।

सुडोकू

		2				9		1
			3				6	
			5		1	7	3	
	3				4			9
1								3
4			6				2	
	9	6	4		2			
	4				5			
7		1				2		

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

3	5	2	7	4	6	9	8	1
9	1	7	3	2	8	4	6	5
8	6	4	5	9	1	7	3	2
6	3	8	2	1	4	5	7	9
1	2	9	8	5	7	6	4	3
4	7	5	6	3	9	1	2	8
5	9	6	4	8	2	3	1	7
2	4	3	1	7	5	8	9	6
7	8	1	9	6	3	2	5	4

तारीख पर तारीख के लिए सरकार व पुलिस जिम्मेदार

हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ और पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली पर उठाए सवाल

संवाद न्यूज एजेंसी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ के लिए सरकार और पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने फिल्म दामिनी के संवाद का जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों पर लगा तारीख पर तारीख का दाग तब तक नहीं हटेगा, जब तक सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी।

इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत ने आगरा के मेवालाल की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अदालतों में लंबित मुकदमों की समस्या का कारण प्रशासनिक कमियां हैं। ट्रायल कोर्ट में पेशकार, आशुलिपिक और अन्य अनुसचिवीय कर्मचारियों की बड़ी कमी है। इस कारण एक-एक लिपिक हजारों फाइलों का बोझ संभाल रहा है। उधर, पुलिस अदालती समन और वारंट समय पर तामील करने में विफल हो रही है। गवाहों और पुलिस अधिकारियों का अदालत में पेश न होना देरी का एक बड़ा कारण है।

कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि जिला पुलिस प्रमुखों और कमिश्नरों को जिला जज की अध्यक्षता वाली मॉनिटरिंग सेल की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति न्यायिक प्रोटोकॉल का अपमान है।

आधुनिक मशीनों की कमी, रिपोर्ट आने में लगता है समय

- कोर्ट ने कहा सच्चाई यह है कि एक न्यायाधीश तब तक मामले का फैसला नहीं कर सकता जब तक पुलिस अभियुक्तों और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित न करे। समय पर सही फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध न कराई जाए। इन्हीं तमाम वजहों से देरी होती है और तारीख पर तारीख एक धारणा बन गई है।
- कोर्ट ने पाया कि फॉरेंसिक लैब की स्थिति दयनीय है। वहां आधुनिक मशीनों और स्टाफ की कमी के कारण रिपोर्ट आने में लंबा समय लगता है। वर्तमान में यूपी की फॉरेंसिक लैब पुलिस विभाग का हिस्सा हैं, जिससे वे प्रशासनिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने इन्हें गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त विभाग बनाने का सुझाव दिया है।

साइको किलर ने 24 घंटे में तीन हत्याएं कीं, देर रात मुठभेड़ में ढेर

सीन रीक्रिएशन के दौरान आरोपी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने में मारा गया

पीडीडीयू नगर (चंदौली)। चंदौली जिले में 24 घंटे में तीन हत्याओं को अंजाम देने वाले साइको किलर की मुठभेड़ में मौत हो गई। रात करीब 11 बजे दरियापुर में सीन रीक्रिएशन के दौरान वह पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था। आरोपी के सीने और पेट में दो गोलियां लगी हैं। इस दौरान एसआई और जीआरपी सिपाही घायल हुए हैं।

डीआईजी वाराणसी रेंज वैभव कृष्ण के मुताबिक अमृतसर के रहनेवाले गुरप्रीत सिंह ने पहली वारदात रविवार सुबह 6.45 पर पैसेंजर ट्रेन में अंजाम दी थी। जिसमें आरोपी ने ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में चढ़कर गाजीपुर के रहने वाले 34 साल के मंगरू की हत्या कर दी थी। इसके बाद वो 10 मई की रात 1:30 बजे जम्मूतवी एक्सप्रेस में सवार हुआ और बिहार के गया के दिनेश साहू पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद वो पैदल घूमता रहा, सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे मुगलसराय के जीवक अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर से इलाज कराने के लिए पर्ची बनवाई और उसके बाद वार्ड में घुस गया। वहां भर्ती महिला लक्ष्मीना देवी के सिर पर रिवॉल्वर रखकर गोली चला दी। वारदात के बाद भाग रहे आरोपी को वॉर्ड बॉय और बाकी लोगों ने पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया था। उसके पास से पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर, डबल बैरल बंदूक और कारतूस बरामद किए थे। आरोपी ने तीन हत्याएं करने की बात कबूली थी। पूछताछ में सामने आया था कि गुरप्रीत सिंह ने 2021 में सेना की नौकरी छोड़ दी थी। संवाद

एसआईआर का तीसरा चरण जल्द 40 करोड़ मतदाता

नई दिल्ली। चुनाव आयोग जल्द ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तीसरे चरण को शुरू करने जा रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इसमें देश के शेष 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, जिनमें लगभग 40 करोड़ मतदाता हैं।

चुनाव प्राधिकरण ने पिछले महीने केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के कारण इसे शुरू करने में देरी की थी। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो अब एसआईआर को शुरू किया जा सकता है। अब तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान समेत 10 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असम में मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन किया गया। तीसरे चरण के साथ ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभियान पूरा हो जाएगा। एजेंसी

जमानत याचिकाओं के निपटारे में देरी से मौलिक अधिकार प्रभावित

शीर्ष कोर्ट ने कहा-हाईकोर्ट तय समयसीमा में करें निपटारा...स्वत: सुनवाई व्यवस्था विकसित करें

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में लंबित जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई। साथ ही, यह अंबार जल्द खत्म करने के लिए स्वतः सुनवाई व्यवस्था विकसित करने और याचिकाओं के निपटारे की समयसीमा निर्धारित करने जैसे सुझाव भी दिए।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जमानत मामलों की सुनवाई में देरी न्याय व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है और इससे आरोपियों के मौलिक अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट, राज्य सरकारें और जांच एजेंसियां जमानत याचिकाओं के समय पर निपटारे की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगी। साथ ही, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करेंगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश को हाईकोर्ट के कामकाज में दखल के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये सुझाव व्यवस्था की दक्षता को मजबूत करने के मकसद से दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ सनी चौहान बनाम पंजाब राज्य मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस मामले में विभिन्न हाईकोर्ट से लंबित जमानत मामलों का ब्योरा मांगा था। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है जिससे हर जमानत याचिका को निश्चित सुनवाई तिथि मिल सके। अदालत ने सरकारी वकीलों द्वारा अनावश्यक स्थगन मांगने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई।

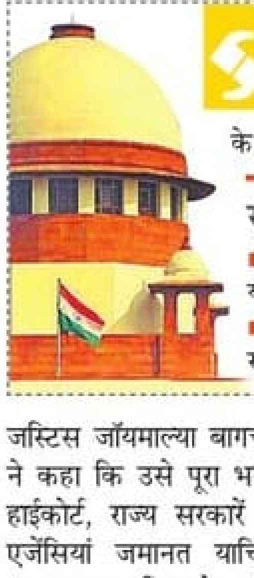

याचिकाएं दोबारा स्वत: सूचीबद्ध हों...जिन मामलों की सुनवाई नहीं हो सके, उन्हें स्वत: दोबारा सूचीबद्ध किया जाए। जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जाए। **- कोर्ट**

सुप्रीम कोर्ट का इन पहलुओं पर भी जोर

- जमानत मामलों की स्वत: सुनवाई की सूची साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर तैयार करने की व्यवस्था पर जोर।
- पहली सुनवाई से पूर्व स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने व राज्य या केंद्र सरकार के वकीलों को अग्रिम सूचना दें।

लंबित मामलों की स्थिति चिंताजनक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ उच्च न्यायालयों में लंबित जमानत याचिकाओं की संख्या अब भी अत्यधिक है।

- इलाहाबाद हाईकोर्ट का विशेष रूप से जिक्र करते हुए अदालत ने कहा, वहां लंबित जमानत याचिकाओं की संख्या बहुत अधिक है, जबकि न्यायाधीश प्रतिदिन सैकड़ों मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट में जमानत मामलों के महीनों तक लंबित रहने पर भी चिंता जताई।
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पिछले वर्ष 63 हजार से अधिक लंबित जमानत याचिकाओं की स्थिति को भी पीठ ने चिंताजनक बताया।

बिग कैट अलायंस सम्मेलन में आने की 14 देशों ने की पुष्टि

एक व दो जून को होने जा रहा सम्मेलन, भारत की वैश्विक पहल में सऊदी अरब बनेगा 26 वां सदस्य

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एक और दो जून को अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 (आईबीसीए) में आयोजित किया जाएगा। बड़ी बिल्लियों, मानवता और पारिस्थितिक तंत्र को बचाएं थीम वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दुनिया के 14 देशों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि की है। पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इस बीच, सऊदी अरब भारत के नेतृत्व वाले आईबीसीए का 26वां सदस्य बनने की तैयारी में है।

सऊदी अरब के इस गठबंधन में शामिल होने से आईबीसीए के ढांचे के तहत वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। सम्मेलन में भारत ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 95 बिग कैट रेंज देशों को आमंत्रित किया है, ताकि बड़ी वन्य बिल्लियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत किया जा सके। एजेंसी/ब्यूरो

25 सदस्य देश और पांच पर्यवेक्षक राष्ट्र शामिल : वर्तमान में इसमें 25 सदस्य देश और पांच पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। आईबीसीए के 25 सदस्य देशों में भारत सहित अंगोला, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इरिट्रिया, एस्वातीनी, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, गिनी, केन्या, लाइबेरिया, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, नाइजर, पैराग्वे, रूस, रवांडा, सोमालिया और श्रीलंका शामिल हैं। पर्यवेक्षक देशों में कजाकिस्तान, नामीबिया, थाईलैंड, इक्वाडोर और वियतनाम शामिल हैं।

यूपी में आयातित ब्राह्मणों पर आश्रित हुई भाजपा योगी सरकार के 8 ब्राह्मण मंत्रियों में 5 बाहरी

जितिन केंद्र में बने मंत्री तो उनकी जगह मनोज पांडे को मिला मौका

हिमांशु मिश्र

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की करीब सौ सीटों पर प्रभावशाली उपस्थिति रखने वाले ब्राह्मण बिरादरी को साधे रखने के लिए भाजपा दूसरे दलों से आयातित नेताओं के भरोसे है। राज्य में 2022 में पहली बार अपनी सत्ता बरकरार रखने वाली भाजपा की सरकार में आठ ब्राह्मण मंत्रियों में से पांच दूसरे दलों से आयातित हैं। बीते लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद के केंद्र में मंत्री बनने के बाद रविवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में सपा से आए मनोज पांडे को योगी सरकार में जगह दी गई है।

वर्तमान स्थिति की बात करें तो मंत्रिमंडल में शामिल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रतिभा शुक्ला बसपा से, मनोज पांडे, रजनी तिवारी सपा से और दयाशंकर मिश्र दयालू कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए थे। साल 2022 में दोबारा सरकार बनने पर कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जैसा अहम विभाग मिला था। हालांकि बाद में प्रसाद जब केंद्र में मंत्री बने तो सपा से आए मनोज पांडे को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली।

पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं से महज तीन नाम : योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में सतीश चंद्र शर्मा, सुनील शर्मा और योगेंद्र उपाध्याय को ही मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बीती सरकार में बेहद अहम ऊर्जा विभाग संभालने वाले श्रीकांत शर्मा को दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जबकि डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को राज्यसभा भेजा गया।

ऐसी रणनीति क्यों?

दरअसल 10 से 13 फीसदी आबादी वाली ब्राह्मण बिरादरी का राज्य में मुख्य रूप से पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड में व्यापक उपस्थिति है। यह बिरादरी सौ से अधिक सीटों पर हार-जीत के निर्णय में अहम भूमिका निभाती है। बीते कई चुनावों में इस बिरादरी ने राज्य के चुनाव परिणाम को तय करने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में पार्टी की रणनीति अलग-अलग क्षेत्रों के बिरादरी के कद्दावर नेताओं को साधने की रही है।

पुनर्मतगणना के नतीजे पर सुप्रीम रोक, कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा होंगे श्रृंगेरी के विधायक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्मतगणना के नतीजों पर रोक लगाते हुए कर्नाटक के श्रृंगेरी से कांग्रेस विधायक टीडी राजेगौड़ा को ही विजेता घोषित किया। हाल ही में हुई पुनर्मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार डीएन जीवराज को विधानसभा सीट से विजेता घोषित किया गया था। जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस केवी चंद्रन की पीठ ने यथास्थिति (पुनर्मतगणना से पहले की स्थिति) बहाल करने का निर्देश दिया, साथ ही यह भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से पहले से मान्य डाक मतपत्रों का पुनः सत्यापन करना प्रथम दृष्टया अवैध था। पीठ ने राजेगौड़ा को ही विधायक के रूप में बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से संबंधित है, जहां कांग्रेस के राजेगौड़ा को श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र से 201 वोटों के मामूली अंतर से विजेता घोषित किया गया था। बाद में भाजपा उम्मीदवार जीवराज ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनाव याचिका के माध्यम से इस परिणाम को चुनौती दी। एजेंसी

सीजेआई ने की एक मामला एक डाटा पहल की घोषणा

एआई चैटबॉट सु सहाय की शुरुआत का भी किया एलान

नई दिल्ली। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायिक डाटा एकीकरण को मजबूत करने और देश भर की अदालती सेवाओं तक जनता की पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से सोमवार को एक बड़ी डिजिटल पहल की घोषणा की। न्यायालय की कार्यवाही शुरू होते हुए सीजेआई ने घोषणा की कि न्यायपालिका 'एक मामला एक डाटा' (वन केस वन डाटा) पहल शुरू कर रही है।

सीजेआई ने कहा, हम 'एक मामला एक डाटा' पहल शुरू कर रहे हैं जिसमें सभी उच्च न्यायालयों, जिला और तालुका अदालतों की बहुस्तरीय जानकारी शामिल होगी। हम एक कुशल केस प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पहल से देश भर की अदालतों में एक अधिक व्यापक और परस्पर जुड़ा हुआ डिजिटल डाटाबेस बनाकर केस प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है। सीजेआई ने 'सु सहाय' नामक एक एआई-संचालित सहायता चैटबॉट की शुरुआत की भी घोषणा की। इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया गया है। एजेंसी

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 12-05-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMTEN User: arvind.yadav1@timesofindia.com Time: 05-11-2026 22:51 Color:

ऊर्जा स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

ऊर्जा में आत्मनिर्भरता!

पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और EV का इस्तेमाल करने की अपील की, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम की जा सके। यह अपील पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे संकट का नतीजा है और तय था कि गतिरोध लंबा खिंचने की सूरत में कुछ एहतियाती उपाय तो करने ही होंगे। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है।

कई उपाय करने होंगे

रुपये पर दबाव । पीएम ने पेट्रोल-डीजल के कम इस्तेमाल के साथ एक साल तक सोना न खरीदने और गैस व फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों पर भी बात की। इन सभी के लिए भारत आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कीमतें बढ़ रही हैं और देश को अपनी जरूरत के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। इससे रुपये पर दबाव बढ़ रहा है, जो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है।

महंगा होता क्रूड । जब अमेरिका-इस्राइल ने ईरान पर हमला किया, तब क्रूड ऑयल 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था और अब यह 100 के पार है। तेल मार्केटिंग कंपनियों पर हर दिन 1600 से 1700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जो अभी तक उपभोक्ताओं पर नहीं आया है। लेकिन, ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता। जब होर्मुज स्ट्रेट में तनाव जल्द कम होने की उम्मीद नहीं दिख रही, तब विकल्पों की ओर बढ़कर आर्थिक दबाव से निपटा जा सकता है।

रिन्यूबल का रेकॉर्ड । कार पूलिंग, वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम फौरी तौर पर भले कुछ राहत दें, लेकिन देश को जरूरत है दीर्घकालिक उपायों की। ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भरता घटाने के रास्ते तलाशने होंगे। रिन्यूबल एनर्जी और EV से इसमें मदद मिलेगी। सौर और पवन ऊर्जा के मामले में भारत तेजी से बढ़ रहा है। कुल बिजली क्षमता में आधे से ज्यादा हिस्सा, 262.7 गीगावॉट अब रिन्यूबल एनर्जी का हो चुका है। लेकिन, सोलर इंडस्ट्री के लिए जरूरी सामानों पर चीन पर निर्भरता है। इफिशिएंसी और अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करने पर काम करना होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत । EV की बात करें तो 2025 में 23 लाख इलेक्ट्रिक वीकल बिके, जो रेकॉर्ड है। लेकिन, कुल वाहनों में इनकी हिस्सेदारी केवल 8% रही। चीन, यूरोप के मुकाबले भारत EV अपनाने में पीछे है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पश्चिम एशिया संकट ने आयात पर अति निर्भरता से जुड़े जोखिमों को सामने ला दिया है। ऐसे में एनर्जी बास्केट में विविधता की जरूरत है, ताकि अगली बार तेल संकट आए तो ऐसी स्थिति न बने।

ऐवें कुछ भी

सुकून से ऐतराज़

मुझे आजकल सुकून से ऐतराज होने लगा है। जब चारों तरफ आग लगी हो तो सुकून समोसे की तीखी चटनी में गुलाब जामुन की चाशनी सा लगता है। अनवॉंटेड टाइप। अब भला बताइए वॉशरूम में सुकून की क्या जगह है? और सुकून भी ऐसा कि साहब वहीं बस जाने को मन करने लगे।

आलोक सिंह भदौरिया

मॉल के वॉशरूम में, रेस्त्रां के वॉशरूम में, ऑफिस के वॉशरूम में सुकून। आदमी झनझनाया हुआ घुसता है और वहां ऐसी हवाएं, ऐसी फिजाएं, ऐसी खुशबुएं, ऐसा संगीत कि कई बार सदमा लग गया। भाई कहीं मैं वॉशरूम पहुंचते-पहुंचते रास्ते में ही मर तो नहीं गया। ये क्या जगह है दोस्तो, ये कौन सा मकाम है... बिल्कुल येई वाली फीलिंग होती है। दिमाग में तमाम तिकड़में चल रही होती हैं, वहां जाना है, ये करना है, आज इतने की जेब कट गई, ये फाइल नहीं हुई, फलां अफसर नहीं आए और झम्म से कानों में गूंजने लगे- अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम और वो भी केवल धुन, मतलब केवल अहसास भर।

कुछ संभले इत्ते में बजने लगा, मैं तैनूं समझावां अरे राम रे। वो तो भला हो किसी दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, हां बड़े बाबू, वो फाइल निकाल लेना, हम जरा जरूरी मीटिंग में हैं। आवाज में भतेरा दर्द होता है। समझ गया कि एक तरफ नेचर का प्रेशर है दूसरी तरफ जिंदगी का प्रेशर। असल में ये सुकून वाला शौचालय हम लोग के लिए बना ही नहीं। हमें या तो खेत, झाड़ी और रेल की पटरी समझ आती है या फिर घर से 100 गज दूर बना भूतिया सा 4x4 का छोटा सा कमरा। जहां ऐसा लगता है कि बस किसी का कत्ल करने आए हैं।

सोचता हूं, घर लौटकर इंजीनियर साहब को यह सब बताऊंगा तो कहेंगे- अरे साहब फ्रेश तो हम गांव में होते थे। वो ब्रह्ममुहूर्त की बेला, नदी का किनारा, अमराई से आती आमों की खुशबू और कोयल की कूक, पेट इस जनम का क्या पिछले जन्म तक का साफ हो जाता था।

बोल वचन

दिलीप लाल

शिकार के लिए मचान

'मचान' लोकजीवन से जुड़ा हिंदी का एक सामान्य शब्द है। इसका अर्थ होता है- लकड़ी, बांस या अन्य किसी चीज से बनाया गया छोटा मंचनुमा ढांचा, जो ऊंचा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की रखवाली करने या शिकार देखने के लिए मचान बनाया जाता है। आज भी गांवों में किसान रात के समय फसलों की रक्षा के लिए मचान का इस्तेमाल करते हैं। राजमिस्त्री, रंगाई-पुताई करने वाले अस्थायी मंच तैयार करते हैं, ताकि ऊंचाई पर काम कर सकें। इसके लिए भी वे मचान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भाषाविदों के अनुसार 'मचान' शब्द की जड़ संस्कृत के 'मञ्च' शब्द में मिलती है, जिसका अर्थ ऊंचा आसन या मंच है। समय के साथ यह प्राकृत और अपभ्रंश से गुजरते हुए 'मचान' बन गया। हिंदी के अलावा भोजपुरी, अवधी, मैथिली, बंगला और मराठी में भी इसके समान रूप मिलते हैं। Man-Eaters of Kumaon में Jim Corbett ने मचान का रोमांचक चित्र खींचा है, 'अंधेरे जंगल में पेड़ पर बंधा मचान ही शिकारी का सुरक्षित ठिकाना होता था।' इस शब्द के साथ प्रतीक्षा, भय, सतर्कता और मनुष्य-प्रकृति संघर्ष की पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। मचान को स्मृति में दोहराएं तो यह रोमांचक दृश्य पेश करता है।

AI Image

BJP अभी कांग्रेस के पीक की बराबरी नहीं कर पाई है, लेकिन आगे और बढ़ सकता है उसका प्रभुत्व

अपने शिखर से कितनी दूर है BJP

अवधेश कुमार

दो दशक पहले शायद ही किसी ने सोचा हो कि BJP इतनी ताकतवर पार्टी बन जाएगी। पश्चिम बंगाल में जीत के साथ BJP की 11 राज्यों में अपनी और 11 में गठबंधन सरकार हो गई है। कांग्रेस के चार राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं (केरल में मुख्यमंत्री का नाम तय होना है), जबकि तीन राज्य सरकारों में वह जूनियर पार्टनर है।

शानदार जीत । पश्चिम बंगाल में BJP को 280 सीटें और लगभग 48% मत मिलना शानदार प्रदर्शन माना जाएगा। असम में भी पार्टी सत्ता में लौट आई है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और सबसे बढ़कर पूर्वोत्तर में BJP की स्वीकार्यता काफी मायने रखती है। हालांकि कांग्रेस का जो पीक रहा है, BJP अभी वहां तक नहीं पहुंची है। लेकिन, कांग्रेस के सामने 1967 तक सशक्त विपक्ष था ही नहीं। वहीं, BJP राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के अलावा, लगभग हर राज्य में क्षेत्रीय दलों की चुनौती के बीच आगे बढ़ी है।

असंतोष को आवाज । देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था, शिक्षा वगैरह के लिए जो मॉडल अपनाया गया, वह देश के संस्कारों से मेल नहीं खाता था। फिर अति-अल्पसंख्यकवाद के विरुद्ध लोगों में असंतोष बढ़ा, जिसे किसी राष्ट्रीय पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया। दूसरे दलों ने आर्थिक-सामाजिक विकास के मुद्दे उठाए पर सही मायनों में तब के जनसंघ और आज की BJP ने जनता के असंतोष को आवाज दी। कल्याणकारी राष्ट्रीयता का भाव इसी का अंग है। BJP ने इसे ही अपनी राजनीति का केंद्र बनाया।

मोहभंग की वजह । कांग्रेस को राजनीति के हाशिये में पहुंचाने वाली BJP ही है। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने तब का सबसे कमजोर प्रदर्शन किया था, केवल 114 लोकसभा सीटें जीती थीं। 2014 में वह 44 और 2019 में 52 पर सिमट गई। 1985-86 के बाद श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को कांग्रेस सांप्रदायिक बताती रही। फिर शाहबानो मामले में अल्पसंख्यकवाद का चरम दिखा, जब राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। ऐसे में देश का आम हिंदू अपनी पार्टी तलाशने लगा।

स्थितियों से तालमेल । BJP ने खुलकर हिंदुत्व को विचार-व्यवहार में अपनाया। आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाया। आम हिंदुओं में BJP को लेकर स्वीकार्यता बढ़ने लगी। इस बार पश्चिम बंगाल और असम में इसी वजह से BJP के पक्ष में आक्रामक ढंग से वोटिंग हुई।

माहौल में अंतर । कांग्रेस ने कभी सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं लड़ा। 1962 में चीन युद्ध, 1967 में कांग्रेस में आंतरिक संघर्ष, 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा पार्टी तोड़कर समयपूर्व चुनाव, 1980 में जनता पार्टी सरकार का पतन, 1984 में इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या, 1991 में विश्वनाथ सरकार के समय पूर्व पतन व मंडल और मंदिर आंदोलन से समाज में उथल-पुथल का माहौल था। इसके ठीक उलट, जनसंघ और BJP ने शून्य से शुरू किया। उसे कांग्रेस समेत अनेक दलों और विचारधाराओं से सीधी चुनौती मिली।

प्रयासों में कमी । कांग्रेस ने समयानुसार ठोस संगठन और निश्चित विचारधारा का आधार देकर खुद के पुनर्निर्माण की कभी कोशिश नहीं की। लालबहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' और इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे देकर पार्टी को बचाने का प्रयास किया, पर ये तात्कालिक नारे थे। दूसरी ओर, अयोध्या आंदोलन तात्कालिक नहीं था, यह एक लंबे लक्ष्य की शुरुआत थी।

ऐसे बदली राजनीति

- BJP ने खुलकर हिंदुत्व को विचार और व्यवहार में अपनाया
- मजबूत संगठन और चुनावी प्रबंधन ने सफलता दिलाई
- जन्मभूमि आंदोलन के विरोध का कांग्रेस को नुकसान हुआ

BJP की ताकत । UPA के दौर में कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगे। सच्चर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई नीतियों ने असंतोष और बढ़ा दिया। वहीं, BJP संगठन से निकली पार्टी है। संगठन के प्रति समर्पित लोग उससे जुड़ते रहे। नरेंद्र मोदी की जनता से जुड़ने की कला, संगठन की ताकत और चुनावी प्रबंधन ने BJP को सफलता के रास्ते पर डाल दिया।

सावधानी भी चाहिए । BJP की ताकत उसकी विचारधारा और समर्पित कार्यकर्ता हैं। राजनीति में दूसरे दलों के लोगों को लेना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें मुख्य भूमिका में लाते समय सतर्कता जरूरी हो जाती है। पार्टी की पारी तभी लंबी होगी, जब वह स्वाभाविक पसंद बनेगी। मजबूरी में हुआ चुनाव, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं, अच्छा नहीं होता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

कांटे की बात

हमारा देश कभी दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा। अगर समझौते की बात होती है तो इसका मतलब हार मानना या पीछे हटना नहीं है, बल्कि ईरानी जनता के हक को पाना और राष्ट्रीय हितों की मजबूती से रक्षा करना है।

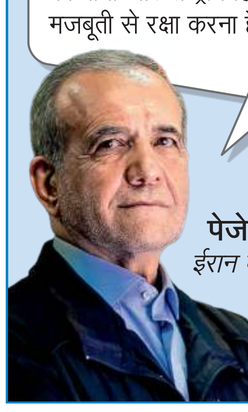

मसूद पेजेश्कियान, *ईरान के राष्ट्रपति*

AI की दुनिया

आपकी नज़र से दुनिया देखेंगे एपल के AirPods

Apple खास तरह के Air-Pods पर काम कर रहा है, जो गाना सुनने या कॉल करने के अलावा आसपास की चीजों को देख भी सकेंगे। इनका डिवेलपमेंट आखिरी चरण में है। प्रोटोटाइप लगभग तैयार है।

AI Image

सिरी से मिलेगा जवाब

नए AirPods में छोटे-छोटे कैमरे लगाए गए हैं, जो Apple के डिजिटल असिस्टेंट Siri की आंखों की तरह काम करेंगे। यानी आप जो देख रहे हैं, उसके बारे में Siri को समझ में आएगा और वह तुरंत जानकारी दे सकेगी। मसलन, एयरपॉड्स पहनकर आपने सब्जियां देखीं और Siri से रेसिपी पूछी, तो जवाब मिल जाएगा।

सितंबर तक इंतजार

इन AirPods का एक और दिलचस्प इस्तेमाल नेविगेशन में होगा। नए एयरपॉड्स का हार्डवेयर लगभग तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती AI फीचर्स को बेहतर बनाना है। कंपनी इस साल की शुरुआत में लॉन्च करना चाहती थी, पर Siri के नए वर्जन में देरी की वजह से प्लान टल गया। सितंबर तक आने की उम्मीद है। *-प्रदीप तिवारी*

जनता जंक्शन

इरफ़ान

इसलिए जीत जाते हैं दक्षिण के सितारे

कॉमन रूम

दक्षिण भारत में फिल्मी सितारों का राजनीति में आना नई बात नहीं है। एमजी रामचंद्रन, एनटी रामा राव और जे जयललिता इसकी मिसाल हैं। फिर भी सी जोसेफ विजय की एंट्री और असर ने उत्तर भारत को चौंकाया है।

प्रशांत जैन

उल्टा ट्रेंड । दक्षिण के उलट, हिंदी फिल्मी सितारों का राजनीति में सफर इतना सफल नहीं रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, गोविंदा, सनी देओल, जया प्रदा, उर्मिला मातोंडकर जैसे कलाकार चुनाव तो जीते, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी लंबी नहीं रही। बॉलिवुड के बड़े सितारों के भले करोड़ों प्रशंसक हों, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी का ही रुख करना पड़ता है। इसके बावजूद, जीत की गारंटी नहीं रहती।

प्रशंसकों से जुड़ाव । अक्सर पूछा जाता है कि दक्षिण में फिल्मी सितारों की इतनी जबरदस्त लोकप्रियता का राज क्या है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां सितारों की लोकप्रियता पर्दे तक नहीं सिमटी, उनका अपने फैंस के साथ भी गहरा जुड़ाव होता है। बॉलिवुड सितारों के मुकाबले दक्षिण के कलाकार अपने प्रशंसकों के बीच ज्यादा सक्रिय और उनके करीब रहते हैं। बॉलिवुड स्टार्स का आम फैंस से सीधा जुड़ाव कम देखने को मिलता है, इसलिए उनकी राजनीतिक पकड़ भी उतनी मजबूत नहीं बन पाती।

फिल्म और त्योहार । दक्षिण भारत के सितारे अपने फैंस क्लब के जरिये प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं। वे सिर्फ फिल्मों का प्रमोशन ही नहीं करते, अपने फैंस के साथ अपनी फिल्में भी देखते हैं। कई कलाकार तो अपने फैंस क्लब के लिए टिकटें भी उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि वहां किसी बड़े सितारे की फिल्म रिलीज फैंस के लिए त्योहार जैसी बन जाती है और पहले दिन सिनेमाघरों में जश्न का माहौल दिखता है।

फैंस क्लब । बॉलिवुड में शाहरुख खान को छोड़कर ज्यादातर सितारों के फैंस क्लब इतने सक्रिय नहीं। दक्षिण भारत में फैंस अपने पसंदीदा कलाकार को खास नाम या टाइटल देते हैं, जिन्हें कलाकार भी गर्व के साथ अपने नाम में जोड़ते हैं। इसलिए, चंद्रशेखरन जोसफ विजय ने भी अपने नाम के साथ थलपति जोड़ा। उनकी राजनीतिक सफलता में भी उनके फैंस क्लब विजय मक्कल इयक्कन (VMI) की भूमिका रही, जो लंबे समय से समाजसेवा और जनता से जुड़े काम करता है।

जनता से जुड़े किरदार । दक्षिण भारतीय फिल्मों के हीरो अक्सर अपनी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाते हैं, जो आम लोगों की समस्याओं के खिलाफ लड़ता हो। MGR से शुरू हुई यह परंपरा विजय तक चली आ रही है। विजय की फिल्मों में जनहितैषी नेता की छवि बनी, जिसका राजनीतिक फायदा भी उन्हें मिला। बॉलिवुड में ऐसे किरदार कम देखने को मिलते हैं। साथ ही उनकी भाषा, पहनावा और सांस्कृतिक जुड़ाव भी लोगों को अपनेपन का अहसास कराता है, जिससे उन्हें राजनीति में मजबूत समर्थन मिलता है।

बंगाल के बाद BJP का 'मिशन पंजाब'

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

भूपेंद्र शर्मा

पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बना चुकी BJP पंजाब में यही करिश्मा दोहराने की कोशिश में है। अगले साल फरवरी-मार्च में पंजाब समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पंजाब को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में BJP ही सत्तासीन है। राज्य में पार्टी पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है, लेकिन अपने बलबूते वह कभी सत्ता में नहीं आई। पंजाब में ऐतिहासिक बहुमत के साथ 2022 में AAP सत्ता में आई थी। लेकिन अभी उसके राजनीतिक वजूद पर सवालिया निशान लगा है। दिल्ली में वह पहले ही सत्ता गंवा चुकी है। इन हालात में पंजाब की अहमियत उसके लिए बहुत ज्यादा है।

स्थानीय मुद्दों पर जोर

पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव व उपचुनाव में BJP को कामयाबी नहीं मिली। इधर पार्टी ने राज्य में जमीन मजबूत करने की कोशिशें तेज की हैं। मगर सवाल है कि पंजाब के लिए BJP की रणनीति क्या होगी? क्या उसे पश्चिम बंगाल की तरह पंजाब के लिए अलग रणनीति बनानी होगी? सवाल यह भी है कि क्या छह वर्षों के बाद फिर से BJP पुराने सहयोगी अकाली दल के साथ हाथ मिलाएगी? राज्य में BJP ने TMC सरकार को तुष्टिकरण की राजनीति, महिला सुरक्षा, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर घेरा था। TMC की पिछले 15 वर्षों से राज्य में सरकार थी और उससे लोगों की नाराजगी का फायदा भी BJP को मिला।

इधर, पंजाब में पार्टी ने कानून-व्यवस्था को लेकर भगवंत मान सरकार को घेरना शुरू किया है। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। पंजाब सरकार के एक मंत्री पर भी शिकंजा कसा है। नशा आज भी राज्य में बड़ी समस्या है, तो आगामी चुनाव में वह इसे भी मुद्दा बनाएगी। पंजाब की तरह ही यहां भी BJP स्थानीय मुद्दों पर काफी जोर दे रही है। उसका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में महिलाओं को लेकर जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए। फिर कृषि कानूनों के कारण पंजाब के ग्रामीण इलाकों में BJP विरोध बढ़ा था।

पंजाब से BJP में आए छह राज्यसभा सांसदों के जरिए वह AAP के संगठनात्मक ढांचे को तोड़ने में कामयाब हो सकती है। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार रहे राघव चड्ढा, संदीप पाठक दलबदल के बाद रोज AAP पर हमले कर रहे हैं। BJP को लगता है कि इनकी मदद से राज्य में वह जनाधार बढ़ाने में कामयाब होगी। देखना यह भी होगा कि AAP के बाकी नेता चुनाव की घोषणा होने तक एकजुट रहते हैं या नहीं?

अकाली दल से समझौता

कृषि कानूनों के मुद्दे पर 2020 में अकाली दल से अलग होने के बाद, 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों के साथ आने की बात तो चली थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। एक बार फिर से इसकी कोशिश होती दिख रही है। हालांकि दोनों दलों के नेता यही कह रहे हैं कि वे पंजाब की सभी सीटों के लिए अलग-अलग तैयारी कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में AAP को 117 में से 92, कांग्रेस को 18, अकाली दल को 3, BJP को 2 सीटें मिली थीं।

गुस्से में हैं, तो जवाब से पहले धैर्य और विवेक का साथ लें

बी.के शर्मा

छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करना आम बात हो गई है। फिर यही क्रोध आगे चलकर झगड़े, हिंसा और कभी-कभी गंभीर अपराधों का कारण बन जाता है। क्रोध शांत होने के बाद केवल पश्चाताप शेष रह जाता है, लेकिन तब तक बहुत हानि हो चुकी होती है। क्रोध आने पर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ढक जाते हैं और उसके भीतर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना उत्पन्न होने लगती है।

यदि क्रोध के मूल कारण पर विचार करें, तो उसके पीछे मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं और स्वार्थ दिखाई देते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती और उसमें कोई बाधक बनता है, तब क्रोध आ जाता है। यदि सामने वाला व्यक्ति कमजोर हो तो क्रोध तुरंत प्रकट हो जाता है, और यदि वह अधिक शक्तिशाली हो तो भय के कारण दब जाता है। यही दबा हुआ भाव बाद में किसी अन्य परिस्थिति में क्रोध बनकर बाहर आता है। इस प्रकार क्रोध हमारे भीतर तक को प्रभावित करता है और हमें अशांत बनाए रखता है। इसका सूक्ष्म रूप द्वेष है, जो मन में धीरे-धीरे सुलगता रहता है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

मनुष्य का मन इंद्रियों और बुद्धि के बीच स्थित होता है। वह बाहरी विषयों और भीतर के विचारों, दोनों से प्रभावित होता है। जब मन विवेक युक्त बुद्धि के अनुसार काम करता है, तब जीवन शांत और संतुलित रहता है। लेकिन जब इच्छाएं बुद्धि पर हावी हो जाती हैं, तब मन उचित-अनुचित का विचार छोड़कर केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और मनुष्य धर्म-अधर्म का भेद भूल जाता है।

समाज में हिंसा को कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। क्रोध न केवल मानसिक तनाव, अशांति और अनिद्रा को जन्म देता है, बल्कि दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त है, वही वास्तव में शांत और मुक्त जीवन जीता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य, विवेक और परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। क्रोध कभी समस्या का समाधान नहीं करता, उसे और अधिक जटिल बना देता है।

रीडर्स मेल

तमिलनाडु में विजय का दौर

तमिलनाडु की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है। अभिनेता से जननेता बने सी.जोसेफ विजय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। उनकी पार्टी TVK ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि तमिलनाडु की जनता अब नई राजनीति और नए नेतृत्व की तलाश में थी। विजय का उदय जनता की बदली हुई सोच का प्रतीक माना जा रहा है।

-कांतिलाल मांडोत, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 इस समाचार-पत्र का प्रकाशन आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए किया गया है। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) मुद्रण उपेंद्र नायक द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई-400101 में (टेलीफोन नंबर: 66353535, 22733535) और इंद्रजीत सेन द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400 708 में (टेलीफोन नंबर: (022) 2760 9999.) किया गया है।

सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित।

सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलोंके बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर,नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 6.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 7.00 रुपये।

संपादकीय

युद्धाच्या झळा, काटकसरीच्या कळा

अमेरिका व इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याला सत्तर दिवस उलटल्यानंतर आणि प्रामुख्याने भारतातील पाच राज्यांच्या निवडणुका आटोपल्यानंतर त्या युद्धामुळे देशावर आलेल्या संकटाची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हैदराबाद येथे झाली. त्यांनी देशवासीयांना काटकसरीचे, डॉलर्समधील खर्च टाळण्याचे आवाहन केले. शक्य तिथे घरून काम करा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरून पेट्रोल व डिझेल या इंधनाचा वापर कमी करा, परदेशवारी व सोनेखरेदीच्या रूपाने होणारा डॉलर्सचा वापर टाळा, अशा स्वरूपाचे हे आवाहन सहा वर्षांपूर्वीची कोरोना महामारी व लॉकडाऊनची आठवण करून देणारे आहे. खरे तर ही पावले आधीच उचलायला हवी होती. विशेषत: इराणवरील हल्ल्यानंतर महिनाभरात त्या युद्धाचे रूपांतर जागतिक महायुद्धात होते की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. होर्मुझ सामुद्रधुनीत तेल व एलपीजीचे टँकर अडकून पडले होते. जगाचा व्यापार अडचणीत आला होता. भारतात इंधन व स्वयंपाकाच्या गॅससाठी रांगा लागल्या होत्या. तेव्हा सरकारने अशी काही पावले उचलण्याची गरज होती. तथापि, त्यावेळी सरकारी यंत्रणा व देशाचे कर्तेधर्ते मात्र सारेकाही आलबेल आहे, कोणतीही टंचाई नाही, उगीच घाबरून जाण्याची गरज नाही, अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे सांगत होते. आता गेल्या तीन-चार दिवसांत पेट्रोलपंपांवर पुन्हा रांगा दिसत आहेत. रुपयाची घसरण सुरूच आहे. कारण, युद्ध थांबण्याची चिन्हे धूसर झाली आहेत. होर्मुझमध्ये पुन्हा टँकर अडकले आहेत. म्हणूनच उशिरा का होईना, देशवासीयांना काटकसरीचे आवाहन करण्याची वेळ पंतप्रधानांवर आली. त्यांना किती प्रतिसाद मिळतो आणि परिणाम काय होतात, हे लगेच स्पष्ट होणार नाही. परंतु, या आवाहनानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या आवाहनाची खिल्ली उडविताना, 'आपण मार्चमध्येच ही पावले उचलण्यास सांगत होतो. परंतु, त्यावेळी पंतप्रधान अमेरिकेला शरण होते', अशी टीका केली आहे. तिचा प्रतिवाद करताना भारतीय जनता पक्षाकडून लाल बहादूर शास्त्री व इंदिरा गांधी यांच्या काळातील अशाच काटकसरीच्या आवाहनांची आठवण करून दिली आहे. ही तुलना आणखी वाढविताना विरोधकांकडून सांगितले गेले की, 'शास्त्री यांनी भुकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशवासीयांना उपवास धरण्याचे आवाहन केले तेव्हा सुरुवात स्वत:पासून केली होती. इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकी निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेला देश संकटातून बाहेर काढण्यासाठी स्वत:चे दागिने देशाला अर्पण केले होते. याउलट, सामान्य भारतीयांना इंधन वाचविण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही तासांत खुद्द पंतप्रधानांनी गुजरातमध्ये भव्य रोड शो केला, इंधनाची नासाडी केली.' राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून देशहिताला प्राधान्य देण्याची गरज असताना असे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होणे दुर्दैवी आहे खरे. परंतु, त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यापैकी कोणत्याही एका बाजूला दोष देता येणार नाही. त्यापेक्षा मोठा विषय देशाच्या स्वावलंबनाचा, स्वयंपूर्णतेचा, आत्मनिर्भरतेचा आहे आणि राजकीय हडेलहप्पीमध्ये त्याकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. गेली काही वर्षे उठताबसता केली जाणारी आत्मनिर्भर भारताची घोकंपट्टी आणि वस्तुस्थिती यात कमालीची तफावत आहे. मावळत्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षात भारताची एकूण आयात एक हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात होती आणि त्यात मालाची आयात ७७५ अब्ज डॉलर्सची होती. पंतप्रधानांच्या आवाहनात ज्या गोष्टींचा उल्लेख आहे, त्या कच्च्या तेलासाठी त्यापैकी १३५ अब्ज डॉलर्स, अन्य पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी आणखी ४० अब्ज डॉलर्स, सोने आयातीवर ७२ अब्ज डॉलर्स, खाद्यतेलासाठी २० अब्ज डॉलर्स व खतांसाठी १५ अब्ज डॉलर्स असे मिळून जवळपास ३०० अब्ज डॉलर्स खर्च झाले. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल सामानाची आयात मोठी आहे. तथापि, ती आपल्या उद्योगाची अपरिहार्य गरज आहे. आता युद्ध लांबल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत. ही वाढ किती असेल याचा अंदाज बांधता येत नाही. परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली आहे. फेब्रुवारीपासून परकीय गंगाजळीत किमान चाळीस अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. एकूणच पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे हे नक्की. तेव्हा, हे संकट निवारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना काटकसरीची हाक देत असतील तर तिला प्रतिसाद देताना आवाहनाच्या वेळेचे राजकारण नव्हे, तर देशहित अधिक महत्त्वाचे असते.

भगव्या बंगालमध्ये सगळ्यांना 'भाकरी' मिळेल का?

तळपत्या उन्हात मतदानासाठी रांगा लावणाऱ्या पश्चिम बंगालमधल्या सामान्य लोकांना आता भाकरी आणि शांतता, ठोस विकास हवा आहे.

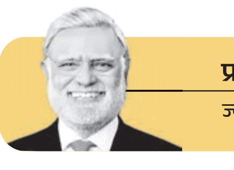

प्रभू चावला

ज्येष्ठ पत्रकार

कोलकात्याच्या ब्रिगेड मैदानावर नऊ मेच्या माध्यान्ही तळपत्या उन्हात इतिहासाने केवळ एक पान उलटले नाही. पश्चिम बंगालच्या इतिहासात प्रथमच तृणमूल काँग्रेसचे खंदे कार्यकर्ते म्हणून कारकिर्दीची सुरुवात करणारे सुवेंदू भगव्या पोशाखात पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेते झाले. त्यांचा पोशाख हे केवळ एक वस्त्र नव्हते, काँग्रेसची स्वयंसंतुष्टता, मार्क्सवाद्यांचा गैरकारभार आणि ममतांची कारस्थाने यांनी गांजलेल्या राज्याचा तो एक ठाम सांस्कृतिक कायापालट होता. काही क्षण आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या प्रसंगासाठी खास तयार करण्यात आलेल्या भगव्या रंगाच्या खुल्या विजयरथातून त्यांना घेऊन आले. तत्पूर्वी तामिळनाडूत कधीही पारंपरिक पोशाखात न दिसलेले राज्यपाल आर. एन. रवी भगव्या रंगाचा कुर्ता आणि बंगाली धोतर परिधान करून आले होते. संपूर्ण मंडपात भगव्या रंगाचा विशाल जनसागर पसरला होता. ध्वज फडकत होते, गमछे उसळत होते. लोकांनी कपाळावर गंध लावलेले होते. अधिकारी आणि त्यांचे पाच मंत्री भगवाच पोशाख करून आले होते. राज्याचा नवा रंग, नवी दिशा त्यातून निर्णायकपणे सूचित होत होती.

ही केवळ प्रतीकात्मकता नव्हती. बंगालची नवी अस्मिता त्यातून जाहीर होत होती. हा क्षण खेचून आणणारा जनमताचा कौलही ऐतिहासिकच. भाजपने २०७ जागा आणि ४५ टक्के मतहिस्सा मिळवणे महत्त्वाचेच. हा सांस्कृतिक विजय होता. भाजपने दूरदर्शीपणाने अचूक आणि हुकमी पावले टाकली. जे समोर दिसले त्याच्या मुळांना भाजपने गेली पंधरा वर्षे पाणी घातले.

सनातनी राष्ट्रवादासाठी पश्चिम बंगालची भूमी कायमच सुपीक होती. राजा राम मोहन राय यांच्यासारख्या बुद्धिप्रामाण्यवादी सुधारकाची ही भूमी. बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी 'वंदे मातरम्' हे राष्ट्रीय गीत लिहिले. अनेक पिढ्यांना या गीताने प्रेरणा दिली. ब्रिटिश राज्याला सुभाषचंद्र बोस यांच्या आक्रमक स्वातंत्र्यलढ्याने आव्हान दिले. श्री. अरविंद यांनी हिंदू अध्यात्म क्रांतिकारी रूपात प्रकट केले. स्वामी विवेकानंद हिंदुत्वाचे जागतिक दूत झाले. 'भारताचा आत्मा अमर आहे' अशी गर्जना त्यांनी जागतिक धर्मसभेत केली. या सर्व मातब्बर व्यक्तींनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची बीजे पेरली.

काँग्रेस, डावे पक्ष आणि नंतर तृणमूल काँग्रेसने बंगालचे रूपांतर आत्माविहीन भग्न राज्यात केले.

मतांच्या राजकारणाने समाज धर्मात विभागला गेला. बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीने सीमेवरील जिल्हे धगधगते ठेवले. राज्यकर्त्यांनी हिंसाचाराला आश्रय दिल्याने गुंतवणूकदार पळून गेले. एकेकाळी औद्योगिक ऊर्जा केंद्र असलेला बंगाल भांडवलदृष्ट्या कंगाल झाला. उद्योग निघून गेले. खंडण्या तेवढ्या उरल्या. भाजपला यात संधी दिसली. गेली १५ वर्षे उपेक्षिल्या गेलेल्यांसाठी त्यांनी शांतपणे काम केले. हिंदूंना त्यांची संकटात सापडलेली पूजास्थाने भाजपने दाखवून दिली. लोकसंख्येत असाच बदल होत राहिला तर स्वतःच्या भूमीतच तुम्ही परके होऊन जाल, याची जाणीव करून दिली. संदेशखालीत घडलेल्या भयावह घटनांनी हा उद्रेक बाहेर आला. जात आणि वर्ग यांच्या पलीकडे जाऊन हिंदूंनी अभूतपूर्वरीत्या एकत्र येऊन मतदान केले. जुनी राजवट केवळ नाकारली नाही, तर नव्या राजवटीला साद घातली.

असे असले तरी कोणताही विजय कठोरतम अशी अग्निपरीक्षा समोर ठेवतो. अधिकारी सरकारला आता केवळ थातूरमातूर काम करून भागणार नाही. तळपत्या उन्हात मतदानासाठी रांगा लावणाऱ्या लाखो लोकांना आता भाकरी आणि शांतता, ठोस विकास हवा आहे. झालेल्या जखमा भरून याव्यात, असे त्यांना वाटते. त्यांना आता वंचितांना न्याय देणारे रामराज्य प्रत्यक्षात हवे आहे. अपेक्षा बऱ्याच आहेत : गुंतवणूक पुन्हा येईल, गुंडांची भीती राहणार नाही, सीमा सुरक्षित होतील, लांगुलचालन संपेल. बंगालचे बौद्धिक आणि आर्थिक पुनर्भरण होईल.

नवे सरकार रायटर्स बिल्डिंग परतून काम करणार आहे, यातला संकेतही महत्त्वाचा. ज्या ठिकाणी वसाहतवाद्यांनी आपल्या अधिसूचना काढल्या आणि नंतर क्रांतिकारींनी त्यांचे आदेश मोडले, त्या इमारतीत नवे सरकार परतत आहे. तेथे जाताना सरकारला हे जाहीर करावयाचे आहे की, बंगालची ओळख म्हणजे वसाहतीचे अवशेष नव्हती. ही डाव्यांची प्रयोगशाळा नाही.. विभिन्नतेत एकता पाहणारा जीताजागता भारत हीच या राज्याची ओळख असेल.

अर्थात, टीकाकार पुढे सरसावतीलच. काहीजण म्हणतील संस्कृतीचे भगवीकरण हे पाप होय. धर्मनिरपेक्षता संपली म्हणून काहीजण छाती पिटतील; परंतु जनादेश स्पष्ट आहे. भूतकाळाने मोडलेली वचने मतदारांनी भिरकावली आहेत. शेती कुंठित करणाऱ्या भूमीसुधारणा, संपाना आमंत्रण देणारी औद्योगिक धोरणे, अल्पसंख्याकांचे राजकारण या गोष्टींनी बहुसंख्याकांना वाटणारी चिंता दुर्लक्षित केली होती.

भगव्या शाईने इतिहास पुन्हा लिहिला गेला आहे. ही शाई बंगालच्या पुनरोदयाची संहिता लिहिते की, केवळ आरंभशूरता ठरते, हे येणारा काळ ठरवेल.

अन्वयार्थ

न्यायालय म्हणते, बोगस दिव्यांग 'काळी मेंढरे' सेवेतून हाकला !

'माफी मागा व निवृत्त व्हा', अशी सवलत न्यायालयाने बोगस दिव्यांगांना दिली आहे. बोगस प्रमाणपत्र घेणारे व देणारे दोघेही खरे तर गुन्हेगारच आहेत.

सुधीर लंके

निवासी संपादक,
लोकमत, अहिल्यानगर

प्रशासन नैतिक हवे. कर्मचाऱ्यांचे नैतिक अध:पतन त्यांना नोकरीतून काढण्यास पुरेसे आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिव्यांग घोटाळ्यात नोंदविले आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात अलीकडे दिलेला निकाल हा प्रशासन, वैद्यकीय व्यवस्था व राज्यकर्ते या सर्वांना सणसणीत चपराक लगावणारा आहे.

शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी गुणवत्तावान मुलांच्या मोठ्या रांगा आहेत. नोकरीतील सामाजिक-आर्थिक आरक्षणावरून झगडे सुरू आहेत. पण, राज्यात गत काही वर्षांत एक घोटाळा बिनबोभाट व खुलेआम सुरू आहे, तो म्हणजे 'बोगस दिव्यांग घोटाळा'. ज्याकडे राज्यकर्ते कानाडोळा करत आहेत. याची व्याप्ती एवढी भयानक आहे की अनेक 'आयएएस', 'आयपीएस' व लोकसेवा आयोगातून निवड झालेले अधिकारीदेखील बोगस दिव्यांग आहेत, असा संशय आहे. अनेकांनी 'एमबीबीएस'चे प्रवेश मिळवलेले असू शकतात. वर्ग ३ व ४ च्या पदांवर तर असे बोगस लोक ढिगाने आहेत. अनेकांनी बदल्या व इतर लाभांसाठी ही बनावटगिरी केली आहे. खऱ्या दिव्यांगांवर या ठग लोकांनी अन्याय केला आहे. समाजाला हे दिसते, पण तो हतबल आहे. कारण प्रशासन, राज्यकर्ते कारवाईच करत नाहीत. दिव्यांगांचे नेते म्हणविणारी मंडळीही यात सोयीस्करपणे गप्प आहेत.

'लोकमत' दहा-बारा वर्षांपासून या घोटाळ्याचा पाठपुरावा करत आहे. ६ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे पहिले श्रेय जाते ते दिव्यांग कल्याण विभागाचे माजी सचिव तुकाराम मुंढे यांना. या विभागात रुजू होताच त्यांनी हा घोटाळा नेमकेपणाने ओळखला. त्यापूर्वीच्या बहुतांश सचिवांनी डोळे मिटलेले होते. मुंढेंनी हे बोगस तण गाडण्यासाठी ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आदेश काढला की, 'शासकीय नोकरीत जेवढे दिव्यांग कर्मचारी असतील त्यांची पुन्हा प्रत्यक्ष शारीरिक पडताळणी करा. भले ते नोकरीला कधीही लागलेले असोत'. त्यामुळे गोंधळ उडाला. मुंढेंना अगदी विधानसभेत टार्गेट करण्यात आले. पुढे त्यांची शासनाने बदलीही केली.

मुंढे यांनी काढलेल्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या. त्यात बहुतांश शिक्षक होते. 'आमच्याकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र असताना पुन्हा तपासणी कशाला?' असा या याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. न्यायालयाने सुरुवातीला अशा तपासणीला स्थगिती दिली. पण, मुंढे यांनी न्यायालयासमोर 'डाटा'च मांडला की या तपासणीत अनेक लोक दिव्यांगच नाहीत हे निदर्शनास येत आहे. ज्याने स्वत:ला ४० टक्के दिव्यांग दाखवले तो प्रत्यक्षात शून्य टक्के दिव्यांग आहे, असेही दिसले. काहींची प्रमाणपत्रेच बनावट निघाली. परिणामी शासनाने सुरू केलेली मोहीम योग्य आहे, यास पुष्टी मिळाली.

'ज्यांनी बनावट अथवा चुकीच्या प्रमाणपत्रांआधारे नोकरी मिळवली त्यांच्या नोकरीला सुरक्षा देता येणार नाही', असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे 'चुकीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाभ घेणे हे नैतिक अध:पतन आहे व ही बाब सेवेतून काढण्यास पुरेसी आहे. हे लोक काळी मेंढरे (ब्लॅक शीप) आहेत' अशा कडक भाषेत उच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदविले आहे.

'बेंचमार्क डिसॲबिलिटी' म्हणजे ४० टक्के दिव्यांग असलेल्यांनाच दिव्यांग अधिनियम २०१६ नुसार लाभ मिळतो. आता दिव्यांग कोट्यातून भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याची ही टक्केवारी यापेक्षा कमी आढळली तर त्यांना नोटीसा बजावून 'सक्तीने निवृत्त करा', असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ज्यांनी नोकरी लागल्यानंतर हे प्रमाणपत्र मिळविले त्यांचे यापोटीचे सर्व लाभ काढण्याचा आदेश आहे. न्यायालयाने दिलेली एक सवलत मात्र अनाकलनीय आहे. दिव्यांग अधिनियमाचे कलम ९१ सांगते की, बोगस अथवा चुकीचे दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. न्यायालयाने एकत्रित याचिकांवर निकाल देताना 'वन टाईम मेजर' म्हणून अपवादात्मक स्थितीत फौजदारी कारवाई टाळून केवळ सेवा समाप्त करण्यास परवानगी दिली आहे. 'माफी मागा व निवृत्त व्हा', अशी सवलत न्यायालयाने दिली आहे. बोगस प्रमाणपत्र घेणारे व देणारे हे दोघेही खरेतर गुन्हेगारच आहेत. त्यांनी जनतेला फसवले. पात्र नसताना लाभ उपटले. घरफोडी करणारा अथवा दरोडा टाकणारा जसा गुन्हेगार असतो, तसेच हे व्हाइट कॉलर गुन्हेगार आहेत.

दिव्यांग नसताना तसे प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवरही न्यायालयाने शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. या घोटाळ्यास मुख्यत्वे आरोग्य विभाग व त्यांची वैद्यकीय मंडळे जबाबदार आहेत. त्यांनी खोटी प्रमाणपत्रे देऊन धडधाकट महाराष्ट्र दिव्यांग बनवला. या निर्णयातून प्रशासन व राज्यकर्त्यांनी शहाणे व्हायला हवे. मुंढे यांची शासनाने बदली केली आहे. सध्याच्या दिव्यांग सचिवांनी आता मुंढे यांचा रोल अदा करून नैतिकता दाखवावी. न्यायालयीन निर्णयाची कडक व वेळेत अंमलबजावणी करावी. या बोगस लोकांना केवळ माफीनामा व निवृत्तीवर का सोडायचे? याबाबत पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याबाबतही शासनाने विचार करायला हवा.

sudhir.lanke@lokmat.com

जगभर

ऑनलाइन फूड स्कॅम, बोगस हॉटेल्सनं चीन हादरला!

घटना आहे चीनमधली. काही दिवसांपूर्वीची. म्हटलं तर अगदी छोटीशी, पण या साध्याशा घटनेनं अख्खा चीन आणि चीन सरकारही हादरलं आहे. एका ग्राहकानं सहज म्हणून ऑनलाइन केक मागवला. केक घरी आल्यानंतर तो आश्चर्यचकित झाला. कारण केकवर सजावटीसाठी लावलेली फुलं प्रत्यक्षात प्लास्टिकची निघाली. याबद्दल त्यानं तक्रार केली आणि नंतर विसरूनही गेला. पण, या छोट्याशा तक्रारीनं असा एक मोठा घोटाळा समोर आला, ज्यामुळे संपूर्ण देश हादरला !

अलीकडे चीनमध्ये फूड डिलिव्हरी उद्योगाचा बराच बोलबाला आहे. अनेकांनी हा उद्योग सुरू केला आहे आणि नागरिकही बऱ्याचदा अन्न ऑनलाइन मागवतात. या ग्राहकानं सहज म्हणून तक्रार केली आणि तक्रार आलीच आहे, तर आता जुजबी का होईना, चौकशी करावीच लागेल, म्हणून अधिकाऱ्यांनीही तपासणी सुरू केली, पण थोडंसं खोलात गेल्यावर त्यांना कळलं, हे प्रकरण इतकं साधं नाही. यात एक मोठी साखळी गुंतलेली आहे.

थोड्याच कालावधीत त्यांना ६७,००० अशी 'दुकानं', 'हॉटेल्स' सापडली, ज्यांचं ना कुठे दुकान होतं, ना त्यांच्याकडे कसला परवाना होता, ना पदार्थ बनवण्यासाठी कुठलं स्वयंपाकघर! ही सगळी दुकानं ऑनलाइन ॲप्सवर मात्र प्रत्यक्षात असल्याचं दाखवत होती. स्क्रीनमागचा तो एक फसवा खेळ होता. अनेक दुकानदारांनी अन्नपदार्थ विक्रीची दुकानं फक्त ऑनलाइनच सुरू केली होती. त्यांचं ना कुठलं हॉटेल होतं, ना कुठे एखाद्या ठिकाणी हे पदार्थ ते बनवत होते, ना त्यांनी विशिष्ट कोणाला ही ऑर्डर दिलेली होती. हे सारेच 'दुकानदार' बनावट होते.

एखाद्या खाद्यपदार्थाची कोणी ऑर्डर दिली की, ती लगेच ते एखाद्या स्वस्त आणि अंधाऱ्या स्वयंपाकघरात पाठवत असत, जिथे अत्यंत निकृष्ट पद्धतीनं अन्न तयार केलं जायचं. हे 'घोस्ट' विक्रेते

ॲपवर स्वतःला आलिशान आणि मोठ्या रेस्टॉरंटप्रमाणे दाखवत होते. आकर्षक फोटोशॉप केलेली छायाचित्रं, बनावट परवाने आणि रसिकांच्या खोट्याच बढ्या-चढ्या प्रतिक्रिया यांच्या आधारे ग्राहकांना ते भुरळ घालत होते.

चौकशीत लक्षात आलं, ग्राहक जेव्हा महागड्या किमतीत खाद्यपदार्थांची ऑर्डर द्यायचे, तेव्हा मध्यस्थ त्या ऑर्डरची बोली लावत आणि जो सर्वात कमी किमतीत पदार्थ बनवून देईल, त्यालाच हे काम ते द्यायचे. परिणामी पदार्थ स्वस्त तर मिळायचे, पण ते अत्यंत अस्वच्छ आणि निकृष्ट दर्जाचे असायचे. ग्राहकांना मोठ्या रकमेसह आपल्या आरोग्यानं त्याची किंमत चुकवावी लागत होती.

या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर चीन सरकारनं सात प्रमुख फूड डिलिव्हरी कंपन्यांवर तब्बल ५.३ अब्ज डॉलर्सचा मोठा दंड ठोठावला. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दंड मानला जात आहे. ही समस्या केवळ चीनपुरती मर्यादित नाही. जगातील अनेक देशांमध्ये 'डार्क किचन' किंवा 'क्लाउड किचन' मॉडेल वेगानं वाढत आहे. या ठिकाणी एकाच स्वयंपाकघरातून अनेक वेगवेगळ्या नावांनी अन्न विकलं जातं. इंग्लंडमध्ये दर सात फूड डिलिव्हरी व्यवसायांपैकी एक पूर्णपणे डार्क किचनवर चालतो, ज्याचं कोणतंही प्रत्यक्ष रेस्टॉरंट नसतं. ऑस्ट्रेलियात एका स्वयंपाकघरातून १७ वेगवेगळ्या रेस्टॉरंट नावांनी अन्न विकलं जात असल्याचं आढळलं. ग्राहकांना वेगवेगळ्या ठिकाणांहून अन्न येतंय असं वाटतं, पण ते प्रत्यक्षात एकाच ठिकाणी तयार होत होतं...

जनमन

जलसुरक्षेबाबत सतर्कता आवश्यक

मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील बर्गी धरणात पर्यटकांची क्रूझ बोट उलटून नुकत्याच झालेल्या अपघातात ९ जणांचा मृत्यू झाला. अशा प्रकारच्या घटना वारंवार होतात, तरीदेखील सरकार आणि जनता यातून काहीच बोध घेत नाही. प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सक्षम यंत्रणा राबविण्यात आली पाहिजे. नियम कडक करून त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. जे लोक नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. नागरिकांचे नाहक जीव जाणे अतिशय क्लेशकारक आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रवाशांनी देखील नियमांचे पालन करावे. जलमार्गाने प्रवास करताना सुरक्षाकवच (सेफ्टी जॅकेट) बंधनकारक केले पाहिजे. प्रवाशांनीही सुरक्षाकवच (सेफ्टी जॅकेट) घालूनच जलप्रवास करावा. तसेच सरकारने सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना पोहण्याचे प्रशिक्षण लहानपणापासून देणे सर्व शाळांना बंधनकारक करावे, जेणेकरून भविष्यात प्रत्येक व्यक्ती आपला स्वतःचा जीव वाचवू शकेल.

आजही अनेक लोक पर्यटनासाठी जलमार्गाचा वापर करतात; परंतु सेफ्टी जॅकेटचा वापर करत नाहीत, तर काही लोक स्वतःला उत्तम पोहता येते असे समजून स्वतःचा जीव गमावतात. जलसुरक्षेवर सरकारने आणि जनतेने गांभीर्याने विचार करावा आणि सुरक्षित प्रवासासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत आणि प्रवाशांचे प्राण वाचतील. थोडीशी काळजी घेतली आणि त्याबाबत संवेदनशील राहिले तर अशा प्रकारच्या घटना टळू शकतात.

- **विजय आकुर्डेकर,** बिबवेवाडी

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

शहर नोंदी

शहरांनी सुरळीत धावण्यासाठी त्यांच्या पायांना कसली चाकं हवीत?

'जिथले श्रीमंत लोक नियमितपणे सार्वजनिक वाहतूक वापरतात, तो खरा प्रगत देश. जिथल्या गरिबांकडे मोटारी असतात, तो नाही !'

मेघना भुस्कुटे

ब्लॉगर, भाषांतरकार

शहरांच्या वेगात मोठी भूमिका त्यातल्या दळणवळणाच्या साधनांची असते. वेग म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर फक्त गोळीच्या वेगानं सणाणत निघालेल्या बुलेट ट्रेनचं चित्रच काय ते येतं. पण दळणवळणाच्या साधनांचा वेग शहरांच्या वेगासाठी तितका महत्त्वाचा नसतोच.

गोंधळलात ना ? ! एक मिनिट ! पण खरंच. बस किंवा टॅक्सी किंवा ट्रेन ताशी किती किमी वेगानं धावते, हे महत्त्वाचं नसतं. शहर दीर्घकाळ सुरळीत चालण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वेग नाही, तर इतर अनेक घटक जास्त महत्त्वाचे असतात. एकाच एक प्रकारची वाहतूक आहे की त्या त्या भागाच्या वापराला आणि भूगोलाला अनुसरून बस, ट्रेन, रिक्षा, टॅक्सी, टमटम, मेट्रो, दुचाकी वाहनं, खासगी वाहनं.. इत्यादी प्रकारांचं यथायोग्य मिश्रण आहे? ते सर्वसामान्य माणसांना सहज वापरता येईल असं नि इतकं स्वस्त आहे का ? वाहतूक प्रकारांची ही जाळी आपापसांत 'बोलतात' का - म्हणजे ट्रेन आहे, पण कनेक्टिंग बस नाही, म्हणून ताटकळत बसावं लागतं, असं तर होत नाही ना? प्रवास सुखदायक आहे का? की रोज जिवाची बाजी लावावी लागते प्रवासात? उपलब्धतेत सातत्य आहे का ? असे अनेक प्रश्न असतात. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं समाधानकारक असतील, तर शहरं सुरळीत धावतात.

असं म्हणतात, सार्वजनिक वाहतुकीवर आज खर्चलेला एक रुपया नजीकच्या भविष्यकाळात शहरांच्या अर्थव्यवस्थेला पाच रुपये कमावून देतो. जर्मनीत २०२२ साली झालेला '९-युरो तिकीट' नावाचा यशस्वी प्रयोग पुष्कळ बोलका आहे. जर्मनीतल्या शहरांत उपनगरी रेल्वे, जमिनीखालून जाणारी मेट्रो, ट्रॅम, उपनगरी बस अशी बहुरंगी सार्वजनिक

वाहतूकव्यवस्था आहे. ९ युरोंचं तिकीट घ्या नि यातल्या कुठल्याही वाहनांतून एक दिवस कितीही प्रवास करा, अशी एक योजना त्यांनी काही शहरांत जाहीर केली. हे फार स्वस्त, सोयीस्करही होतं. महागड्या गाड्या बाळगायची आणि रहदारीच्या किचकिचाटात अडकून पडायची सक्ती टाळून बरेच लोक सार्वजनिक वाहनांनी ये-जा करायला लागले. वेळ, पैसे, ताकद तर वाचलीच. पण प्रदूषणही कमी झालं. मग तो प्रयोग जर्मनीभर राबवण्यात आला. युरोपात सगळीकडेच त्याची पुनरावृत्ती झाली. लक्झेंबर्गमधल्या मंडळींनी त्यांची सार्वजनिक वाहतूक पूर्णतः चकटफू करून टाकली. फ्रान्समधल्या शहरांत खाजगी पार्किंगसाठी राखलेले भले-दांडगे भूखंड आणि इमारती काढून घेण्यात आल्या आणि त्या सार्वजनिक वापराला खुल्या केल्या. 'जिथले श्रीमंत लोक सार्वजनिक वाहतूक वापरतात, तो खरा प्रगत देश. जिथल्या गरिबांकडे मोटारी असतात, तो नाही!' हे कोलंबियाच्या राजधानीच्या - बोगोटाच्या महापौरांचं विधान आणि त्यांचे शहररचनेतले प्रयोगही असेच प्रसिद्ध आहेत.

हे सगळे प्रयोग सरकारी कल्पकपणातून, सार्वजनिक वाहतुकीत केलेल्या गुंतवणुकीतून, जबाबदार नागरी सहभागातून केले गेले - यशस्वीही झाले. त्या प्रयोगांना 'फुकटेपणा' वा 'रेवड्यावाटप' अशी लेबलं लावली गेली नाहीत. त्याचा फायदा त्या शहरांच्या नागरिकांना झाला. वेगासाठी त्यांनी धुराची-धुळीची किंमत मोजली नाही, रोजच्या प्रवासासाठी प्राणांची बाजी लावली नाही, वा स्वतःच्या खिशातून भरमसाठ पैसाही मोजला नाही. आपण या प्रयोगांतून प्रेरणा कधी घेणार आहोत? की आपल्याला मोठाल्या, सुळसुळीत, वेगवान, महागड्या, नि खाजगी गाड्यांचं वेड - आणि पर्यायानं त्यातून येणारे ट्रॅफिकचे, प्रदूषणाचे, गर्दीचे प्रश्न आवडायला लागले आहेत ?

meghana.bhuskute@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 12 मई, 2026

कल्पमेधा

जीवन का अर्थ ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान की खोज है, क्योंकि इससे उसके चिंतन को बल मिलता है।
- जेम्स जीन्स

संकट का सामना

पश्चिम एशिया में संघर्ष का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। ऊर्जा संकट और व्यापार में बाधाओं के कारण पैदा हुई चुनौतियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा (रुपए) के लगातार कमजोर होने से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। उधर, अमेरिका और ईरान के तल्ख तेवरों से शांति समझौते पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में अब मौजूदा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक उपायों को अमल में लाना जरूरी हो गया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को देश की जनता से पेट्रोलियम उत्पादों का संयमित तरीके से उपयोग करने, सोने की खरीदारी से परहेज करने, गैर जरूरी विदेश यात्रा से बचने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। सरकार का मानना है कि इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत दुनिया भर में जारी ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से सामना कर सकेगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिससे सरकारी कोष को मजबूत बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इसमें दोराय नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है, लेकिन देश की जरूरत मुख्य तौर पर अभी भी जीवाश्म ईंधन से पूरी की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि मौजूदा संकट के दौरान आयातित ऊर्जा संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से तेल की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे ऊर्जा का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में हुई बढ़ोतरी से देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है, जिस कारण आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि, अभी तक सरकार ने पेट्रोल-डीजल और घरेलू रसोई गैस के दामों को नियंत्रित करने के प्रयास किए हैं, लेकिन संकट गहराने से अब यह सब आसान नहीं होगा। इसके लिए वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा, ताकि प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री के आह्वान से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। यानी कच्चे तेल से जुड़ी महंगाई, पैकेजिंग सामग्री और ईंधन लागत में बढ़ोतरी के बीच साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और पेय उत्पाद जैसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। खबरों के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली देश की प्रमुख कंपनियां मुनाफे पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री के ये सुझाव कि कोरोना काल की तरह घर से काम करने समेत अन्य तरीकों पर फिर से अमल करना, खाद्य तेल की खपत कम करना और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना, यह सब मौजूदा संकट की गंभीरता को दर्शाता है। यह सही है कि संकट जब गंभीर हो, तो उससे निपटने के लिए सरकारी उपायों के साथ-साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे उसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। मगर इस सब के बीच यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इस तरह के उपायों का समाज के निचले और मध्य वर्ग की आजीविका पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

सुरक्षा पर सवाल

उत्तर प्रदेश सरकार यह दावा करती आई है कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन हत्या की वारदात का सिलसिला थम नहीं रहा है। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। चंदौली जिले में सोमवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला की गोली मार कर हत्या कर देने की घटना ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पता चलता है कि राज्य में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी हथियार लेकर सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं और कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। सवाल है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था के अनुपालन में वास्तव में सख्ती बरती जाती, तो क्या कोई अस्पताल में घुस कर महिला की हत्या कर सकता था? अपना इलाज करवाने के बहाने अस्पताल में घुसे हमलावर ने महिला पर गोली चलाने के बाद परिसर में हवा में भी गोलियां चलाईं और भागने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

उत्तर प्रदेश में हत्या की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, उससे लगता है कि सड़क से लेकर घर और अस्पताल में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। पिछले दिनों संभल जिले में कुछ लोग एक युवक को घर से खींच कर ले गए थे और बाद में सड़क पर उसकी हत्या कर दी गई थी। राज्य में इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। सवाल है कि सरकार के दावों के बरक्स आखिर अपराधियों के भीतर कानून का खौफ क्यों नही है? जाहिर है कि इसके पीछे पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही जिम्मेदार है। पुलिस तंत्र में तालमेल और त्वरित कार्रवाई का अभाव साफ नजर आता है। पुलिस के अपराध नियंत्रण के ढांचे में खामियों का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि सरकारी हो या निजी अस्पताल, वहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाने चाहिए। अगर कोई अपराधी हथियार लेकर अस्पताल के अंदर दाखिल होता है, तो यह वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही को उजागर करता है। ऐसे में राज्य सरकार को अपराध पर नियंत्रण के लिए सही मायने में ठोस कदम उठाने होंगे।

निगमित क्षेत्र की चाल और चुनौतियां

देश की अर्थव्यवस्था में निगमित क्षेत्र का अहम योगदान है। अब यह क्षेत्र तेजी से वृद्धि और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मगर इसकी राह में बाधाएं भी कम नहीं हैं।

अजय जोशी

देश की अर्थव्यवस्था में निगमित क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह क्षेत्र अब तेजी से वृद्धि और बदलाव के दौर में है। वर्तमान में यह संरचनात्मक परिवर्तनों, तकनीकी एकीकरण और स्थिरता की दिशा में विकास के चरण से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र सर्वाधिक अहम है। पिछले कुछ वर्षों से इसकी गति धीमी चल रही थी। मगर अब इसके पुनरुद्धार की दिशा में किए गए प्रयासों से विनिर्माण क्षेत्र में तेज वृद्धि देखी जा रही है। नवंबर 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र में 8.0 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की ओर से समय-समय पर जारी आंकड़ों के अनुसार, यह क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में इसमें 7.72 फीसद और दूसरी तिमाही में 9.13 फीसद वृद्धि दर्ज की गई है। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 17 फीसद रहा है। ताजा संशोधित आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण की वृद्धि दर वर्ष 2025-26 में 11.5 फीसद रहने का अनुमान है। भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 17 फीसद से बढ़ा कर 25 फीसद करना है।

निगमित क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन का दौर भी तेजी से चल रहा है। बैंकिंग, खुदरा व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा और सामग्री प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा (एआइ) को तेजी से अपनाया जा रहा है। निगमित क्षेत्र में ब्राडबैंड और इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़ रहे हैं। नवंबर 2025 तक ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या एक सौ करोड़ के पार चली गई, जो एक दशक पहले के 13.15 करोड़ से सात गुना अधिक है। देश के 99.9 फीसद जिलों में 5जी की सुविधा है और 5.18 लाख से अधिक बेस स्टेशन कार्यरत हैं। वहीं यूपीआइ लेन-देन भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है। देश में डेटा की लागत वर्ष 2014 के 269 रुपए प्रति गीगाबाइट से घट कर वर्ष 2025-26 में 8-10 रुपए प्रति गीगाबाइट रह गई है। डेटा सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम- 2025 में लागू हुए, जिसमें बच्चों के डेटा और गोपनीयता के संबंध में सख्त प्रावधान किए गए हैं।

अब कारपोरेट क्षेत्र में केवल मुनाफे के बजाय पर्यावरणीय और सामाजिक शासन के मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे हरित ऊर्जा और सतत विकास के क्रियाकलापों में निवेश बढ़ा है। निगमित संस्थाओं में पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बने सीएसआर कोष से इसके लिए व्यय लगातार बढ़ रहा है। कंपनियां पर्यावरणीय पहलों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण आदि पर अधिक खर्च कर रही हैं। सीएसआर के तहत प्रमुख कार्यों में भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रमुखता से प्रयास किए गए हैं। अब कंपनियां केवल परियोजना-आधारित व्यय के बजाय, स्थायी विकास के लक्ष्यों को अपनी मूल व्यावसायिक

रणनीतियों में शामिल कर रही हैं। कंपनियां पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को अपना रही हैं, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। कई संस्थाएं 18 राज्यों में 2,250 गांवों और कस्बों में पांच लाख से अधिक परिवारों को जोड़ते हुए अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों

> **भारत के निगमित क्षेत्र में इस समय कई तरह की आर्थिक, ढांचागत और नियामक चुनौतियां हैं। इससे विकास और उत्पादकता प्रभावित होती है। विशेष रूप से लघु और मध्य स्तर की कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करने, नई तकनीक अपनाने या उत्पाद शृंखला में विविधता लाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी से जूझ रही हैं। खराब परिवहन प्रणाली, अपर्याप्त भंडारण और बिजली की कमी, ये सभी उत्पादन लागत को बढ़ाते हैं। जटिल नियामक ढांचा, भ्रष्टाचार और नियमों में बार-बार बदलाव के कारण व्यावसायिक वातावरण में अनिश्चितता बनी रहती है।**

के माध्यम से सतत विकास में योगदान दे रही हैं। इनका प्रमुख जोर पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर है।

भारतीय निगमित जगत ने वित्तीय मजबूती के लिए ऋण में भारी कटौती की है, जो वर्ष 2010 के दशक के 67 फीसद से घट कर 2024 में 48 फीसद पर आ गया है। इससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। एनएसओ द्वारा वार्षिक निगमित सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण की शुरुआत के साथ, निगमित प्रशासन और डेटा पारदर्शिता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा और रेलवे जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को उदार बना कर सौ फीसद तक की अनुमति दे दी गई है। जुलाई 2025 तक विनिर्माण विकास में 5.4 फीसद की वृद्धि देखी गई। 2025 में अप्रैल-अगस्त के दौरान उत्पाद निर्यात 2.52 फीसद से बढ़ कर 184.13 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। देश में आटोमोबाइल उत्पादन 1991-92 के बीस लाख से बढ़ कर 2023-24 में दो करोड़ 80 लाख इकाइयां हो गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन 7.12 फीसद से बढ़ कर 370 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नई इकाइयों को मंजूरी देकर वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। इन नवीन पहलुओं के परिणामस्वरूप, भारतीय निगमित क्षेत्र न केवल घरेलू मांग को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक मूल्य शृंखला में भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है।

इन सभी के बीच देश के निगमित क्षेत्र में इस समय कई तरह की आर्थिक, ढांचागत और नियामक चुनौतियां हैं। इससे विकास और उत्पादकता प्रभावित होती है। विशेष रूप से लघु और मध्य आकार की कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करने, नई तकनीक अपनाने या उत्पाद शृंखला में विविधता लाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी से जूझ रही हैं। भारत में लाजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13-14 फीसद है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। खराब परिवहन प्रणाली, अपर्याप्त भंडारण और बिजली की कमी, ये सभी उत्पादन लागत को बढ़ाते हैं। जटिल नियामक ढांचा और नीतिगत अनिश्चितता, भ्रष्टाचार और नियमों में बार-बार बदलाव निवेश को हतोत्साहित करते हैं। अनुसंधान और विकास में कम निवेश के कारण भारतीय उद्योग नवाचार और उद्यमिता के मामले में पीछे हैं। सख्त श्रम कानूनों के कारण भी निजी क्षेत्र को कार्य बल प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

विपणन और तकनीक की पुरानी कार्यप्रणालियों के उपयोग, विशेष रूप से लघु उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को कम करता है। जीडीपी के मुकाबले निजी ऋण का उच्च अनुपात भी आर्थिक चिंता का विषय है। भारत के निगमित क्षेत्र को विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, नौकरशाही और वित्तीय मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। निगमित क्षेत्र के इन आयामों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से पुराने श्रम कानून और व्यवसाय शुरू करने तथा उनको चलाने में अत्यधिक दस्तावेजीकरण निवेश को हतोत्साहित करते हैं। एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली को मजबूत करना तथा श्रम कानूनों का और सरलीकरण करना जरूरी है। खराब परिवहन से उत्पादन और वितरण लागत बढ़ जाती है। गति शक्ति पहल के तहत बहु-परिवहन प्रणालियों और समर्पित माल गलियारों में निवेश तेज करना तथा सामग्री प्रबंधन लागत को कम करने के प्रयास जरूरी है।

आभासी बनाम वास्तविक

अनिल त्रिवेदी

आभासी दुनिया न तो प्राकृतिक है, न ही वास्तविक है। मगर वास्तविक या प्राकृतिक दुनिया पर आभासी जगत का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। वास्तविक दुनिया में रहते हुए भी हम जीवन की मूल प्रकृति या वास्तविकता से लगातार धीरे-धीरे ही सही, पर दूर होते जा रहे हैं और आभासी गतिविधियों को निरंतर जाने-अनजाने अपनाने ही नहीं, प्राण प्रण से मानने भी लगे हैं। आभासी जगत ने हमारे देखने-सुनने और प्रतिक्रिया करने के तौर-तरीकों को बहुत ही गहरे तौर पर बदल दिया है। हममें से कई लोगों की समझ तो यह भी बनने लगी है कि आभासी दुनिया के बिना जीवन जीना अब संभव नहीं रहा है।

इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिक दुनिया आभासी जगत की दीवानी होती जा रही है। जिस तेजी से आभासी दुनिया ने हमारी आंखों और कानों को बैठे-बैठे अतिव्यस्त से लेकर इतना अस्त-व्यस्त कर दिया है कि हम हर दिन वास्तविक जीवन की निरंतर चलने वाली प्राकृतिक गतिविधियों और आपाधापी से हर क्षण दूर होते जा रहे हैं। वास्तविकता से परे जीवन को ले जाने में वैसे देखा जाए, तो प्रकृति को कोई दिक्कत नहीं है और प्रकृति अपने अंश मनुष्य को आभासी दुनिया में धंसने या विलीन हो जाने से रोकती भी नहीं है। प्रकृति को मनुष्य के वास्तविक जीवन से छलांग लगा कर आभासी दुनिया में रच-बस जाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी महसूस नहीं हो सकती। जो कुछ भी परेशानी या द्वंद्व उठ खड़ा होता है, वह प्राकृतिक मनुष्य के मन और जीवन में होता है। आभासी दुनिया पूरी तरह से आभासी है। उसमें जीवन की रोजमर्रा की मशक्कत या सुख-दुख भी नहीं आते-जाते। आभासी दुनिया एकदम स्थितप्रज्ञ की तरह ही है।

दुनिया मेरे आगे

> **इसमें दोराय नहीं कि आभासी दुनिया जड़ और अचेतन वस्तुओं पर कोई असर नहीं करती, पर चेतन मन और जीवन के मूल स्वरूप को वास्तविकता से परे धकेल देती है। जो वास्तव में है ही नहीं, उसका आदी बनने में हम सक्रिय हैं। इससे आभासी और वास्तविक का भेद करने की क्षमता खत्म हो रही है।**

आभासी दुनिया जन्म और मृत्यु से परे तो है, ही साथ ही युद्ध और शांति से भी कोसों दूर है। आभासी दुनिया जड़ और अचेतन वस्तुओं पर कोई असर नहीं करती है, पर चेतन मन और जीवन के मूल स्वरूप को पूरी तरह से वास्तविक जीवन से परे धकेल देती है। एक आभासी दुनिया, जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है, उसका अत्यधिक आदी बनने में हम सतत सक्रिय हैं। प्राकृतिक जीवन से जुड़ी मूल चेतना को आभासी गतिशीलता में बदलकर वास्तविक चेतना या प्राकृतिक जीवन को आभासी जड़ता में बदल डालती है। इसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि प्राकृतिक या वास्तविक दुनिया का मनुष्य अपने आप आभासी दुनिया में इतना अधिक आत्ममुग्ध हो जाता है कि उसके अंदर आभासी और वास्तविक का भेद करने की क्षमता ही लुप्त होने लगती है। पर यह सब कुछ होते हुए भी प्राकृतिक या वास्तविक दुनिया में मौजूद मनुष्येतर प्राणियों के मन-मस्तिष्क और जीवनक्रम में आभासी दुनिया का शायद अब तक कोई असर नहीं हुआ है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इस तरह एक बात तो यह तय है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्तियों का मनमाने तरीके से यांत्रिक विस्तार करके आभासी दुनिया में लिप्त रहकर और अपने जीवन की वास्तविकता को नजरअंदाज करने की राह चल पड़ा है। मनुष्य के अलावा बाकी सारे जीव अपने जीवन के प्राकृतिक रूप-स्वरूप में बने हुए हैं।

मनुष्य को अपने जीवन में जो ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण का विस्तार प्राकृतिक रूप से मिला था, वह आभासी दुनिया के आदी मनुष्य के लिए अब एक छोटे-से परदे में सिमट गया है। ऐसी दुनिया में जीने वाले मनुष्य के लिए परदा ही जीवन है और जीवन ही परदा है। अंतहीन या शून्य अंतरिक्ष से लेकर महासागर की गहराई- सब कुछ छोटे से परदे में समा गई है। आज आभासी दुनिया का समूचा सफर हाथ की दो-चार अंगुलियों की गतिविधियों में सीमित हो गया है। इसी से आभासी दुनिया ने समूचे मानव समाज को अब अपने चंगुल में समेट लिया है।

वास्तविक दुनिया में घूमने, जानने, समझने, देखने, लिखने, बोलने और सुनने के लिए जो अलग-अलग तरह के इंतजाम और धन एवं साधनों की जरूरत होती थी, उसे अब कहीं भी बैठे-बैठे या चलते-फिरते भी मनुष्य स्क्रीन पर अपनी अंगुली के स्पर्श से ही सब कुछ करते रहने का साधन पा गया है। दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी करना, देखना, भेजना या मंगाना हो, तो यह अब केवल आभासी दुनिया के मनुष्य के मन की कल्पना नहीं रही, बल्कि आभासी जगत का साकार सत्य बन गया है। यही वह बिंदु है कि निरक्षर से लेकर प्रकांड विद्वान और अरबपति से लेकर कंगाल तक, किसी भी देश के राष्ट्रपति से लेकर आम जनता तक, सब कोई दुनिया भर के किसी भी कोने में रहते हुए अपनी अंगुलियों के स्पर्श और स्क्रीन के माध्यम से आभासी संसार को अपने जीवन में आसानी से उतार सकता है।

भले ही प्राकृतिक रूप से मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा हो, पर आभासी दुनिया सब कुछ करते रहने का वास्तविक अनुभव देने के बजाय करते रहने का आभास तो भरपूर दे ही रही है। इस दुनिया में सत्य से साक्षात्कार भले ही नहीं हो पा रहा है, मगर स्वप्न के सत्य होने का आभासी अनुभव हम सबको बिना किसी भेदभाव और बिना रोक-टोक के तो हो ही रहा है। वर्तमान समय का यह परिदृश्य आज की आभासी दुनिया का वास्तविक सत्य बन गया है!

महंगाई का बोझ

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का असली तापमान शेयर बाजार नहीं, बल्कि रसोई तय करती है। यदि वहां आग तेज हो जाए, तो बेचैनी हर घर तक पहुंचती है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी केवल होटल, ढाबों और रेस्तरां की समस्या नहीं है, बल्कि यह सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। जब वाणिज्यिक गैस महंगी होती है, तो उसका असर अंततः उस व्यक्ति पर पड़ता है, जो सुबह चाय की दुकान पर नाश्ता करता है और दोपहर में बाहर भोजन करता है। रेस्तरां संचालक खाने के दाम बढ़ाने की आशंका जता चुके हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि व्यापार करने वाला बढ़ी हुई लागत को लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा। इसका सबसे अधिक असर मध्यवर्ग और श्रमिक वर्ग पर पड़ेगा, जो सीमित और एक निश्चित आय में जीवन चलाता है। दूसरी ओर छोटे होटल, ठेले और दुकानदारों की कमाई भी प्रभावित होगी, क्योंकि लोग महंगाई से बचने के लिए अपने खर्च घटाने लगेंगे। यानी गैस महंगी होने से एक तरफ व्यापारी दबाव में आएगा, दूसरी तरफ ग्राहक परेशान होगा।

- मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

सुरक्षा की चिंता

'आतंक का साया' (संपादकीय 7 मई) पढ़ा। पंजाब के जलंधर और अमृतसर में हाल में हुए धमाकों को केवल सैन्य दृष्टि से देखने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के संबंध में समझना अधिक आवश्यक है। ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जांच की दिशा को भटका सकते हैं और समाज में भी भय और अविश्वास पैदा करते हैं। आतंकवाद किसी दल, विचारधारा या क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा होता है। पंजाब ने 1980 और 1990 के दशक में उग्रवाद और अलगाववाद का भयावह दौर देखा है। उस समय कई निर्दोष लोगों, सुरक्षा कर्मियों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी जान गंवाई है। लंबे संघर्ष और जनता के सहयोग से राज्य ने फिर से शांति और विकास की राह पकड़ी है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस चुनौती से निपटने के गंभीर प्रयास करने होंगे।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

नकारात्मकता का असर

यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की छवि हिंसा और द्वेष के कारण सबसे ज्यादा खराब है। चुनाव नतीजे के बाद हिंसा में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की पिछले दिनों हत्या कर दी गई। स्वाधीनता आंदोलन और उससे पूर्व सामाजिक-धार्मिक सुधार का प्रेरणास्रोत पश्चिम बंगाल ही रहा है। बंगाल की प्रगतिशीलता और आधुनिकता की चर्चा देश भर में होती है। मगर जैसे ही राजनीति से संबंधित बयानबाजी की बात आती है, उसमें कटुता दिखने लगती है। इसमें सभी दलों के नेताओं में होड़ मच जाती है। इससे यहां विद्रूप राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई है, जिसकी धारा रिसते हुए आम जन तक पहुंच चुकी है। इसलिए जरूरी है कि नेता अपने बयानों में कटुता के बजाय विनम्रता और उदारता को महत्त्व दें, तभी नकारात्मकता यह दौर खत्म हो सकेगा।

- मुकेश कुमार मनन, पटना

आंकड़ों का उपयोग

इन दिनों जनगणना को लोग साधारण आंकड़ों के संग्रह के रूप में देख रहे हैं, जबकि यही आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधनों के संतुलित वितरण की दिशा तय करते हैं। जब यह प्रक्रिया समय पर और सटीक नहीं होती, तो योजनाएं अनुमान पर आधारित रह जाती हैं और इससे असमानता बढ़ती है। आज समाज का ढांचा तेजी से बदल रहा है। शहरीकरण, प्रवासन और असंगठित क्षेत्र का विस्तार जनसंख्या के स्वरूप को जटिल बना रहा है। फिर भी इन वर्गों का समुचित आकलन अक्सर अधूरा रह जाता है। प्रवासी श्रमिकों की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट आंकड़ा न होना इस कमी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह केवल आंकड़ों की समस्या नहीं, बल्कि नीति निर्माण की गंभीर चुनौती भी है। जनगणना के आंकड़ों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, फिरोजाबाद

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

साधना

शिमला : दोरजे ड्रेक मठ में धार्मिक आयोजन के दौरान बौद्ध भिक्षु नवांग ताशी। ताशी को धर्माचार्य ताकलुंग रिनपोछे का अवतार माना जाता है।

बोल

आपको बोलने, बहस करने या किसी भी बात पर चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा। 850 सदस्यों वाला लोकसभा कक्ष 'चाइनीज पीपुल्स कंसल्टेटिव कांफ्रेंस' का देसी संस्करण बन जाएगा।

– शशि थरूर, कांग्रेस नेता

बोल

मैंने ईरान के तथाकथित 'प्रतिनिधियों' का जवाब पढ़ा। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया – यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। वे 50 वर्षों से अमेरिका के साथ खेल कर रहे हैं। अब वे ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे।

– डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

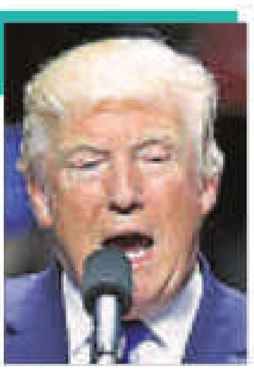

सम-सामयिक

परमाणु हथियारों की होड़ : बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कमजोर होते नियम

जनसत्ता संवाद

दुनिया में परमाणु हथियार कम होने के बजाय और आधुनिक व खतरनाक बनते जा रहे हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कमजोर होते नियमों के बीच खतरा है कि दुनिया फिर अस्थिर परमाणु दौर में जा सकती है।

आज दुनिया में लगभग 12,000 परमाणु युद्धाग्र (वारहेड्स) मौजूद हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा सक्रिय है और चिंताजनक संख्या उच्च सतर्कता स्तर पर रखी गई है। संख्यात्मक रूप से धीरे-धीरे कमी दिखने के बावजूद, इसके पीछे गहरा संरचनात्मक बदलाव छिपा है-परमाणु हथियारों का गुणात्मक महत्त्व फिर बढ़ रहा है।

इस बदलाव की खास बात आधुनिकीकरण है। सभी नौ परमाणु देश शस्त्रागार उन्नत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका-रूस आपूर्ति प्रणाली, युद्धाग्र और नियंत्रण के ढांचे में बड़े सुधार कर रहे हैं। चीन का तेजी से विस्तार विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जो उसकी रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं और पारंपरिक न्यूनतम दृष्टिकोण से बढ़ती असहजता को दर्शाता है। वहीं अन्य परमाणु शक्तियां भी धीरे-धीरे अपनी क्षमता और सामर्थ्य दोनों बढ़ा रही हैं, जिससे परमाणु प्रतिस्पर्धा अब केवल महाशक्तियों तक सीमित नहीं रह गई है।

इसके साथ ही उभरती तकनीकों का परमाणु रणनीति में समावेश स्थिति को और जटिल बना रहा है। हाइपरसोनिक आपूर्ति प्रणाली, परमाणु कमांड और नियंत्रण में साइबर कमजोरियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका निर्णय लेने के समय को कम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक प्रतिरोधक स्थिरता कमजोर पड़ रही है। अब परमाणु क्षेत्र अलग-थलग नहीं रहा; यह पारंपरिक, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं के साथ गहराई से जुड़ गया है, जिससे अनजाने में संघर्ष बढ़ने का जोखिम बढ़ रहा है।

रूस परमाणु संधि से बाहर निकल गया। साथ ही, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और व्यापक परमाणु अप्रसार संधि ढांचे पर बढ़ते दबाव से मौजूदा व्यवस्था की नाजुकता स्पष्ट हुई है। क्षेत्रीय स्तर पर, उत्तर कोरिया बिना किसी खास रोक-टोक के अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है, जबकि पश्चिम एशिया में ईरान महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया में परमाणु प्रसार की शृंखला (प्रोलिफरेशन कैस्केड) की संभावना अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई है। इसके अलावा, उभरते भू-राजनीतिक गठबंधनों ने संवेदनशील तकनीकों के प्रसार को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के प्रसार की गति तेज हो सकती है।

प्रमुख और क्षेत्रीय शक्तियों की परमाणु नीतियों में एक सूक्ष्म लेकिन महत्त्वपूर्ण बदलाव भी उतना ही अहम है। अब परमाणु हथियारों को केवल अंतिम विकल्प के रूप में अलग-थलग नहीं देखा जा रहा, बल्कि इन्हें जबरदस्ती की व्यापक कूटनीति के हिस्से के रूप में शामिल किया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक सटीक हमले, साइबर आपरेशन और अंतरिक्ष-आधारित क्षमताएं भी शामिल हैं। यह एक बढ़ते विश्वास को दर्शाता है कि परमाणु संकेत (न्यूक्लियर सिग्नलिंग) को संतुलित तरीके से अन्य साधनों के साथ मिलाकर प्रतिद्वंद्वी के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है, बिना पूर्ण परमाणु युद्ध की सीमा को पार किए।

यह सैद्धांतिक बदलाव खासकर तथाकथित 'टैक्टिकल' या कम-शक्ति (लो-यील्ड) वाले परमाणु हथियारों पर नए सिरे से जोर में दिखाई देता है। रूस जैसे देश गैर-रणनीतिक परमाणु प्रणालियों पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं।

बहुध्रुवीय दौर

शीत युद्ध बाद की परमाणु व्यवस्था कमजोर हो रही है और दुनिया बहुध्रुवीय, प्रतिस्पर्धी व अविश्वासपूर्ण दौर में प्रवेश कर रही है, जहां स्थिरता कठिन है। यह परखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वैश्विक समुदाय परमाणु अव्यवस्था को रोक या नियंत्रित कर सकता है। चुनौती केवल पुराने ढांचों को पुनर्जीवित करने की नहीं है।

शोध

आठ राज्यों में जलस्तर गिरा, तीन नदी घाटियां संकट में

जनसत्ता संवाद

केंद्रीय जल आयोग देश के 166 जलाशयों और 20 नदी घाटियों की निगरानी कर रहा है। आयोग की 30 अप्रैल की रिपोर्ट ने अहम संकट के संकेत दिए हैं। 166 जलाशयों में पानी का भंडारण 40 फीसद से नीचे पहुंच चुका है, वहीं नदी घाटियों में भी जल स्तर लगातार कम हो रहा है। असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में जलाशयों का स्तर पिछले साल से कम हो गया है।

देश में जल भंडारण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। जहां एक ओर 166 जलाशयों में पानी का भंडारण 40 फीसद से नीचे पहुंच चुका है, वहीं नदी घाटियों में भी जल स्तर लगातार कम हो रहा है। असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में जलाशयों का स्तर पिछले साल से कम हो गया है। 30 अप्रैल 2026 को केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी साप्ताहिक बुलेटिन में इस आशय के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं।

देश के 166 जलाशयों में से 20 जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े हैं, जिनकी कुल संग्रह क्षमता 183.565 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित कुल क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 71.20 फीद है। 30 अप्रैल के बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रह 71.082 बीसीएम है, जो उनकी कुल क्षमता का 38.72 फीसद है। नौ अप्रैल को यह 44.71 फीसद था। हालांकि इसकी तुलना सामान्य के स्तर या पिछले साल से की जाए तो अभी स्थिति बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 62.296 बीसीएम था, जबकि सामान्य संग्रह 56.176 बीसीएम था। सामान्य भंडारण का अर्थ पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण से है।

पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में हालात बहुत खराब हैं। असम में जलाशयों में सामान्य से लगभग 43 फीसद की कमी दर्ज की गई है, जो सबसे खराब स्थिति है। त्रिपुरा के जलाशयों में करीब 42 फीसद और पश्चिम बंगाल में लगभग 58 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है।

(फाइल फोटो)

इन राज्यों में कई जलाशय 40 फीसद से नीचे की श्रेणी में हैं।

दक्षिण भारत में कुल भंडारण सामान्य से बेहतर बताया गया है, लेकिन कुछ प्रमुख राज्यों में गिरावट चिंता बढ़ा रही है। कर्नाटक में सामान्य से लगभग 14 फीसद कम जल भंडारण हैं। केरल में हल्की गिरावट है, लेकिन जल स्तर लगातार कम हो रहा है। तमिलनाडु के जलाशयों में करीब 22 फीसद कमी दर्ज की गई है, जो कावेरी बेसिन पर दबाव का संकेत है। सबसे अहम बात यह है कि दक्षिण भारत में 36 जलाशय 40 फीसद से नीचे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के जलाशयों में पिछले साल के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पश्चिम भारत के गोवा में केवल एक जलाशय है, लेकिन यहां 12 फीसद से अधिक कमी दर्ज की गई है।

देश में ऐसे नौ प्रमुख जलाशय हैं, जहां पानी सामान्य स्तर के 50 फीसद से भी कम रह गया है। इनमें असम का खांडोंग (21.16 फीसद), झारखंड का चंदन डैम (0.00 फीसद), कर्नाटक का तट्टिहल्ला (24.63 फीसद), केरल का पेरियार (29.21 फीसद), तमिलनाडु के अलियार (48.89 फीसद), करायर (49.89 फीसद) और वैगई (15.17 फीसद), तेलंगाना का प्रियदर्शिनी जूराला (46.56 फीसद) तथा पश्चिम बंगाल का कांगसबाती (28.54 फीसद) शामिल हैं। इन जलाशयों की स्थिति खास तौर पर चिंता बढ़ाती है क्योंकि इनमें से कई ऐसे राज्यों में स्थित हैं जहां जल भंडारण पहले से ही पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया है। कुल 166 जलाशयों में से 22 जलाशय ऐसे हैं, जहां पानी का स्तर सामान्य के 80 फीसद या उससे कम है।

विश्व परिक्रमा

जर्मनी : अमेरिकी सैन्य बल में कटौती, साझा हितों पर जोर

जनसत्ता संवाद

जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की उस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका इस यूरोपीय देश से अपने लगभग 5,000 सैनिक वापस बुलाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की संख्या में कटौती की उम्मीद पहले से ही थी। उन्होंने यूरोप में अमेरिकी तैनाती के पारस्परिक लाभ पर जोर दिया।

रक्षा मंत्री पिस्टोरियस ने कहा कि यूरोप ने अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के भीतर, जिसमें जर्मनी एक अहम सदस्य है, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत को समझा है और वह इस दिशा में काम भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय महाद्वीप में अपनी सेना की तैनाती से अमेरिका को भी फायदा होता है। पिस्टोरियस ने कहा, 'यूरोप में, और विशेष रूप से जर्मनी में, अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी हमारे और अमेरिका के हित में है।' पिस्टोरियस ने इस कदम को पहले से संभावित बताया, जो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जर्मनी से सैनिकों की संख्या में कटौती करने संबंधी हालिया बयान की ओर इशारा है।

फिर भी, अगले छह से 12 महीनों में योजनाबद्ध वापसी, जर्मनी और अमेरिका के संबंधों में एक नई गिरावट का संकेत है। ट्रंप ने ईरान युद्ध में शामिल होने की नाटो सहयोगियों की अनिच्छा पर अपनी नाराजगी जाहिर की और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर जैसे नेताओं पर तीखा हमला बोला। मर्ज ने पिछले हफ्ते ईरान युद्ध की आलोचना करते हुए कहा था कि ईरानी नेतृत्व द्वारा अमेरिका को अपमानित किया जा रहा है।

जानें-समझें

पश्चिम एशिया संघर्ष

खाद्य आपूर्ति के लिए अहम वैश्विक गलियारे

जनसत्ता संवाद

पश्चिम एशिया का संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय सुरक्षा संकट नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक खाद्य और कृषि आपूर्ति शृंखलाओं के लिए बड़ी परीक्षा बन चुका है। कभी सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए चर्चित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आइमेक) और ग्रेटर मेकांग जैसे गलियारे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद अहम बन गए हैं। बढ़ते युद्ध और आपूर्ति संकट के बीच ये गलियारे दुनिया को सुरक्षित खाद्य आपूर्ति का नया रास्ता दे सकते हैं।

नाकेबंदी से अस्थिरता

वर्ष 2026 में इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष जैसे भू-राजनैतिक व्यवधान अब वैश्विक खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं पर काफी असर डाल रहे हैं। दरअसल, एक ही व्यापारिक मार्ग-होर्मुज पर अत्यधिक निर्भरता के कारण संरचनात्मक कमजोरियां सामने आई हैं। होर्मुज से दुनिया का लगभग 38 फीसद कच्चा तेल, 13 फीसद रसायन और उर्वरक एवं 2.4 फीसद अनाज की ढुलाई होती है। इस मार्ग के अस्थिर होने से इसका असर सिर्फ ऊर्जा बाजारों तक सीमित नहीं रहा है। प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ने से नाइट्रोजन आधारित उर्वरक महंगे हो गए हैं। गरीब देशों में उनकी उपलब्धता कम हुई है। खाड़ी देशों पर एशिया की उर्वरक निर्भरता के कारण पूरे क्षेत्र का कृषि उत्पादन खतरे में आ गया है।

भारत की स्थिति

भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया और डाय-अमोनियम फास्फेट आयातक है। वह पहले ही इंडोनेशिया, बेलारूस, रूस और चीन जैसे देशों की ओर अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। उर्वरक कीमतों में बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत ने 2025 से पोषक-आधारित छूट में 11.6 फीसद की वृद्धि की घोषणा की है और अन्य उर्वरकों के लिए भी अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे-जैसे उर्वरक और ईंधन की लागत बढ़ रही है, लागत-प्रेरित खाद्य महंगाई का खतरा बढ़ रहा है। खाद्य उत्पादन पर दबाव बढ़ रहा है। विश्व बैंक के मुताबिक, मार्च 2026 में खाद्य महंगाई में वृद्धि दर सभी वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक है।

(फाइल फोटो)

जैसे-जैसे उर्वरक और ईंधन की लागत बढ़ रही है, लागत-प्रेरित खाद्य महंगाई का खतरा बढ़ता जा रहा है। मार्च 2026 के विश्व बैंक के अनुमान बताते हैं कि खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति की वृद्धि दर सभी वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक है। – ***कौशिक बसु, विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री***

खाद्य पहुंच, वहनीयता और आपूर्ति स्थिरता की रक्षा के लिए नियम-आधारित व्यवस्था पर आधारित विशेष सुरक्षा उपाय स्थापित किए जाने चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का भी कहना है कि खाद्य व्यापार एक नैतिक दायित्व है। – ***आशिमा गोयल, आरबीआइ मौद्रिक नीति कमेटी की पूर्व सदस्य***

ग्रेटर मेकांग का उदाहरण

ग्रेटर मेकांग उपक्षेत्र के गलियारे विकल्प का अहम उदाहरण बनकर उभरे हैं। यहां निवेश के साथ वार्षिक आर्थिक वृद्धि में छह से आठ फीसद तक बढ़ोतरी और अत्यधिक गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। दक्षिण-पूर्व एशिया के कई उप-क्षेत्रीय समूह पहले ही इसे अपना रहे हैं और इस माडल को दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तक विस्तार देने की तैयारी है। आर्थिक गलियारे केवल अवसंरचना विकास पर निर्भर नहीं करते। अवसंरचना के पीछे मौजूद संस्थागत ढांचा-जैसे साझा मानक, विवाद समाधान तंत्र, निवेश ढांचे, सीमा शुल्क समन्वय और परस्पर-संगत डेटा प्रणालियां ही तय करेंगे कि ये गलियारे सफल होंगे या नहीं। अगर संस्थागत समर्थन मजबूत हों, तो आर्थिक गलियारे ऐसे लचीले व्यापारिक मार्ग बन सकते हैं जो खाद्य प्रणालियों को भू-राजनैतिक झटकों से बचाने, लेन-देन लागत घटाने और अधिक सुरक्षित व विविधीकृत कृषि बाजार तैयार करने में सक्षम होंगे।

खाद्य आपूर्ति का हाल

होर्मुज संकट ने विभिन्न देशों के कृषि निर्यात प्रवाह को भी बाधित कर दिया है। बढ़ती माल ढुलाई लागत के कारण भारत के लगभग चार लाख टन बासमती चावल बंदरगाहों पर अटक गए हैं, जबकि लगभग 200 कंटेनर भारतीय निर्यात बंदरगाहों और रास्तों में फंसे हुए हैं। हालात नहीं सुधरते तो वैश्विक खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं पर दबाव और गहरा सकता है, जैसा कि अन्य भू-राजनैतिक झटकों के दौरान भी देखा गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के शुरुआती चरणों में कृषि वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि और भारी अस्थिरता देखी गई थी। इसी तरह, लाल सागर में हूती हमले और स्वेज नहर के आसपास रुकावटों ने खाद्य वस्तु बाजारों को उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अस्थिर कर दिया है।

विकल्पों की तलाश

नए व्यापारिक रास्ते बनाना जरूरी है। जैसे, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा। वर्ष 2023 में घोषित यह गलियारा भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ग्रीस के माध्यम से यूरोप से जोड़ेगा, जिससे समुद्री गलियारों पर निर्भरता कम होगी। आसियान अब आर्थिक गलियारों को गहरे क्षेत्रीय एकीकरण के आधार के रूप में देख रहा है। कंबोडिया में, दक्षिणी आर्थिक गलियारे और दक्षिणी तटीय गलियारे के साथ चावल, मक्का, कसावा और आम की फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए गलियारा-आधारित हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। लाओस में विकास प्रयास चावल और जैविक सब्जियों पर केंद्रित हैं, जिनमें पूर्व-पश्चिम आर्थिक गलियारा के आसपास उगाई जाने वाली फसलें भी शामिल हैं।

व्यक्तित्व

कर्मबीर : कनाडा की जहाज कंपनी में पहले पगड़ी व दाढ़ीधारी सिख

जनसत्ता संवाद

गुरदासपुर जिले के कस्बा धारीवाल के गांव कंग के रहने वाले कर्मबीर सिंह कंग पहले ऐसे मरीन इंजीनियर बन गए हैं, जो पगड़ी और दाढ़ीधारी हैं। इसके लिए उन्हें चार साल तक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उनकी इस उपलब्धि को समानता और मानवाधिकारों के क्षेत्र में बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

कनाडा में सिख कर्मचारियों को लंबे समय से कार्यस्थलों पर अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विशेष रूप से दाढ़ी और पगड़ी को लेकर कई नियम ऐसे थे, जो सिखों के लिए बाधा बनते थे। कर्मबीर सिंह कंग के मामले में 'वर्ल्ड सिख आर्गेनाइजेशन' और 'बीसी फेरीज एंड मरीन वर्कर्स यूनियन' के बीच सहमति बनने के बाद भेदभावपूर्ण नियमों को हटाने का रास्ता साफ हुआ। इसके परिणामस्वरूप कर्मबीर सिंह को बीसी फेरीज में पूरी दाढ़ी के साथ 'मरीन इंजीनियर' के रूप में नियुक्ति मिली। कर्मबीर के बाद गुरप्रीत सिंह बाजवा के लिए भी रास्ता साफ हो गया। वे इस संस्था में पहले दस्तारधारी सिख डेक अधिकारी और कप्तान बने हैं। यह उपलब्धि सिख समुदाय के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे वे अपनी आस्था से समझौता किए बिना पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगे। कर्मबीर ट्रांसपोर्ट कनाडा द्वारा प्रमाणित द्वितीय श्रेणी के मरीन इंजीनियर (श्रेणी 2 सीओसी मोटर) हैं, जो बीसी फेरीज में भर्ती के अंतिम चरण तक बार-बार पहुंचे, लेकिन कंपनी की पहले की दाढ़ी-मूंछ साफ रखने की नीति के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। यह नीति सुरक्षा भूमिकाओं के लिए स्व-निहित श्वास उपकरण (एससीबीए) की आवश्यकता से जुड़ी थी। कंग ने एक बयान में कहा, 'मेरे पास आवश्यक योग्यताएं थीं और मैं लगातार भर्ती के अंतिम चरण तक पहुंचता रहा, लेकिन हर बार मुझे दाढ़ी-मूंछ साफ रखने के लिए कहा गया। मेरे धर्म के कारण, यह मेरे लिए संभव नहीं था।'

यह नीतिगत बदलाव बीसी फेरीज द्वारा किए गए व्यापक जोखिम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप हुआ। मूल्यांकन में पाया गया कि डेक आफिसर, चीफ इंजीनियर और अधिकांश फर्स्ट इंजीनियर पदों सहित कई अहम पदों के लिए तत्काल एससीबी (स्क्वायर्ड स्किन बाथ) की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, जिन पदों के लिए सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक नहीं था, उनके लिए दाढ़ी न रखने की अनिवार्यता को हटा दिया गया। इसके साथ ही संगठन ने जुलाई 2024 में अपनी वर्दी नीति को भी अद्यतन किया और पगड़ी को औपचारिक मान्यता दी।

जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), पठानकोट के 2012 बैच के पूर्व छात्र कंग ने बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस (बीआइटीएस), पिलानी से मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने भारत और हांगकांग में प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद कनाडाई प्रमाणपत्रों के लिए भी पढ़ाई की है। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में रहने वाले कंग अपने मूल से जुड़े हुए हैं।